ISSN-0971-8397

विशेषांक

योजना

अगस्त 2023 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 30

समग्र आरोग्यता के लिए एकीकृत दृष्टिकोण
डॉ मनसुख मंडाविया

आज़ादी का अमृत महोत्सव
जी किशन रेड्डी

देश को एकजुट रखने में भारतीय खेलों की भूमिका
अनुराग सिंह ठाकुर

प्रकाशन विभाग

परीक्षा तैयारी

के लिए

हमारा संग्रह

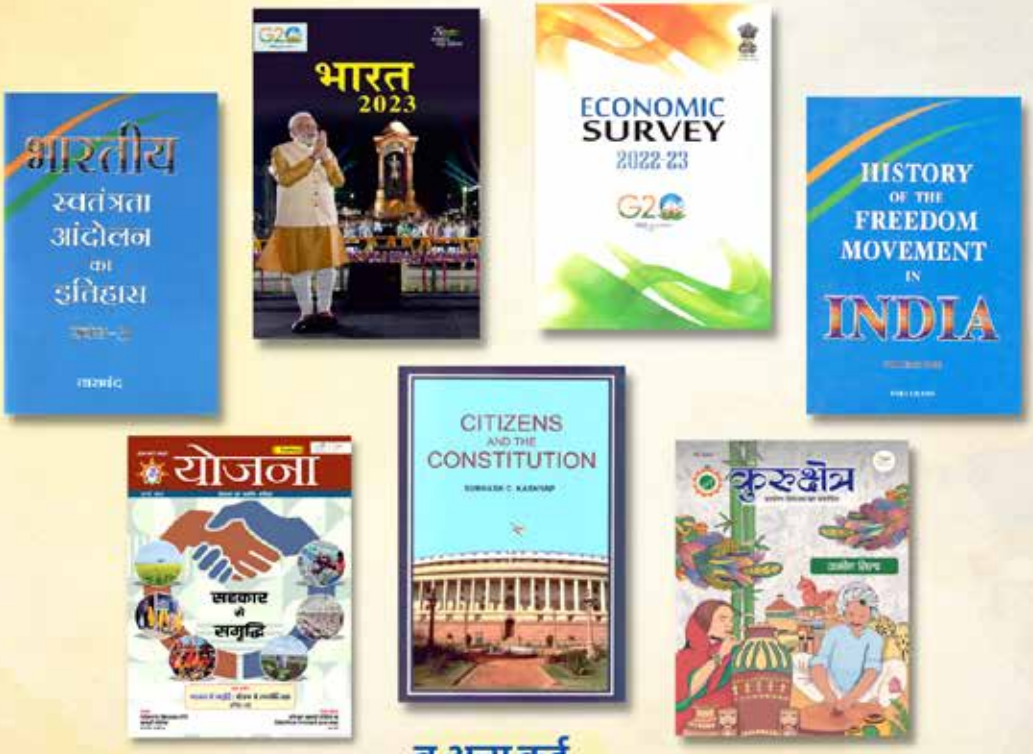

व अन्य कई ...

रोज़गार संबंधी जानकारी और महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर गहन विश्लेषण के लिए हर सप्ताह पढ़ें रोज़गार समाचार

सब्सक्राइब करें : www.employmentnews.gov.in

खरीदने के लिए : www.publicationsdivision.nic.in

संपर्क करें:

पुस्तकों के लिए : businesswng@gmail.com 01124365609

पत्रिकाओं के लिए: pdjucir@gmail.com 01124367453

सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

ISSN-0971-8397

विशेषांक

योजना

वर्ष : 67
अंक : 08

अगस्त 2023
श्रावण-भाद्रपद, शक संवत् 1945

मूल्य : ₹ 30
पृष्ठ : 64

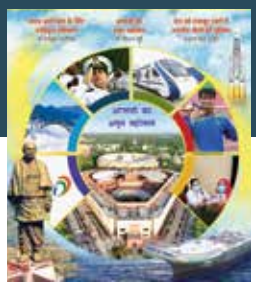

संपादक
डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : डीकेसी हृदयनाथ
आवरण : नीरज रिडलान

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के व्यक्तिगत हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के सम्बन्ध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-62** पर देखें।

योजना की सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -
pdjucir@gmail.com
या संपर्क करें-
दूरभाष : 011-24367453
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर
प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–
अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड,
नयी दिल्ली-110003

इस अंक में...

विहंगावलोकन

6 **आज़ादी का अमृत महोत्सव**
जी किशन रेड्डी

27 **संवहनीय मैनुफैक्चरिंग की ओर छलांग**
अंशुमान खन्ना

33 **सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल**
अनिल सहस्रबुद्धे

37 अटल इनोवेशन मिशन
एक समग्र नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण
प्रमित दाश

45 **भारत की जी-20 अध्यक्षता**
प्रो हर्ष वी पंत

विशेष आलेख

10 **समग्र आरोग्यता के लिए एकीकृत दृष्टिकोण**
डॉ मनसुख मंडाविया

16 **देश को एकजुट रखने में भारतीय खेलों की भूमिका**
अनुराग सिंह ठाकुर

फ़ोकस

23 **भारतीय अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और आगे का रास्ता**
वी अनंत नागेश्वरन

स्थायी स्तंभ

C-3 पुस्तक चर्चा
काला पानी

49 भारत में कृषि
वैश्विक शक्ति बनने की ओर
डॉ जगदीप सक्सेना

53 मीठी क्रांति
शहद उत्पादन में धूम
डॉ शैलेश कुमार मिश्र
डॉ धीरज कुमार तिवारी

57 **भारतीय सिनेमा का सफ़र**
अमिताव नाग

आगामी अंक : संविधान, सुशासन एवं सुधार

प्रकाशन विभाग के देशभर में स्थित विक्रय केन्द्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 61

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

Mc Graw Hill

Presenting the consistent best seller and the most celebrated title on the subject

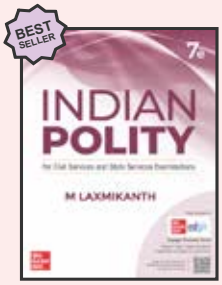

ISBN: 9789355325341

₹1045/-

Indian Polity,7e by M LAXMIKANTH

Salient Features

- 92 chapters covering the entire Indian political and constitution spectrum
- 12 new chapters including some important ones like World Constitutions, Landmark Judgements and their Impact, Delimitation Commission, Bar Council of India, National Consumer Disputes Redressal Commission etc.
- 8 relevant appendices
- Revised chapters as per the latest pattern and syllabus
- This edition includes last 10 years questions of preliminary and main exam
- With this edition, learners will get free access to 7 conceptual videos, additional reading material and PYQ's on McGraw Hill Edge

With free access to

Mc Graw Hill edge™

Engage · Evaluate · Excel

Practice Tests | Expert Sessions
Preparation Strategy & much more!

Scan to explore McGraw Hill Edge

UP PSC (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा) एवं अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु

उत्तर प्रदेश-समग्र अध्ययन,3e

लेखक: राकेश सारस्वत

ISBN: 9789355324962

₹420/-

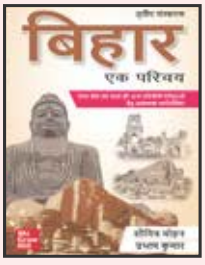

बिहार पीसीएस परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण किताब

बिहार एक परिचय,3e

लेखक: सौमित्र मोहन, प्रभाष कुमार

ISBN: 9789355325600

₹440(T)/-

Toll Free Number: 18001035875 | support.india@mheducation.com | www.mheducation.co.in

YH-2417/2023

जीवन का उत्सव

भारत त्योहारों का देश है। यहां लोग पूरे वर्ष अपनी आस्था, विभिन्न कैलेंडर तिथियों, देवी-देवताओं, महान संतों, लोगों तथा दिनों और क्षेत्रीय रीति-रिवाजों पर आधारित तथा जीवन के सभी पहलुओं के नाम पर असंख्य उत्सव मनाते हैं। ये त्योहार विविधता को दर्शाते हैं और देश भर के लोगों को एक साथ लाते हैं। भारत में बच्चे के जन्म से पहले ही उत्सव और अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं। सचमुच, भारत एक ऐसा देश है जहां उत्सव जीवन जीने का एक तरीका है।

इन उत्सवों और भारत की उत्सव भावना को राष्ट्रवादी उत्साह प्रदान करते हुए और सभी भारतीयों को एक सामान्य त्योहार के लिए एक साथ लाते हुए, आज़ादी का अमृत महोत्सव (अकाम) का भव्य उत्सव, 15 अगस्त 2023 को आज़ादी की 75 वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह की उलटी गिनती के साथ 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ। स्वतंत्रता संग्राम, अद्वितीय विचारों, उपलब्धियों, कार्यों और संकल्प पर केंद्रित पांच स्तंभों पर आधारित यह महोत्सव 'जनभागीदारी' की भावना से मनाया गया है। इसने देश की इन 75 वर्षों की उपलब्धियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया और अगले 25 वर्षों के लिए संकल्प की रूपरेखा भी दी।

आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें हर घर तिरंगा, वंदे भारतम् नृत्य उत्सव और कलांजलि जैसे कई बड़े कार्यक्रम शामिल हैं। अमृत महोत्सव का उद्देश्य भारत और दुनिया भर में सहयोगात्मक अभियानों और आउटरीच के माध्यम से जन आंदोलन को और बढ़ावा देना है। ये अभियान 'पंच प्राण' के अनुरूप नौ महत्वपूर्ण विषयों की तर्ज पर हैं। ये विषय हैं- महिलाओं, बच्चों तथा जनजातियों का सशक्तीकरण, जल, सांस्कृतिक गौरव, पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफ), स्वास्थ्य तथा आरोग्यता, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत और एकता।

इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय महत्व के कई स्मारक और संरचनाएं राष्ट्र को समर्पित की गईं, जिनमें प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से आज़ादी के बाद भारत की कहानी दर्शाने वाला 'प्रधानमंत्री संग्रहालय', नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, इंडिया गेट के निकट 'कर्तव्य पथ' और अत्याधुनिक नया संसद भवन शामिल हैं।

प्रत्येक क्षेत्र ने इस उत्सव में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे सहभागी शासन के माध्यम से यह वास्तव में जन-अभियान बन गया। उदाहरण के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाने के लिए शुरू किए गए 'महिला सम्मान बचत पत्र' हों या मोटा अनाज तथा योग के माध्यम से सभी के लिए स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा देना हो या महान स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों का संकलन हो, या फिर जिले की अनूठी विरासतों के डिजिटल जिला भंडार, भारत के लोगों को समर्पित कई अन्य पहल की गई हैं। इन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में इतना आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उन्हें 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना से प्रेरित 'कर्तव्य काल' और कर्म युग के दृष्टिकोण को सक्षम करने की शक्ति और क्षमता भी दी है।

योजना का यह अंक अतीत में किए गए उन महान कार्यों के लिए सम्मान है जिन्होंने उसकी नींव रखी है जहां हम आज खड़े हैं। विभिन्न क्षेत्रों और पहलों ने भारत की विकास गाथा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये हाल में घोषित कर्तव्य काल - कर्तव्य की अवधि, दृढ़ निश्चय और संकल्प में आगे की राह पर भी प्रकाश डालता है।

आइए, हम दया, करुणा, अच्छाई और समर्पण के अपने छोटे-छोटे तरीकों से इस उद्देश्य में योगदान देने का प्रयास करें। ये उत्सव हमारे जीवन का हिस्सा बना रहें। आइए, हम भारत को आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर स्थान बनाने का संकल्प लें। ❑

आज़ादी का अमृत महोत्सव

जी किशन रेड्डी
केन्द्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। ईमेल: office-hcm@gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार का एक प्रमुख प्रयास है। आज़ादी का अमृत महोत्सव विश्व के सबसे बड़े उत्सवी प्रयासों में से एक है। इसमें व्यापक, उत्साही भागीदारी देखी गई है। इसने समूचे समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है।

'अकाम' के अन्तर्गत मार्च 2021 से लेकर अब तक केन्द्र और राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के विभागों और निजी संगठनों ने मिलकर एक लाख 70 हज़ार से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर देश के सुदूर सीमावर्ती गांवों तक आयोजित किए गए। आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐसा जन आंदोलन बन गया जिसमें पूरे देश ने एकजुट होकर अद्भुत भारत का उत्सव मनाया।

आज़ादी का अमृत महोत्सव (अकाम) के पांच स्तंभ

आज़ादी का अमृत महोत्सव में पांच स्तंभों – स्वतंत्रता संग्राम, विचार@75, कार्य@75, संकल्प@75 और उपलब्धियां@75 के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रत्येक स्तंभ में भारत की गाथा को संजोया गया और देश के क्रमिक विकास के बारे में बताया गया। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे इतिहास के पड़ावों तथा हमारे गुमनाम नायकों का स्मरण है, विचार@75 के तहत राष्ट्र को आकार देने वाले विचारों और आदर्शों का

उल्लेख है, कार्य@75 में नए भारत की प्रतिबद्धताओं को साकार करने की दिशा में अथक प्रयास उजागर किए जा रहे हैं, संकल्प@75 में निश्चित लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति हमारे संकल्पों की पुष्टि है तथा उपलब्धियां@75 के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति और क्रमिक विकास का प्रदर्शन है।

प्रयास और अभियान

'अकाम' आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक विशेष प्रयास किए गए हैं – 'मेरा गांव मेरी धरोहर' के अंतर्गत देश के 6 लाख 50 हज़ार गांवों का सांस्कृतिक मानचित्र बनाने की योजना है जिसमें प्रत्येक गांव की भौगोलिक, जनसांख्यिकी और सृजनात्मक विशेषताओं का परिचय होगा। गुमनाम नायक पहल के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के कम परिचित, अज्ञात और भूले-बिसरे वीरों का स्मरण करते हुए अकाम की वेबसाइट पर 8 हज़ार 858 गाथाएं प्रकाशित की गयी हैं। डिजिटल जिला भंडार (डीडीआर), जिला इकाई स्तर पर भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों, घटनाओं और स्थानों का पता लगा कर उनका विवरण संग्रहित करने का प्रयास है। इसके अंतर्गत 11 हज़ार 935 गाथाओं को अकाम की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। इस सब की परिणति अकाम के संभवत: सबसे बड़े अभियान 'हर घर तिरंगा' में हुई और देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 23 करोड़ से अधिक

परिवारों ने इस अभियान में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय ध्वज अपने घरों में फहराया तथा 6 करोड़ से अधिक लोगों ने तिरंगे को ऑनलाइन प्रदर्शित किया।

अकाम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों का विहंगावलोकन

अकाम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में अलग-अलग स्तरों पर जन-भागीदारी देखी गई। 'रचनात्मकता में एकता' पहल भारत की गली-कूचों से विलक्षण प्रतिभा को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के लिए की गई। इसके तहत संस्कृति मंत्रालय को कुल 5 लाख 16 हज़ार 885 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। ग्रैंड फिनाले में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। कलांजलि में कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट पर खुले गगन के तले एम्फी थिएटर (रंगभूमि) में प्रत्येक सप्ताहांत में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को हज़ारों लोग देखने आते हैं। इन कार्यक्रमों में भारतीय विरासत की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताओं को उजागर किया जाता है। वितस्ता: कश्मीर की अविरल विरासत के इस उत्सव से राष्ट्र पर कश्मीरी संस्कृति के प्रभाव को उजागर होता है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में वितस्ता के तीन चरणों में सफल आयोजन से इन स्थानों और कश्मीर के बीच समानताएं उजागर हुई। अकाम के अंतर्गत एक और आयोजन-धारा, भारतीय ज्ञान व्यवस्था का सागर मन्थन है जिसमें औषधि, गणित, खगोल विद्या, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में भारत के प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान को बताया गया है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव में पांच स्तंभों - स्वतंत्रता संग्राम, विचार@75, कार्य@75, संकल्प@75 और उपलब्धियां@75 के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रत्येक स्तंभ में भारत की गाथा को संजोया गया और देश के क्रमिक विकास के बारे में बताया गया।

अकाम के अंतर्गत अन्य आयोजनों में जनजातीय खेल महोत्सव, माधवपुर घेड़ उत्सव, स्वदेशी वैज्ञानिक शृंखला, भारत की सीमाएं, अमृत समागम, आध्यात्मिक गुरु सम्मेलन, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, कलिंग उत्सव, काशी तमिल संगमम् इत्यादि शामिल

हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनमानस में एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना का संचार किया गया है और उन्होंने मिलजुल कर यह महोत्सव मनाया।

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन से पिछली सहस्त्राब्दी में इस महान देश की नींव डालने वालों को सम्मानित करने के हमारे संकल्प की पुष्टि होती है। वीर बाल दिवस गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबज़ादों बाबा फतेह सिंह और ज़ोरावर सिंह के बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनकी परिणति कर्तव्य पथ पर उनकी कांस्य प्रतिमा की स्थापना के साथ हुई। इसी तरह श्री अरबिंदो घोष की 150वीं जयंती, अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती, राजा राम मोहन रॉय की 350वीं जयंती और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर देशभर में बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री, कई गणमान्य व्यक्तियों और आम लोगों ने भाग लिया।

अभियान 2.0

अकाम के दूसरे चरण में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वाधीनता दिवस पर अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित पंच प्राण से प्रेरित नौ नए विषयों की पहचान की गई है। इनमें महिलाएं और बच्चे, जनजातीय सशक्तीकरण, जल, पर्यावरण के लिए जीवनशैली (लाइफ), स्वास्थ्य और आरोग्य, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत, सांस्कृतिक गौरव और एकता शामिल है। ये अभियान मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों, गैर-सरकारी संगठनों तथा निजी संगठनों जैसे सभी संबंधित पक्षों के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। ये भविष्य के अभियानों का आधार बनेंगे तथा अमृत काल में भारत की वैभवशाली यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ❑

समग्र आरोग्यता के लिए एकीकृत दृष्टिकोण

डॉ मनसुख मंडाविया
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। ईमेल: india-hfm@gov.in

भारत में पारंपरिक चिकित्सा और एलोपैथी का एकीकरण समग्र आरोग्यता की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतीक है। यह सहक्रियात्मक दृष्टिकोण, दोनों पद्धतियों के संबंधित गुणों को जोड़ता है और रोगियों को व्यापक सेवाएं प्रदान करता है जो उनकी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों के माध्यम से सेवाओं की निरंतरता बनाये रखने के लिए तैयार की गई है। इन तीनों स्तरों के बीच एक महत्वपूर्ण कार्यात्मक संबंध है, और सभी का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए उनकी परस्पर निर्भरता अपरिहार्य है।

भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में 2014 के बाद से उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना ध्यान, विलासिता के रूप में स्वास्थ्य सेवा से हटाकर सभी के लिए सार्वभौमिक तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने पर केंद्रित किया है। वर्तमान सरकार, प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने और 'किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने और कतार में अंतिम व्यक्ति को सेवाएं प्रदान करने' के अंत्योदय के सिद्धांत का पालन करते हुए, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं लोगों के दरवाजे पर मुफ्त प्रदान करने पर जोर दे रही है।

पिछले दशक में, 'टोकन टू टोटल' दृष्टिकोण का पालन करते हुए, स्वास्थ्य क्षेत्र को समग्र रूप से मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने और स्वास्थ्य तथा आरोग्यता दोनों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। उनके

शब्दों में, ''आरोग्यता के लिए विश्व के लिए भी हमारा दृष्टिकोण वैसा ही है जैसा कि यह अपने देश के लिए है। दुनिया खासकर कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य और आरोग्यता को गंभीरता से ले रही है। भारत के पास इस संबंध में देने के लिए बहुत कुछ है। हमारा योग और आयुर्वेद विश्व को स्वस्थ बनाने में योगदान कर सकते हैं।''

किसी राष्ट्र का स्वास्थ्य उसके सभी आयु के लोगों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। राष्ट्र-निर्माण की दिशा में कोई भी प्रयास तभी सफल होता है जब जनता स्वस्थ होती है, जो बदले में स्वस्थ समाज और राष्ट्रीय उत्पादकता में योगदान करती है। देश में राजनीतिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और महामारी संबंधी परिवर्तनों का लोगों के स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। परिवर्तनों के साथ लगातार तालमेल बनाये रखने के लिए, नागरिकों के लिए कुशल, न्यायसंगत, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य नीतियां और मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं। इस संबंध में, राष्ट्र एक उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है जो उसके नागरिकों को उत्पादक जीवन जीने और स्वस्थ समाज बनाने में सक्षम बनाती है।

भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों के माध्यम से सेवाओं की निरंतरता बनाये रखने के लिए तैयार की गई है। देखभाल के तीनों स्तरों के बीच एक महत्वपूर्ण कार्यात्मक संबंध है, और सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए उनकी अंतर-निर्भरता अपरिहार्य है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), जिसे अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के रूप में जाना जाता है, शुरू में विशेष रूप से कमजोर समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य और संचारी रोगों और एक चयनात्मक प्राथमिक सेवा दृष्टिकोण के साथ चलाया गया था। लाभदायक होने के बावजूद, इसमें कमी यह थी कि यह आबादी की बदलती जरूरतों और गैर-संचारी रोगों के कारण मृत्यु दर तथा रुग्णता के बढ़ते बोझ को संबोधित नहीं कर सका।

आयुष्मान भारत

2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत पहल, जिसमें स्वास्थ्य तथा आरोग्यता केन्द्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) शामिल हैं, स्वास्थ्य सेवा चुनौतियों का समाधान करने और इन सेवाओं की लागत को कम करने में सहायक रही है। आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्यता केन्द्र, समुदाय को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य और आरोग्यता सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीबों और कमजोर लोगों को अस्पताल में भर्ती और रोगी सेवाएं मुफ्त प्रदान करती है। इन पहल ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सफलतापूर्वक लोगों के करीब ला दिया है।

व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं (सीपीएचसी) प्रदान करने और आरोग्यता गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्यता केन्द्र समुदाय के करीब संचालित किये गये। दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और आरोग्यता केन्द्र चालू करके समयबद्ध तरीके से इनका संचालन शुरू करने का इरादा था। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, राष्ट्र ने सफलतापूर्वक 1,59,859 आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और आरोग्यता केन्द्रों को समुदाय के करीब लाकर मुफ्त सेवाएं प्रदान कीं और महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इन केन्द्रों में शुरुआत के बाद से, 172.13 करोड़ लोगों ने सेवाएं ली हैं, जिनमें मधुमेह के लिए 35.67 करोड़, उच्च रक्तचाप के लिए 41.26 करोड़, ओरल कैंसर के लिए 24.46 करोड़,

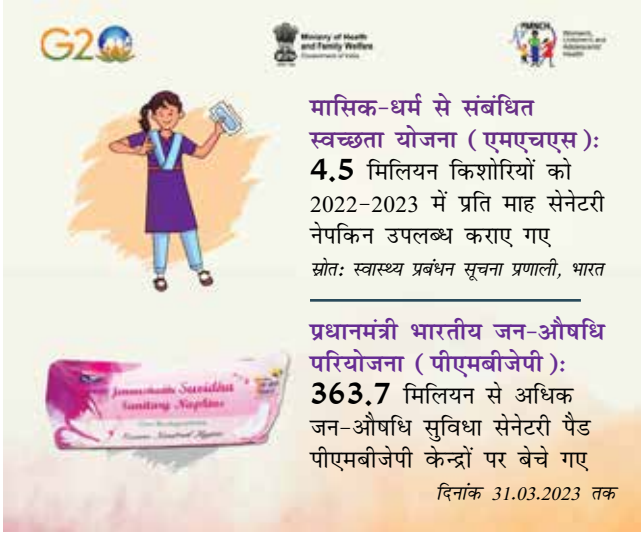

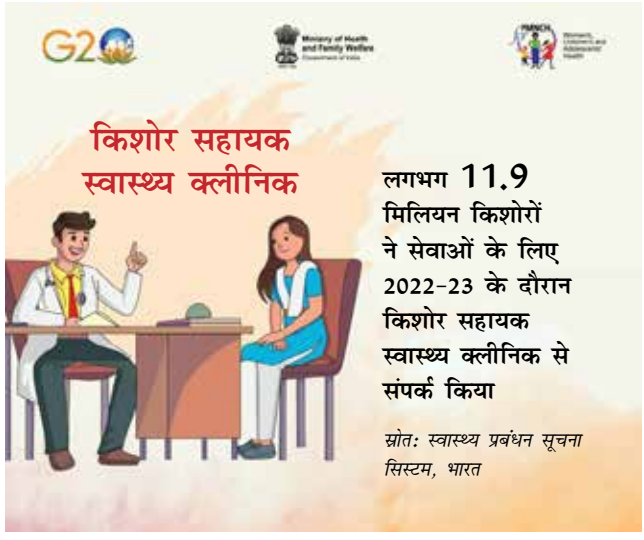

स्तन कैंसर के लिए 11.32 करोड़, ग्रीवा कैंसर के लिए 7.74 करोड़ से अधिक जांच की गई है। 2.08 करोड़ योग या आरोग्य गतिविधियां की गईं। आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और आरोग्यता केन्द्रों को अब समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं और आरोग्यता के लिए पहले पड़ाव के रूप में पहचाना जा रहा है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, 33 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में 40 प्रतिशत पात्र आबादी को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। 23 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाये गए हैं और उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान करने के लिए 28,368 से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। यह योजना अब काफी हद तक विकसित हो चुकी है और इसमें निदान के अलावा अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं और उपशामक सेवाओं सहित 1,949 प्रक्रियाओं की सेवाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होने के बाद से, 61,807 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की सेवाओं के साथ 5 करोड़ से अधिक रोगियों की भर्ती को सफलतापूर्वक अधिकृत किया है; इस प्रकार, गरीबों का वित्तीय बोझ कम हुआ और उनके जीवन की रक्षा की जा सकी।

भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों के माध्यम से सेवाओं की निरंतरता बनाये रखने के लिए तैयार की गई है। देखभाल के तीनों स्तरों के बीच एक महत्वपूर्ण कार्यात्मक संबंध है, और सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए उनकी अंतर-निर्भरता अपरिहार्य है।

डिजिटल परिवर्तन

देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को विकसित करने और इसमें सहयोग करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) शुरू किया गया। इसके तहत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विस्तार करते हुए 200 करोड़ रुपये से अधिक का महत्वपूर्ण निवेश किया गया। मिशन आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों (एबीएचए) के निर्माण के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में देश की भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। एबीएचए आईडी का उद्देश्य विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच एक विशिष्ट पहचान स्थापित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से लेकर बीमा योजनाओं तक के सभी स्वास्थ्य लाभों को आईडी से जोड़ना, देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं में पंजीकरण में सुगमता प्रदान करना और स्वास्थ्य डाटा साझा करने के लिए अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाना है। जून 2023 तक 40.22 करोड़ से अधिक एबीएचए आईडी बनाये गए हैं, और 27.48 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंक किए गए हैं। इससे पहले, मरीजों को विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी या निजी सेवा-प्रदाताओं के पास जाना पड़ता था। अब, ई-संजीवनी सेवाओं जैसी ई-स्वास्थ्य पहल 1.11 लाख से अधिक एबी-एचडब्ल्यूसी पर उपलब्ध है इसने सेवा-पहुंच के अंतर को कम कर दिया है और विशेषज्ञ सेवाओं को घर के करीब ला दिया है। ई-संजीवनी ने 9 करोड़ टेली-परामर्श प्रदान किए हैं, इनमें 57 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं और 12 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक हैं।

महामारी प्रतिक्रिया और तैयारी

कोविड-19 महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया ने

उसके वैश्विक नेतृत्व और लचीलेपन को प्रदर्शित किया। देश ने 2022 तक तेजी से अपनी परीक्षण क्षमता को 3388 प्रयोगशालाओं, 821 सरकारी और 1487 निजी आरटी-पीसीआर प्रयोगशालाओं, 1115 कार्टिज प्रयोगशालाओं और 53 जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाओं तक विस्तारित किया। आत्मनिर्भर भारत पहल ने नैदानिक बाजार में प्रतिस्पर्धा की सुविधा प्रदान की और डायग्नोस्टिक वस्तुओं की लागत कम की जो 2020 में 1727 रुपये से घट्कर 2021 में 72 रुपये पर आ गईं। कोविड केन्द्र, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन उत्पादन के लिए पीएसए प्लांट जैसे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को त्वरित उपलब्ध कराया गया।

महामारी से मिली सीख के आधार पर, देश ने सबसे बड़ी अखिल भारतीय बुनियादी ढांचा योजना - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन (पीएमएबीएचआईएम) के माध्यम से सेवाओं के स्तर पर एक समग्र स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए 'संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण को चुना। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन- बुनियादी ढांचे, निगरानी, निदान, प्रबंधन और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए सेवाओं के सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संस्थानों की क्षमताओं में तेजी लाने पर केंद्रित है। मिशन ने अब तक, 7808 भवन-रहित उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को सहायता प्रदान की है और 264 से अधिक शहरी स्वास्थ्य तथा आरोग्यता केन्द्रों (यूएचडब्ल्यूसी), 485 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), 216 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल), और 166 से अधिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) अस्पताल स्थापित किए हैं। विकेन्द्रीकरण की भूमिका पर जोर देते हुए, 15वें वित्त आयोग स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को 70,051 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए गए।

देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को विकसित करने और इसमें सहयोग करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) शुरू किया गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों (एबीएचए) के निर्माण के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में देश की भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है।

लाभों का दोहन करना, कमियों को दूर करना और तैयारियों के लिए नवाचारों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को शुरू करना, परिवर्तनशील और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। आयुष्मान भारत, एक गेम चेंजर के रूप में, सभी स्तरों पर नियमित और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी की सुरक्षा करते हुए, इष्टतम संकट प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों को सुदृढ़ करने के वास्ते एक बहुत जरूरी वर्धक के रूप में सामने आता है। इस प्रकार, जिलों तथा राज्यों को आत्मनिर्भर बनाकर देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाता है।

स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन (एचआरएच)

कुशल स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के महत्व को पहचानते हुए, सरकार ने चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 2014 के बाद से, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख कार्यनीतियों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में कुशल एचआरएच की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। देश में

वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा के लिए 1.07 लाख से अधिक स्नातक सीटें हैं। मेडिकल कॉलेजों में 67 प्रतिशत, स्नातक सीटों में 93 प्रतिशत और स्नातकोत्तर सीटों में 105 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एचआरएच, विशेषकर डॉक्टरों की उपलब्धता और पहुंच देश भर में भिन्न-भिन्न है, फिर भी कुल मिलाकर एचआरएच में वृद्धि हुई है। सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नर्सिंग संस्थानों को भी मान्यता दी है, और अब लगभग 1.25 लाख नर्सिंग स्नातक सालाना, स्वास्थ्य सेवा कार्यबल में प्रवेश कर रहे हैं। देश में नर्सिंग कार्यबल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2014 से स्थापित मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के सह-स्थान पर 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। इस कदम से हर साल लगभग 15,700 नर्सिंग स्नातक जुड़ेंगे।

टीकाकरण और रोग नियंत्रण:

सरकार ने हमेशा सेवा वितरण में सुधार लाने में गहरी रुचि ली है। उदाहरण के लिए, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम ने टीकाकरण को लोगों के सामाजिक आंदोलन में बदल दिया है। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से, नियमित टीकाकरण सेवाओं के माध्यम से कई अतिरिक्त टीके लगाए गए, और टीकाकरण कवरेज को 62 प्रतिशत (2015-16) से बढ़ाकर 76.4 प्रतिशत (2019-21) कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, संचारी रोगों के बोझ को कम करने के लगातार प्रयासों से 2014 और 2021 के बीच मलेरिया के मामलों में 85.3 प्रतिशत की कमी आई है, और जापानी एन्सेफलाइटिस के मामलों की संख्या 2014 की 1661 से घटकर 2021 में 787 हो गई है। नियमित टीकाकरण के लिए व्यापक संसाधनों और बुनियादी ढांचे ने इसे संभव बनाया है। देश में सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान दुनिया भर में अभूतपूर्व रूप से सफल रहा, जिसमें 9 महीनों में 100 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं, और अगले 9 महीनों में इसे दोगुना करके 200 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं। इसके अतिरिक्त, वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 100 से अधिक देशों और 2 संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं को 291.5 मिलियन से अधिक खुराक की आपूर्ति की गई। इससे भारत वैश्विक मंच पर एक उभरते हुए अग्रणी देश के रूप में चमका।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री की नागरिक-केंद्रित नीतियों को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में उपलब्ध मुफ्त टीबी उपचार के बारे में जागरुकता बढ़ाना है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में बदलाव को प्रदर्शित करते हुए, टीबी मामले संबंधी अधिसूचनाएं पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गई हैं। जन भागीदारी की भावना के अनुरूप, सरकार ने एक अनूठा मंच- निक्षय 2.0 पेश किया है, जो रोगी सहायता और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ाता है। इन सुधारों के लिए कॉर्पोरेट

सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अवसरों का भी लाभ उठाया जाता हैं और एक अग्रणी वैश्विक क्राउड फंडिंग मॉडल स्थापित किया गया है। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत की दिशा में काम कर रहे हैं।

मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्यता

भारत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य विकारों के उपचार में 70 से 92 प्रतिशत तक अंतर बताया गया। उपचार अंतर पर प्रकाश डाला। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य नेटवर्क की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सरकार ने जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की डिजिटल शाखा टेली-मानस की शुरुआत की। 42 स्थापित टेली-मानस सैल के साथ, इस पहल को 1.5 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हो चुकी हैं। गुमनाम सहायता प्रदान करने से व्यक्तियों के अपने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए सहयोग प्राप्त करने में मददगार बताया। इस तरह हम मिलजुल कर, कमियों को दूर कर रहे हैं और इससे संबंधित कलंक से बचने में भी मदद मिलेगा।

पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, जो रोकथाम, प्राकृतिक उपचार और मन-शरीर-आत्मा संतुलन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। आरोग्यता को बढ़ावा देने में पारंपरिक चिकित्सा की प्रभावशीलता को पहचानते हुए, सरकार ने इन पद्धतियों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकीकृत करने के लिए कदम उठाए हैं।

नियमित और आपातकालीन दोनों सेवाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की बढ़ी हुई क्षमता, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता का स्पष्ट परिणाम है। पिछले दशक में, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय में 74 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा में 167 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2013-14 के बाद से स्वास्थ्य पर अपनी जेब से खर्च में 16 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय गिरावट आई है। ये आंकड़े स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने और चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता वाले व्यक्तियों पर वित्तीय बोझ को कम करने के ठोस प्रयासों को प्रदर्शित करते हैं।

पारंपरिक औषधियों के लाभों को स्वीकार करना:

पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, जो रोकथाम, प्राकृतिक उपचार और मन-शरीर-आत्मा संतुलन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। आरोग्यता को बढ़ावा देने में पारंपरिक चिकित्सा की प्रभावशीलता को पहचानते हुए, सरकार ने इन पद्धतियों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकीकृत करने के लिए कदम उठाए हैं। ज्ञान और विशेषज्ञता के इस एकीकरण से मानकीकृत प्रोटोकॉल, साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों और सुरक्षित तथा प्रभावी पारंपरिक चिकित्सा फॉर्मूलेशन का विकास हुआ है।

भारत में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने में आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए यह एक एकीकृत दृष्टिकोण की सुविधा के लिए एलोपैथिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों और स्वास्थ्य सेवाओं के पेशेवरों के साथ सहयोग करता है। देश भर में आयुष आरोग्य केन्द्रों की स्थापना ने पारंपरिक चिकित्सा को व्यापक आबादी के लिए सुलभ बना दिया है, जो एलोपैथिक स्वास्थ्य सेवाओं की पूरक है।

भारत में पारंपरिक चिकित्सा और एलोपैथी का एकीकरण समग्र आरोग्यता की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतीक है। यह सहक्रियात्मक दृष्टिकोण दोनों प्रणालियों की संबंधित शक्तियों को जोड़ता है, रोगियों को व्यापक सेवाएं प्रदान करता है जो उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को संबोधित करता है।

भारत की जी20 की अध्यक्षता लोगों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पर केंद्रित है। लोगों की भागीदारी पर जोर देने वाले जनभागीदारी के मार्गदर्शक सिद्धांत ने पूरे देश में जबरदस्त उत्साह जगाया है। सेमिनार, सम्मेलन और त्योहारों जैसे विविध जी20-संबंधित आयोजनों को भारत की अध्यक्षता में, हितधारकों के रूप में लोगों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए सोच-समझकर डिजाइन किया गया है।

भारत की जी20 अध्यक्षता की भावना को इसके विषय- 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' में दर्शाया गया है, जो 'वसुधैव कुटुंबकम' के प्राचीन संस्कृत लोकाचार में समाहित है। इसके अनुरूप, समावेशिता को बढ़ावा देने और विकास तथा समृद्धि की यात्रा में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का मजबूत विश्वास है। हमारी अटूट प्रतिबद्धता प्रत्येक नागरिक के लिए किफायती, न्यायसंगत और सुरक्षित गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, जो 'सर्वेभवंतुसुखिनःसर्वेसंतुनिरामयाः' मंत्र द्वारा निर्देशित है। ❑

देश को एकजुट रखने में भारतीय खेलों की भूमिका

अनुराग सिंह ठाकुर

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री। ईमेलः minister.inb@gov.in

नए भारत के निर्माण में खेलों की भूमिका बहुमुखी होने के साथ अनूठी भी है। विगत कुछ वर्षों में खेलों का महत्व बढ़ने का कारण प्रधानमंत्री की असाधारण सोच है; उन्होंने 'खेलो इंडिया योजना', 'टार्गेट ओलंपिक पदक योजना', 'फिट इंडिया मूवमेंट' और कई अन्य योजनाओं को कार्यरूप देकर भारत में खेलों की भूमिका को एकदम नया रूप दे दिया है जिससे राष्ट्रीय एकता, महिला सशक्तीकरण, नागरिकों के स्वास्थ्य और फिटनेस, युवाओं में जीवन कौशल की भावना जगाने तथा राष्ट्रीय गर्व की दृढ़ भावना विकसित करने की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त करना संभव हो सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में खेलों के क्षेत्र में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार आया है। 2020 के टोक्यो ओलिंपिक खेलों में भारत ने एथलेटिक्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने के साथ कुल सात पदक प्राप्त करके अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हमने पैरालिंपिक्स और डेफलिंपिक्स में भी क्रमशः 19 और 17 पदक जीतकर अब तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया था। फिर, 72 वर्ष में पहली बार थॉमस कप भारत ने जीता और निकहत ज़रीन ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियन बनकर देश का गौरव बढ़ाया।

अभी हाल में युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों सात्विक और चिराग की जोड़ी ने 1000 इंडोनेशियाई सुपर सीरीज़ में जीत दर्ज करने वाली पहली भारतीय डबल्स टीम बनने का गौरव अर्जित किया और दो दिन के भीतर ही भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी मुकाबलों में भारत के लिए पहली बार कांस्य पदक जीता तथा जूनियर एशियाई कप हॉकी में लड़कों और लड़कियों की टीमों ने एक सप्ताह पहले ही स्वर्ण पदक जीता था–ये सभी उपलब्धियां खेल-जगत में भारत के बढ़ते वर्चस्व को दर्शाती हैं। और, जब भी दुनिया के किसी भी भाग में भारतीय एथलीट पदक जीतता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है।

पदक जीतना और पोडियम पर खड़े होने के साथ ही राष्ट्रगान का बजना समूचे देश को इस प्रकार एक सूत्र में पिरो देता है जैसा साधारणतया अन्य घटनाओं में कम ही होता है।

खेलों की असल खूबी उनसे तुरन्त मिलने वाले परिणाम या कहें सफलता में ही नहीं है, बल्कि इस बात में है कि इनमें समूची पीढ़ी की सोच में बदलाव लाने में है जिसके अंतर्गत युवा अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करके जीतने का लक्ष्य तय कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि 'खेलोगे तो खिलोगे।' असल में हार-जीत इतनी ज़रूरी नहीं है जितना युवाओं में खेलने की भावना विकसित करना है क्योंकि खेलों में जीवन के विभिन्न अध्याय इतनी बारीकी से जुड़े हुए हैं कि हमारी भावी पीढ़ी पूरी मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ राष्ट्रनिर्माण

में योगदान देने के लिए जुट जाती है और खेलों से मिलने वाली कभी हार न मानने की सीख को जीवन का अभिन्न अंग बनाकर आगे बढ़ती रहती है।

नए भारत के निर्माण में खेलों की भूमिका व्यापक और बहुआयामी होने के साथ ही अनूठी भी है। भारत में पिछले कुछ वर्षों से खेलों के बढ़ते महत्व के पीछे प्रधानमंत्री की असाधारण सोच है और खेलों में उनकी व्यक्तिगत रुचि से एथलीटों और खिलाड़ियों को अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली है तथा विभिन्न योजनाओं को कार्यरूप भी दिया गया है। इनमें 'खेलो इंडिया योजना', 'टार्गेट ओलिंपिक पोडियम योजना', 'फिट इंडिया मूवमेंट' और अन्य अनेक योजनाएं शामिल हैं जिनसे देश में खेलों की भूमिका में बड़ा बदलाव आया है और खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, महिला सशक्तीकरण, नागरिकों के स्वास्थ्य और फिटनेस, युवाओं में जीवन कौशल के विकास और राष्ट्रीय गर्व की गहरी भावना विकसित करने की प्रक्रियाओं में तेज़ी आई है।

खेलों में क्षेत्रीय विविधता का अंतराल मिट रहा है

देशभर से ग्राम स्तर की खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें विकसित करके आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 2016 में खेलो इंडिया योजना की रूपरेखा तैयार की थी और 2017 में इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया था। इस योजना से देशभर के एथलीटों को राष्ट्रीय मंच पर अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और आगे प्रशिक्षण के लिए उनका चयन भी किया जाता है। इस योजना के तहत 2500 से ज्यादा एथलीटों में से प्रत्येक को हर वर्ष 6.28 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। इन एथलीटों को आधुनिकतम खेल सुविधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है और छात्रवृत्ति के तहत ही उनके रहने, खाने, खेल उपकरण लेने और पढ़ाई-लिखाई का खर्च उठाया जाता है तथा प्रति माह 10,000 रुपये का नकद भत्ता भी दिया जाता है। इन सभी एथलीटों में एक बड़ी समानता यही है कि ये देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाएं हैं। परन्तु समानता बस इतनी ही है क्योंकि खेलो इंडिया योजना में एथलीट भौगोलिक दृष्टि से अलग-अलग स्थानों के होते हैं तथा इनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि अलग-अलग होती है और ये देश के विभिन्न भागों में स्थित किसी खेलो इंडिया अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

ये एथलीट खेलों का प्रशिक्षण लेने के साथ-साथ एक-दूसरे की संस्कृति भी जानते-समझते हैं और उनमें देश की सांस्कृतिक-भौगोलिक विविधता के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना विकसित होती है। खेलो इंडिया गेम्स में भी ठीक इसी प्रकार एथलीट, कोच (प्रशिक्षक) और अधिकारीगण देश के सभी राज्यों के होते हैं जो 10 दिन से भी ज्यादा समय एक साथ रहकर प्रशिक्षण लेते हैं और स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हैं। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा इन खेलों में स्पष्ट परिलक्षित होती है। ये खेल 2018 में शुरू किए गए थे और अभी तक

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आठ संस्करण हो चुके हैं जिनमें 59,833 प्रतिभागियों के बीच खेलों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ है ।

राष्ट्र निर्माण में सहायक बुनियादी खेल-सुविधाएं

खेलो इंडिया योजना के तहत देशभर में खेलों के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास 2014 के बाद से लगातार किए जा रहे हैं ताकि देश के सभी भागों के युवाओं को खेल के मैदान और प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध हो सकें। प्रत्येक ज़िले में 1000 खेलो इंडिया सेंटर (केआईसी) बनाने का अभियान देश में खेलों के इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में उल्लेखनीय पड़ाव साबित हुआ था। विभिन्न राज्यों के साथ केन्द्र सरकार की भागीदारी में 31 खेलो इंडिया उत्कृष्टता केन्द्र बनाने की योजना के तहत वरिष्ठ और विशिष्ट एथलीटों को विशेष खेल स्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

खेल जगत की इन मूलभूत सुविधाओं में 266 खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमी, 500 प्राइवेट (निजी) अकादमी और गोद लिए गए 27 स्कूलों के जुड़ जाने से काफी विस्तार हुआ है और इन अकादमियों में खेलो इंडिया एथलीट ट्रेनिंग लेते हैं। खेलों को कॅरियर बनाने वाले एथलीटों को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं जिससे देश में खेल संस्कृति का विकास सुनिश्चित हो तथा लगभग 17,500 खेल के मैदान तैयार किए गए हैं जहां अभिभावक अपने बच्चों के लिए अपने घरों के आसपास ही खेलने की जगह ढूंढ सकें।

खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की व्यापक तस्वीर सिर्फ एक आंकड़े से साफ हो जाएगी। 2010 से 2014 के बीच खेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सिर्फ 38 परियोजनाएं पूरी की गई थीं जबकि 2014 से 2023 की अवधि में खेलो इंडिया योजना के

तहत कुल 293 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें से 146 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इन बुनियादी सुविधाओं के बन जाने से एथलीटों और खेलों में रुचि रखने वाले लोगों को तो अपने सपने साकार करने में मदद मिली ही है, साथ ही इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में खासी वृद्धि हुई है और अनेकानेक लोगों को रोज़गार भी मिला है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में खेलों की भूमिका वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण रही है।

खेलों में माध्यम से समावेशिता का विकास

खेलों ने विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों और एथलीटों को एक ही जगह पर साथ लाने में अहम भूमिका निभाने के साथ ही आर्थिक और भौगोलिक रूप से बेहद पिछड़े इलाकों की महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने में भी महती योगदान किया है। महिला एथलीटों के लिए खेलो इंडिया महिला लीग आयोजित करने जैसे विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि महिलाओं को खेलों में भाग लेने की प्रेरणा मिले। पिछले वर्ष खेलो इंडिया महिला लीग शुरू होने के बाद से देशभर के 50 शहरों में आयोजित 27 से ज़्यादा खेल स्पर्धाओं में 1.25 लाख से अधिक महिलाएं भाग ले चुकी हैं। वास्तव में खेल जगत से जुड़ी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो दर्शाती हैं कि आर्थिक और सामाजिक बाधाओं से संघर्ष करके महिला एथलीट किस तरह खेलों में अपनी धाक जमाने

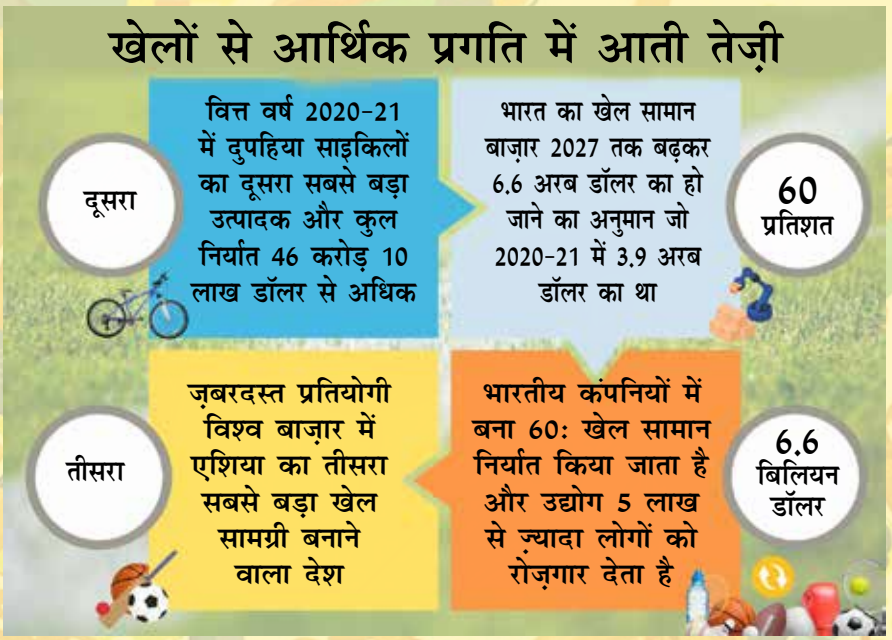

में सफल हुईं और वे मानती हैं कि खेलों ने उनका जीवन बदल दिया। विश्व बॉक्सिंग चैंपियन निकहत ज़रीन की कहानी तो कुछ ज्यादा ही आकर्षक है। उन्होंने कई बार बताया कि खेलों में उनके कॅरियर का समर्थन करने पर उनके पिता को अपनी पुत्री को बॉक्सिंग करने की अनुमति देने पर किस प्रकार अपने आसपास के समाज के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। पर, निकहत अपनी बात की पक्की थीं। आज वे बताती हैं कि उन्हें सफलता मिलने के बाद उनके समुदाय की कई अन्य लड़कियों ने भी बॉक्सिंग का कैरियर अपनाकर अपना जीवन बदला है।

भारत के हृदय से जन्मी इन सच्ची कहानियों से पता चलता है कि नए भारत के निर्माण में खेलों ने बहुत अहम भूमिका अदा की है और आज का नया भारत विश्वास से भरा है जो किसी बाधा के कारण रुकने वाला नहीं है। मुझे यह बताने में बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि टोक्यो ओलिंपिक खेलों में 50 प्रतिशत के आसपास महिला एथलीटों ने भाग लिया और उन्होंने लगभग 50 प्रतिशत पदक भी देश के लिए जीते, इन एथलीटों में मीराबाई चानु, लवलीना बोर्गोहेन और पीवी सिंधु शामिल हैं।

खेलों में आने वाली महिलाओं का समुदाय बढ़ता जा रहा है और यही समुदाय समाज के विभिन्न वर्गों का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा। महिलाओं को जोड़ने के साथ ही देश के सभी भागों से और खासकर जम्मू-कश्मीर तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों से युवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया को तेज़ करने में खेल सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। जम्मू-कश्मीर में खेलों का बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं जबकि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में खेल आयोजनों और स्पर्धाओं के लिए हर ज़िले को 10 लाख रुपये दिए गए हैं।

इन प्रोत्साहनों से इन क्षेत्रों में अपेक्षित बदलाव आया है। उदाहरण के लिए, जम्मू-कश्मीर में कभी जो बच्चे पत्थर फेंकने जैसे काम में धकेले जा रहे थे वही बच्चे आज अपने इलाके के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। जिन क्षेत्रों में उग्रवाद के डर से लोग रात के वक्त जाने से घबराते थे वे ही इलाके अब रात में फुटबॉल मैचों के मुख्य केन्द्र बन चुके हैं। ऐसा जादू खेल ही कर सकते हैं और कर भी रहे हैं।

दिव्यांग एथलीटों को खेलों से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जून, 2023 में 198 दिव्यांग एथलीटों के दल ने बर्लिन में आयोजित 2023 के विशेष ओलिंपिक ग्रीष्म खेलों में भाग लिया। सरकार ने इस भारतीय

बुनियादी खेल सुविधाएं-राष्ट्र निर्माण में सहायक

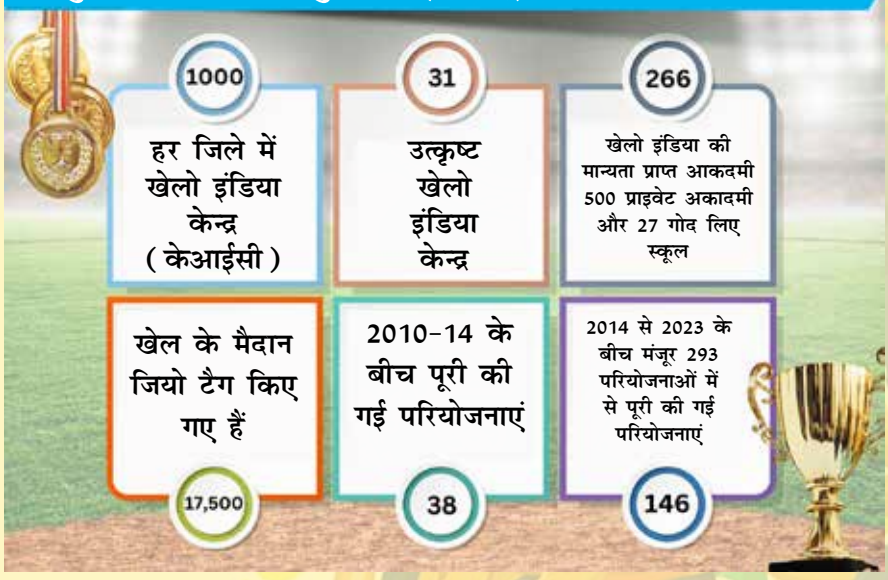

दल के खेलों में शामिल होने के लिए 7.7 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की और इन विश्व स्तरीय खेलों की तैयारी के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विशेष प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्था की थी। इन खेलों के लिए सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता अब तक की सबसे ज़्यादा थी और मुझे विश्वास है कि हमारे ये विशेष एथलीट सर्वाधिक पदक भी जीतकर लाएंगे।

खेलों से मिल रही फिट इंडिया की प्रेरणा

खेल एथलीटों के लिए तो कॅरियर हैं ही, खेल प्रेमियों के लिए भी जुनून से कम नहीं होते। फिर भी, खेल और फिटनेस हर नागरिक की जीवन शैली होनी चाहिए तभी तो वे देश के सर्वांगीण विकास में समुचित योगदान कर पाएंगे। इसी विचार को आधार बनाकर प्रधानमंत्री ने 2019 में फिट इंडिया अभियान की कल्पना की थी ताकि हर नागरिक फिटनेस को अपनी जीवन शैली या दिनचर्या का अंग बना ले और फिटनेस का मंत्र एथलीटों और विशेषज्ञों के लिए ही सीमित न रह जाए।

''फिटनेस की डोज़, आधा घंटा रोज़'' का उनका आह्वान समूचे देश में गूंजा और नागरिकों ने बढ़-चढ़कर मैराथन, साइकिलोथन, दौड़ और अन्य आयोजनों में पूरे वर्ष भर भाग लिया जिससे इसने जनआंदोलन का रूप ले लिया। जहां फिट इंडिया फ्रीडम रन के दो संस्करणों में देशभर के 7.08 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया वहीं स्कूली बच्चों के लिए फिटनेस और खेलों के बारे में आयोजित क्विज़ में 1.74 लाख विद्यार्थियों ने भाग लेने का पंजीकरण कराया जिससे सभी आयु-वर्गों के लोगों में फिटनेस के प्रति बढ़ते आकर्षण और रुचि का पता चलता है। फिट इंडिया इस दृष्टि से अनूठा है कि इससे विद्यार्थियों में फिटनेस और खेलों के महत्व के प्रति जागरुकता पैदा होती है और वे अपने साथियों (समवयस्कों), शिक्षकों और अभिभावकों तक भी इस संदेश को पहुंचाते हैं। विद्यार्थियों को और ज़्यादा प्रेरित करने के उद्देश्य से हर वर्ष फिट इंडिया स्कूल सप्ताह आयोजित किया जाता है और अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी फिटनेस पर आधारित विभिन्न गतिविधियों में भाग ले चुके हैं। स्कूली विद्यार्थियों से युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों तक सभी आयुवर्गों के लोगों के लिए फिट इंडिया अभियान में शामिल होने से स्पष्ट पता चलता है कि नए भारत को फिट इंडिया बनाने में सभी देशवासी पूरी लगन और संकल्प से जुटे हुए हैं।

खेलों से आर्थिक वृद्धि में तेज़ी

भारत इस समय विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह अभूतपूर्व प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आर्थिक प्रगति की इस कहानी में खेल सामग्री बनाने वाले उद्योग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वेस्ट इंडिया की फरवरी, 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अत्यंत स्पर्धात्मक विश्व बाज़ार में खेलों के सामान बनाने के क्षेत्र में भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर, भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित खेल सामग्री में से 60 प्रतिशत निर्यात होता है तथा यह उद्योग 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया कराता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के निर्यातों में व्यायाम के उपकरण, हवा वाली गेंदें, बाइसिकल, क्रिकेट का सामान, खेल पोशाक इत्यादि शामिल हैं और इनके सहारे ही भारत बड़ा और मज़बूत निर्यातक बन सका है। वह 200 देशों को खेल का सामान निर्यात करता है जिनमें चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022 में भारत दोपहिया साइकिलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था और उसके कुल निर्यात 46 करोड़ 10 लाख डॉलर से ज्यादा के हुए थे। फिर, खेल सामान निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना जैसे उपायों से भारत के खेल सामग्री निर्माण उद्योग का विस्तार ही होगा। आशा है कि 2027 तक भारत से खेल सामग्री के निर्यात बढ़कर 6.6 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे जबकि 2020-21 में ये निर्यात कुल 3.9 अरब डॉलर के थे। राष्ट्र निर्माण में खेलों की यही अहमियत है।

वास्तव में, पिछले 9 वर्ष में भारत के खेलों का बहुत विकास हुआ है। अब भारतीय एथलीट विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में अपना वर्चस्व बना चुके हैं और खेल जगत में भारत को अब बड़ी ताकत माना जाने लगा है। तभी तो अनेक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल संगठनों ने हाल के वर्षों में भारत को विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं की मेज़बानी के लिए चुना है। 44वें फिदे शतरंज ओलिंपियाड, 2022 में हुए अंडर-17 फीफा विश्वकप, आइबा विश्व बॉक्सिंग प्रतियोगिता और देश के अनेक शहरों में 2023 में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाज़ी विश्व कप भारत के रुतबे को दर्शाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ❑

PERFECTION IAS
PI
PERFECTION IAS
NEW BATCH FOR UPSC
Starting from
19 July 2023
ENGLISH MEDIUM
TIME: 04:00 PM - 08:00 PM
HINDI MEDIUM
TIME: 04:00 PM - 08:00 PM
NEW BATCH FOR BPSC
Starting from
5 July 2023
HINDI MEDIUM
TIME: 08:00 AM - 12:00 PM
NEW BATCH FOR BPSC
Starting from
12 July 2023
ENGLISH MEDIUM
TIME: 04:00 PM - 08:00 PM
1st floor1(B), Metro Tower, Gate No.8,
Karol Bagh Metro Station, Pusa Road, New Delhi
9031036712
www.perfectionias.com
perfectionias@gmail.com
YH-2405/2023

भारतीय अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और आगे का रास्ता

राष्ट्रों की प्रगति में उनके विकास-पथ को आकार देने में अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इसकी अर्थव्यवस्था की यात्रा उन परिवर्तनों, चुनौतियों और अवसरों को दर्शाती है जो भारत की पुष्ट, गतिशील और प्रगतिशील प्रकृति को परिभाषित करते हैं। समय के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, बाधाओं को पार किया है और स्वयं को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए अवसरों का लाभ उठाया है।

वी अनंत नागेश्वरन | भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार। ईमेल: cea@nic.in

भारत की आर्थिक यात्रा आज़ादी के बाद के शुरुआती वर्षों से प्रारंभ होती है, जब इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया था, जिसमें समाजवादी नीतियों को बाजार अर्थव्यवस्था के घटकों के साथ जोड़ा गया था। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना और आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण, औद्योगीकरण तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इन नीतियों ने हालांकि औद्योगिक विकास की नींव रखी, लेकिन इनसे नौकरशाही की अक्षमताएं, सीमित प्रतिस्पर्धा और अवरुद्ध नवाचार जैसे अनपेक्षित परिणाम भी सामने आए।

1990 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था (कुछ लोग सोचते हैं कि इसकी शुरुआत अस्सी के दशक में हुई)। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में देश को व्यापक आर्थिक असंतुलन का सामना करना पड़ा, जिसने सरकार को 1991 में संरचनात्मक सुधार शुरू करने के लिए प्रेरित किया। केन्द्र और राज्य सरकारों के बड़े संयुक्त घाटे, बढ़ती मुद्रास्फीति का दबाव और चालू खाता घाटे ने भुगतान संतुलन संकट की स्थिति पैदा कर दी थी। तब स्थिति पर काबू पाने के लिए भारत ने आर्थिक उदारीकरण और सुधारों की राह पकड़ी।

सरकार ने लाइसेंस राज को खत्म करने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और निजीकरण को बढ़ावा देने की नीतियां लागू कीं। प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूल्यह्रास की अनुमति देते हुए विनिमय दर को लचीला बनाया गया। चालू खाते पर रुपया पूर्णतः और पूंजी खाते पर आंशिक रूप से परिवर्तनीय हो गया। बाजार-उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर इस बदलाव ने विकास के रास्ते खोले, उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया और वैश्विक निवेश को आकर्षित किया। वास्तविक विकास दर वर्ष 1993 और 2000 के बीच, 1980 के दशक की औसतन 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गई। विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार-से-जीडीपी अनुपात 1990 के 17.2 प्रतिशत से बढ़कर 2000 में 30.6 प्रतिशत हो गया।

नई सहस्राब्दी में रुक-रुक कर हुई प्रगति के बावजूद इन सुधारों को जारी रखा गया। 2000 के दशक की शुरुआत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और अधिक उदार बनाया गया। 1999 की नई दूरसंचार नीति ने भारत में आईटी क्षेत्र में तेजी ला दी, जिससे अन्य क्षेत्रों को भी बड़ा लाभ हुआ। इस अवधि के दौरान इन पहलों के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना के साथ, विनिवेश और निजीकरण की नीति ने गति पकड़ी। व्यापक आर्थिक असंतुलन को दूर

1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में देश को व्यापक आर्थिक असंतुलन का सामना करना पड़ा, जिसने सरकार को 1991 में संरचनात्मक सुधार शुरू करने के लिए प्रेरित किया। केन्द्र और राज्य सरकारों के बड़े संयुक्त घाटे, बढ़ती मुद्रास्फीति का दबाव और चालू खाता घाटे ने भुगतान संतुलन संकट की स्थिति पैदा कर दी थी। तब स्थिति पर काबू पाने के लिए भारत ने आर्थिक उदारीकरण और सुधारों की राह पकड़ी।

करने के लिए संरचनात्मक नीतियां बनाई गईं। सरकार के ऐतिहासिक रूप से उच्च संयुक्त सकल राजकोषीय घाटे पर काबू पाने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम बनाया गया था। 1991 के सुधारों के बाद आर्थिक पुनरुत्थान के दौरान जमा हुए खराब ऋणों के बोझ से दबी बैंकिंग प्रणाली को ब्याज दरों के विनियमन और सरफेसी कानून 2002 के माध्यम से सहायता प्रदान की गई थी। संरचनात्मक सुधारों के इन वर्षों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक-आर्थिक नींव को मजबूत किया ताकि आने वाले वर्षों में उच्च विकास दर को हासिल किया जा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां 2003-2008 में वैश्विक विकास दर औसतन 4.8 प्रतिशत थी, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8 प्रतिशत से अधिक की औसत विकास दर हासिल की। घरेलू आर्थिक गतिविधियों में निरंतर गति, बेहतर कॉर्पोरेट प्रदर्शन, निवेश के अनुकूल माहौल और अनुकूल वैश्विक तरलता की स्थिति तथा ब्याज दरों के परिणामस्वरूप 2004 से 2008 तक भारत में पर्याप्त पूंजी प्रवाह हुआ। घरेलू ऋण विशेष रूप से बैंक ऋण, सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में दोगुना हो गया। 2022-23 के लिए सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 2 में इसका विवरण दिया गया है।

सहस्राब्दी के पहले दशक में इस अरक्षणीय ऋण उछाल ने बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्तियों में वृद्धि की। जैसे-जैसे कंपनियों का निवेश कम होता गया, बैंक ऋण चुकाने की उनकी क्षमता भी कम होती गई। इससे वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्र की बैलेंस शीट की त्रुटियों को ठीक करने की लंबी अवधि शुरू हो गई, जिसके लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र की सहायता के लिए कई नीतिगत उपाय किए। सरफेसी अधिनियम 2002 में संशोधन, दिवाला और ऋण-शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन, 'परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा' की शुरूआत, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे को अपनाना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण तथा विलय और अन्य उपायों ने बैंकों और निगमों की बैलेंस शीट के मुद्दों को हल करने में मदद की।

नए जमाने के सुधार

सहस्राब्दी के दूसरे दशक में बैलेंस शीट को दुरुस्त करने से देश की विकास क्षमता और गतिशीलता पर विपरीत असर पड़ा। नतीजतन, 2014 से सरकार की आर्थिक नीति का ध्यान कारोबार सुगमता और भौतिक तथा डिजिटल बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार कर भारत की विकास क्षमता को बहाल करने पर रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य समग्र व्यावसायिक माहौल में सुधार करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। संचालन व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाते हुए कारोबार सुगमता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विविध आर्थिक सुधार लागू किए गए हैं।

दिवाला तथा ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) जैसे सुधारों के माध्यम से नियामक ढांचे के सरलीकरण ने कारोबार सुगमता को बढ़ाया है और इससे निवेशक भावना में सुधार हुआ है। दिवाला तथा ऋण शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम की प्रक्रियाओं से बचने के लिए, ऋण अदा नहीं करने के मामलों में अदालत के बाहर सेटलमेंट का चलन बढ़ा है। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम ने रियल एस्टेट क्षेत्र को और अधिक संगठित बनाकर उसमें बदलाव ला दिया है, जिसके परिणामस्वरूप नए लॉन्च और मकानों की बिक्री में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, 2014 के बाद से भारत में कराधान तंत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। एकीकृत वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को अपनाना, कॉर्पोरेट और आयकर दरों में

कमी, सॉवरेन वैल्थ फंड और पेंशन फंड को कर में छूट, लाभांश वितरण करों से छूट और पूर्वव्यापी कर को समाप्त करने सहित कर नीति में सुधार से व्यक्तियों और व्यवसायों पर कर का बोझ कम हो गया है। जीएसटी के कार्यान्वयन ने कर आधार को व्यापक बनाया है, अनुपालन आवश्यकताओं को कम किया है, राज्य के बाहर माल के मुक्त प्रवाह की सुविधा प्रदान की है और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में योगदान दिया है। जीएसटी व्यवस्था ने पहले की तुलना में कर संग्रह को बेहतर किया है। जीएसटी का औसत मासिक सकल संग्रह वित्त वर्ष 2018 के 0.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 1.5 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 1.7 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जीएसटी करदाताओं की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बड़ी संख्या में छोटे व्यवसाय जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत आ रहे हैं।

लंबे समय से चली आ रही बुनियादी ढांचे की कमियों और लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने के लिए 2014 के बाद से बड़े पैमाने पर सार्वजनिक खर्च भी किया गया है। केन्द्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 3.8 प्रतिशत हो गया है। इस निवेश का उद्देश्य सड़क संपर्क (भारतमाला), बंदरगाह बुनियादी ढांचे (सागरमाला), विद्युतीकरण, रेलवे और हवाई अड्डों/हवाई मार्गों (यूडीएएन) जैसे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 व्यापक लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करके इन पहलों में सहयोग कर रही है।

भारत जैसे विशाल देश में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निरंतर और दीर्घकालिक प्रयासों की आवश्यकता को पहचानते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (एनआईपी) की स्थापना की है। इस दूरदर्शी दृष्टिकोण वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 2024-25 तक पांच वर्षों में लगभग 111 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। वर्तमान में, 108 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल निवेश के साथ 9,000 से अधिक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इसके अलावा, निवेश माहौल में सुधार के लिए पिछले नौ वर्षों में कई सुधार और पहल की गई हैं। 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमताओं और विभिन्न उद्योगों में निर्यात को बढ़ावा देना है। विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक चैंपियन के रूप में उभरने और घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) पेश किए गए हैं। निजी क्षेत्र के लिए व्यावसायिक अवसर बढ़ाने के लिए रक्षा, खनन और अंतरिक्ष सहित रणनीतिक क्षेत्रों को खोल दिया गया है। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति को और उदार बनाया है, अधिकांश क्षेत्र अब स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खुले हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की

2014 से सरकार की आर्थिक नीति का ध्यान कारोबार सुगमता और भौतिक तथा डिजिटल बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार कर भारत की विकास क्षमता को बहाल करने पर रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य समग्र व्यावसायिक माहौल में सुधार करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। संचालन व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाते हुए कारोबार सुगमता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विविध आर्थिक सुधार लागू किए गए हैं।

उपस्थिति को केवल कुछ रणनीतिक क्षेत्रों तक सीमित करने के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति लागू की गई है।

नीतिगत अनिश्चितताओं को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत छोटे आर्थिक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से कारोबार सुगमता में काफी सुधार हुआ है। इस सुधार के परिणामस्वरूप, 1,400 से अधिक डिफॉल्ट मामलों को अदालती कार्यवाही का सहारा लिए बिना हल किया गया है, और 4,00,000 से अधिक कंपनियों ने दंड से बचने के लिए स्वेच्छा से पिछले डिफॉल्ट को ठीक किया है। इसके अतिरिक्त, पिछले नौ वर्षों में लगभग 25,000 अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त कर दिया गया है, और 1,400 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया गया है।

जलवायु परिवर्तन से प्रेरित ऊर्जा बदलाव और कृत्रिम मेधा जैसे तकनीकी विकास की राजनीतिक तथा आर्थिक रणनीतिक चुनौतियों और भारत की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक तथा उचित आर्थिक सुधार, 2047 तक देश के लिए उज्ज्वल और संतुलित विकास की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस दृष्टिकोण के माध्यम से, भारत भविष्य में टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार कर सकता है।

निरंतर सुधारों ने छोटे व्यवसायों को महामारी के प्रभाव से उबरने में भी सहायता की है और उनके विकास को सुविधाजनक बनाया है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस), आत्मनिर्भर भारत के दायरे में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन, एमएसएमई के लिए विलंबित भुगतान को संबोधित करने के लिए टीआरईडीएस की शुरूआत, खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल करने और एमएसएमई की स्थिति में सुधार की स्थिति में तीन साल के लिए गैर-कर लाभों के विस्तार जैसी पहल ने इस क्षेत्र में बदलाव लाने में योगदान दिया है।

इन सुधारों के दौरान प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म को एकीकृत करना एक सामान्य विषय रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि भारत की कोर डिजिटल अर्थव्यवस्था 2014 और 2019 के बीच समग्र आर्थिक विकास की तुलना में 2.4 गुना बढ़ी है। इस डिजिटीकरण का अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उच्च वित्तीय समावेशन, अधिक नियमनिष्ठ जैसे विभिन्न माध्यमों से विकास की इसकी क्षमता मजबूत हुई है तथा कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

डिजिटल बुनियादी ढांचे ने डिजिटल पहचान के निर्माण, वित्त और बाजारों तक बेहतर पहुंच, लेनदेन लागत में कमी और कर संग्रह में वृद्धि की सुविधा प्रदान की है। हालिया डिजिटल पहल, जैसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, आर्थिक विकास को बढ़ाने में सक्षम हैं। ओएनडीसी ई-कॉमर्स, व्यवसायों के लिए अधिक बाजार पहुंच प्रदान करेगा, जिससे विकास और विस्तार के नए अवसर खुलेंगे। अकाउंट एग्रीगेटर ढांचा छोटे व्यवसायों के लिए अधिक सुलभ ऋण को भी सक्षम बनाएगा, जिससे विकास और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

आगे बढ़ने का रास्ता

भारतीय अर्थव्यवस्था में किए गए नए युग के सुधार अमृत काल के दौरान इसके विकास की नींव रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में विकसित मजबूत वित्तीय क्षेत्र कुशल ऋण प्रावधान सुनिश्चित करेगा, जो आने वाले वर्षों में अधिक निवेश और खपत के माध्यम से गतिशील आर्थिक विकास में योगदान देगा। पुनः स्थापित ऋण चक्र और सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में वृद्धि भारतीय निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय चक्र को फिर से जीवंत कर देगी। डिजिटीकरण सुधार और अधिक नियमनिष्ठता, उच्च वित्तीय समावेशन और अधिक आर्थिक अवसरों के संदर्भ में परिणामी दक्षता लाभ, भारत के आर्थिक विकास के आवश्यक वाहक होंगे। उच्च-स्तरीय विनिर्माण और मध्यम अवधि में मूल्यवर्धित सेवाओं के तीव्र विकास के लिए व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार में निरंतर गति, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि और कुशल कार्यबल की उच्च उपलब्धता की आवश्यकता होगी।

जलवायु परिवर्तन से प्रेरित ऊर्जा बदलाव और कृत्रिम मेधा जैसे तकनीकी विकास की राजनीतिक तथा आर्थिक रणनीतिक चुनौतियों और भारत की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक तथा उचित आर्थिक सुधार, 2047 तक देश के लिए उज्ज्वल और संतुलित विकास की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस दृष्टिकोण के माध्यम से, भारत भविष्य में टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार कर सकता है। ❑

संवहनीय मैनुफैक्चरिंग की ओर छलांग

भारत ने पिछले दशक में खास तौर से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों के अंतर्गत अपनी स्वदेशी मैनुफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धिता को मजबूत करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। मैनुफैक्चरिंग में रोजगार पैदा करने की सबसे ज्यादा क्षमता है। इस क्षेत्र में 2030 तक छह करोड़ से सात करोड़ तक रोजगार पैदा हो सकते हैं। मैनुफैक्चरिंग का भविष्य संवहनीयता में बसा है। भारत सरकार जीरो डिफेक्ट-जीरो एफेक्ट और डिजिटल इंडिया जैसी अनेक पहलकदमियों के माध्यम से व्यवसायों को संवहनीय मैनुफैक्चरिंग अपनाने के लिये प्रेरित कर रही है। देश ने पिछले सात वर्षों में अपने नीतिगत और नियामक परिवेश में काफी सुधार किया है। इससे उद्यमों के लिये खुद को स्थापित करना और फलना-फूलना बहुत आसान हो गया है।

अंशुमान खन्ना | सहायक महासचिव, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (फिक्की)।
ईमेल: anshuman.khanna@ficci.com

स्वतंत्र भारत की 75 वर्षों की यात्रा आसान नहीं रही है। औपनिवेशिक शासकों ने हमारे देश की संपदा को बरबाद कर दिया था। लेकिन आज़ादी के बाद लंबा सफर तय करते हुए भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। भारत के लिये यह अपनी क्षमता को पहचानने और कोविड के बाद की नयी वैश्विक व्यवस्था में विश्व गुरु बन कर उभरने का समय है। यह अनिवार्य है कि हम इंसान और पृथ्वी की रक्षा करते हुए संवहनीय और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा दें।

फिक्की-मैकिंजी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2047 तक उच्च आय वाला राष्ट्र बन जाने की उम्मीद है। उसकी प्रति व्यक्ति आय मौजूदा समय से छह गुना ज्यादा होने और बढ़ते कार्यबल को काम देने के लिये 60 करोड़ रोजगारों

के सृजन की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत हो सकती है। इस क्षमता को हासिल कर भारत 2047 तक सही मायनों में लगभग 1500 लाख करोड़ रुपये (190 खरब डॉलर) की अर्थव्यवस्था बन सकता है।

अर्थव्यवस्था को इस लक्ष्य तक पहुंचाने में उद्योग की प्रमुख भूमिका होगी। हाल के नीतिगत सुधारों से उद्योग के विकास के लिये अनुकूल माहौल तैयार हुआ है। इन सुधारों में माल और सेवा कर, राष्ट्रीय सिंगल-विंडो प्रणाली तथा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शामिल हैं। लगातार विस्तृत की जा रही पीएलआई योजना से इलेक्ट्रॉनिक्स और पूंजीगत सामान, रसायन, कपड़ा, विद्युत वाहनों समेत वाहन और पुर्जे, सौर मॉड्यूल, बैटरी तथा औषधि और चिकित्सा उपकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास को गति मिलने की संभावना है। पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी केन्द्र सरकार की अन्य पहलकदमियों से भी भारतीय मैनुफैक्चरिंग पारिस्थितिकी में उछाल के लिये अनुकूल माहौल बना है।

कुल मिला कर सभी क्षेत्रों में से मैनुफैक्चरिंग में रोजगार पैदा करने की सबसे ज्यादा क्षमता है। इस क्षेत्र में 2030 तक छह करोड़ से सात करोड़ तक रोजगार पैदा हो सकते हैं। वर्ष 2022 में मैनुफैक्चरिंग में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7 से 8 प्रतिशत थी। देश इसे 9 से 10 प्रतिशत तक पहुंचाने की सोच सकता है। भारत 2030 तक मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र की उत्पादकता को पांच गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल सकता है। इसके लिये श्रम उत्पादकता को तीन गुना और पूंजी उत्पादकता को दोगुना करना होगा। सूक्ष्म, छोटे और मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के लिये 70 से 80 प्रतिशत डिजिटल अंगीकरण हासिल करना होगा। वस्तु इंटरनेट (आईओटी) और मशीनीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ ही उत्पादकता वृद्धि के लिये विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) से लाइटहाउस प्रमाणनों की संख्या में दस गुना इजाफा करना होगा। ये लक्ष्य वास्तविकता में तभी तब्दील होंगे जब सबसे छोटे मैनुफैक्चरिंग एमएसएमई तक समूची शृंखला का हिस्सा बनें।

मैनुफैक्चरिंग में पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिये निम्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा।

विश्व की नये युग की फैक्टरी : वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में परिवर्तनों के बीच भारत के लिये चमकने का अवसर

कोविड 19 की वैश्विक महामारी ने संकेंद्रित आपूर्ति शृंखलाओं की चुनौतियों को उजागर कर दिया है। दुनिया भर की कंपनियां अपने प्राथमिक आपूर्तिकर्ताओं के विकल्पों की तलाश में हैं ताकि ज्यादा लचीलापन सुनिश्चित किया जा सके। भारत इस उभरते अवसर का फायदा उठाते हुए प्रमुख वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। ये आपूर्ति शृंखलाएं 2030 में 800 अरब से 12 खरब डॉलर तक की हो जाएंगी।

भारत ज्यादा तेज आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिये वैश्विक मूल्य शृंखलाओं का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है। कपड़ा और सिलेसिलाये वस्त्र जैसे श्रम के ज्यादा महत्व वाले क्षेत्रों में भारत वैश्विक मूल्य शृंखला से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बेशक, इनमें विस्तार की संभावनाएं अभी भी मौजूद

हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पूंजी के ज्यादा महत्व वाले कुछ क्षेत्रों में भी वैश्विक मूल्य शृंखला से भारत का जुड़ाव अच्छा है।

सरकार ने पीएलआई के लिये विविध क्षेत्रों को चुना है। मोबाइल फोन, एसीसी बैटरी, उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, ड्रोन, वियरेबल, सेमीकंडक्टर और विशिष्ट इस्पात जैसे नये जमाने के अनेक क्षेत्रों में यह योजना शुरू की गयी है। सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहनों का एक बड़ा हिस्सा नये जमाने के इन क्षेत्रों के लिये है। ये नये युग के क्षेत्र भारत को मैनुफैक्चरिंग के केन्द्र के रूप में प्रमुखता दिलाने में मददगार होंगे। इन प्रयासों के नतीजे दिखायी देने लगे हैं। भारत में 2014 में मोबाइल फोन की सिर्फ दो फैक्टरियां थीं। लेकिन इस क्षेत्र को नीतिगत समर्थन दिये जाने के परिणामस्वरूप अब हम मोबाइल फोन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गये हैं। मौजूदा समय में भारत 11 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के मोबाइल फोन का निर्यात करता है। मोबाइल उपकरणों के वैश्विक बाजार में भारत एक प्रमुख निर्यातक के तौर पर उभरा है। देश से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में पांचवां सबसे बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन का है।

हमारा लक्ष्य मुंबई-ठाणे-रायगढ़ क्लस्टर की तरह क्लस्टरों को बंदरगाह के नजदीक विकसित कर इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और चिकित्सा उपकरण जैसी पांच से छह विशिष्ट वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की मौजूदगी बढ़ाने का होना चाहिए। राज्य सरकारें अपनी मैनुफैक्चरिंग क्षमताओं के अनुरूप सभी सुविधाओं से लैस क्लस्टर क्षेत्रों की स्थापना कर इन प्रयासों में सहायक बन सकती हैं। मसलन, सरकार के सड़क विकास कार्यक्रम भारतमाला के अंतर्गत अनेक शहरों में बहुविध लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किये जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और वैमानिकी में नागपुर की तरह मैनुफैक्चरिंग के लिये विश्व स्तरीय और कार्यकुशल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र बन सकते हैं। सोलापुर कपड़ा और सिलेसिलाये वस्त्रों का केन्द्र बन सकता है। इसके अलावा क्षमता उपयोग को 80 प्रतिशत से ज्यादा करने के लिये अनुबंध उत्पादन, नवोन्मेष अनुदान जैसे आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम तथा सिंगल विंडो मंजूरी से इन विशिष्ट वैश्विक मूल्यशृंखलाओं में भारत की मौजूदगी बढ़ सकती है।

मैनुफैक्चरिंग का भविष्य संवहनीयता में बसा है। ग्राहकों को वैसे उत्पादों और साझीदारों की तलाश है जो संवहनीयता के लिये प्रतिबद्धता में हिस्सेदारी करते हुए पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं और हरित नीतियों का पालन करें। वित्तीय लाभों और वैश्विक प्रतिस्पर्धिता के लिये भी संवहनीयता महत्वपूर्ण है। इसलिये भी उत्पादकों को संवहनीयता की दिशा में कदम उठाते हुए इसे अपनी रणनीति और संचालन के प्रमुख लक्ष्य में शामिल करना चाहिए।

मैनुफैक्चरिंग में डिजिटल क्रांति का अंगीकरण

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मैनुफैक्चरिंग उद्योग ने वित्त वर्ष 2021 में उद्योग 4.0 समाधानों पर 5.5 से 6.5 अमेरिकी डॉलर तक की रकम खर्च की। सरकार के नियम और निजी क्षेत्र के निवेश भारतीय मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र को डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये प्रेरित कर रहे हैं। छोटे, मझोले और बड़े मैनुफैक्चरिंग उपक्रम अपने व्यवसाय के कुछ या सभी स्तरों पर डिजिटलीकरण के लिये वस्तु इंटरनेट, कृत्रिम मेधा, बिग डाटा वैश्लेषिकी और रोबोटिक्स जैसी 4.0 प्रौद्योगिकियों के उपयोग से उत्पादन के नये प्रतिमान विकसित कर सकते हैं। इससे वे इस नयी औद्योगिक क्रांति की अग्रिम कतार में शामिल हो सकेंगे।

डिजिटलीकरण से विश्वसनीयता और मूल्य शृंखला के लचीलेपन में सुधार हो सकता है। मसलन, दूरमापन जैसी उन्नत वैश्लेषिकी का उपयोग कर उत्पादक अपने डिलीवरी नेटवर्कों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इससे वे भंडारण और वितरक के स्तर पर मांग का बेहतर ढंग से अनुमान भी लगा सकेंगे। प्रौद्योगिकी अनुदान और अंतरराष्ट्रीय संयुक्त उपक्रमों से प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता हासिल करने में सहायता मिलेगी जो मैनुफैक्चरिंग को डिजिटल भविष्य में ले जाने में मददगार होगी। स्मार्ट मैनुफैक्चरिंग में 5 जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उद्योग 4.0 के लिये 5 जी के इस्तेमाल के क्षेत्रों में संयोजित संपदा निगरानी, संबद्ध भंडारगृह, अनुमान आधारित रखरखाव, लॉजिस्टिक्स और फ्लीट मैनेजमेंट तथा गुणवत्ता प्रबंधन शामिल हैं।

मैनुफैक्चरिंग उद्योगों की सहायता के लिये प्रौद्योगिकीय विकास पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की प्रौद्योगिकीय प्रगति के लिये सही कौशलों और क्षमताओं वाला कार्यबल भी आवश्यक है। मैनुफैक्चरिंग एमएसएमई के भविष्योन्मुख होने के लिये कौशल विकास और उन्नयन में सहयोग देना वक्त की जरूरत है। भारत को कौशलों में असमानता को खत्म करने के लिये ठोस कौशल विकास कार्यक्रमों में ज्यादा निवेश करना होगा। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिये शैक्षिक संस्थानों और उद्योग संस्थाओं के बीच

सहयोग की भी दरकार होगी। शैक्षिक संस्थानों और डिजिटल प्रशिक्षण मंचों की मदद से बड़े उत्पादक आधुनिक मैनुफैक्चरिंग प्रौद्योगिकियों के साथ अपने कामगारों का कौशल उन्नयन और परिमार्जन कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार को भी प्रौद्योगिकीय निवेशों, अनुसंधान और विकास तथा संस्थानिक क्षमता के विस्तार को प्रोत्साहन देना चाहिए। इन तत्वों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने से भारत के औद्योगीकरण की रफ्तार में तेजी आ सकती है।

संवहनीय मैनुफैक्चरिंग के भविष्य की ओर छलांग

मैनुफैक्चरिंग उद्योग ग्रीन हाउस गैसों और अन्य प्रदूषकों का एक बड़ा स्रोत है। इसलिये पर्यावरणीय मसलों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। मैनुफैक्चरिंग का भविष्य संवहनीयता में बसा है। ग्राहकों को वैसे उत्पादों और साझीदारों की तलाश है जो संवहनीयता के लिये प्रतिबद्धता में हिस्सेदारी करते हुए पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं और हरित नीतियों का पालन करें। वित्तीय लाभों और वैश्विक प्रतिस्पर्धिता के लिये भी संवहनीयता महत्वपूर्ण है। इसलिए भी उत्पादकों को संवहनीयता की दिशा में कदम उठाते हुए इसे अपनी रणनीति और संचालन के प्रमुख लक्ष्य में शामिल करना चाहिए। औद्योगिक विस्तार के क्रम में पर्यावरण पर उत्पादन के विपरीत प्रभावों के बारे में सचेत रहना जरूरी है। उत्पादकों को अपने तरीकों में लगातार बदलाव और सुधार लाना होगा। उन्हें संवहनीयता के लिये नये समाधानों की तलाश करनी होगी।

भारत सरकार जीरो डिफेक्ट-जीरो एफेक्ट और डिजिटल इंडिया जैसी अनेक पहलकदमियों के माध्यम से व्यवसायों को संवहनीय उत्पादन प्रक्रिया अपनाने के लिये प्रेरित कर रही है। इन पहलकदमियों की सफलता के लिये समूची मूल्य श्रृंखला में उत्पादकों को हरित विकल्पों के सृजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन विकल्पों में जैव आधारित कच्चा माल, संवहनीय पैकेजिंग और हरित मैनुफैक्चरिंग सामग्रियां शामिल हो सकती हैं। उद्योग को एकजुट होकर हरित लेबलों के लिये मानक परिभाषित करने में सहायता करनी चाहिए। उन्हें हरित उत्पादों के लिये एक ठोस ऑडिटिंग प्रक्रिया भी स्थापित करनी चाहिए। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ उत्पाद विकास से संवहनीय मैनुफैक्चरिंग की वास्तविक क्षमता का लाभ उठाने और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। उद्योग 4.0 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और डिजिटलीकरण के मेल से औद्योगिक प्रक्रियाओं और संवहनीयता के लक्ष्यों के बीच तालमेल का विशेष अवसर प्रस्तुत करता है। दीर्घकालिक आर्थिक लाभों के लिये यह महत्वपूर्ण है कि नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से एक ऐसी हरित और व्यवस्थित मैनुफैक्चरिंग प्रणाली तैयार की जाए जो संवहनीय व्यवसायों को सक्षम बनाने में समर्थ हो।

अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

एक औद्योगिक मूल्य श्रृंखला के अंदर बड़े पैमाने पर माल ढुलाई के मामले में भारत की कुछ कमजोरियां हैं। देश में माल ढुलाई में लगने वाला खर्च और समय ज्यादा है। औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसे हस्तक्षेपों के जरिये इन चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य और केन्द्र सरकारें प्रमुख मैनुफैक्चरिंग केन्द्रों में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच साझीदारी तथा विशेष उद्देश्य उपायों के माध्यम से अवसंरचना को मजबूती दे सकती हैं। इस तरह से स्मार्ट सिटी कवरेज का भी विस्तार किया जा सकता है। वे सौर अवसंरचना के जरिये ग्रामीण बाजार विद्युतीकरण जैसी अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने के लिये नयी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत कई क्षेत्रों में आयात स्थानीयकरण पर विचार किया जा रहा है। इन क्षेत्रों को उपयोग के लिये पूरी तरह से तैयार अवसंरचना के जरिये प्रोत्साहित किया जा सकता है। भारतीय उद्योगों को शासन प्रायोजित व्यापक शहरी अवसंरचना विकास की भी दरकार है ताकि वे चीन और पश्चिम के बीच रणनीतिक अलगाव से पैदा अवसरों का लाभ उठा सकें।

आगे का रास्ता

भारत ने पिछले सात वर्षों में अपने नीतिगत और नियामक परिवेश में काफी सुधार किया है। इससे उद्यमों के लिये खुद को स्थापित करना और फलना-फूलना बहुत आसान हो गया है। फिक्की को विश्वास है कि सौ साल के भारत की ओर यात्रा में सुधारों की प्रक्रिया में और तेजी आएगी तथा वह बुनियाद मजबूत होगी जिस पर देश का कार्यकुशल, उत्पादक, संवहनीय और निर्यातोन्मुख विश्व स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र खड़ा होगा। ❑

दृष्टि The Vision

Drishti IAS

UPSC के इतिहास में हिंदी माध्यम के सर्वश्रेष्ठ नतीजे

Drishti IAS के 54+ सफल विद्यार्थी

66 कृतिका मिश्रा — हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, मेंटरशिप प्रोग्राम
85 भरत जय प्रकाश मीणा — जीएस फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम
89 प्रिंस कुमार — जीएस फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम
105 दिव्या — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़, अस्मिता योजना
120 गगन सिंह मीणा — AWAKE प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम
173 अंकित कुमार जैन — हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, मेंटरशिप प्रोग्राम, अस्मिता योजना
226 गौरव कुमार त्रिपाठी — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
240 शशि शेखर — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
268 आफिप खान — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
296 मोइन अहमद — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
318 प्रधुम्न सिंह यादव — जीएस फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम
378 नारायण उपाध्याय — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़, अस्मिता योजना
381 मुदिता शर्मा — जीएस फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम, अस्मिता योजना
454 बजरंग प्रसाद — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
466 शुभम सिंह ठाकुर — जीएस फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम
467 पूजा मीणा — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
468 विकास गुप्ता — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
482 विकास सैथिया — जीएस फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम
483 भारती मीणा — जीएस फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम
486 प्रेमसुख दड़िया — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
507 राकेश कुमार मीणा — जीएस फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम
515 पंकज वर्मा — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
520 आदर्श पटेल — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
557 आशीष पूनिया — हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, मेंटरशिप प्रोग्राम
561 दिनेश कुमार गुहाल — जीएस फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम
567 रोशन मीणा — हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, निबंध और मेंटरशिप प्रोग्राम
571 रजनीश पटेल — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़, अस्मिता योजना
605 जतिन पराशर — हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, मेंटरशिप प्रोग्राम
636 ऋषि राज राय — जीएस फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम
644 ईश्वर लाल गुर्जर — हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, मेंटरशिप प्रोग्राम
651 मनीषा मीणा — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
665 गणपत राम यादव — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
667 राम भजन कुम्हार — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
674 हरीश कुमार — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
685 प्रेम कुमार भार्गव — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
695 मतेंद्र कुमार मीणा — हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, मेंटरशिप प्रोग्राम
708 विपिन दूबे — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
710 मोहन दान — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
732 रणवीर सिंह — जीएस फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम
733 सुषमा सागर — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
751 पंकज राजपूत — जीएस फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम, अस्मिता योजना
756 अमित कुमार यादव — जीएस फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम, अस्मिता योजना
786 मनोज कुमार — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
798 राम शंकर मीणा — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
803 सौरभ अहिरवार — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
819 मुकेंद्र कुमार — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
826 मिथलेश कुमारी मीणा — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
841 हिमांशु — जीएस फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम, अस्मिता योजना
842 हेमेंद्र सिंह — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
876 सतीश कुमार मीणा — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
877 अंजू मीणा — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
880 राजेश धुनावत — जीएस फाउंडेशन कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम
883 वीरेन्द्र कुमार मीणा — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़
889 दिनेश कुमार — मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़

और भी कई...

📞 87501-87501

मुखर्जी नगर
641, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली - 100009

करोल बाग
21, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005

जयपुर
हर्ष टावर 2, टोंक रोड वसुंधरा कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान - 302015

प्रयागराज
13/15, ताशकंद मार्ग, निकट - पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश - 211001

YH-2400/2023

G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम
ONE EARTH · ONE FAMILY · ONE FUTURE
आज़ादी का अमृत महोत्सव
YOJANA
Azadi Ka Amrit Mahotsav
YOJANA
YOJANA
BUDGET
YOJANA
FINTECH
YOJANA
Social Security
YOJANA
New-Age Tech
अब उपलब्ध
संकलन 2022
योजना (अंग्रेजी)
YOJANA
Tribals in India
YOJANA
Literature and Itself
YOJANA
YOJANA
OUR ECOSYSTEM
YOJANA
Indian Maritime
YOJANA
ARCHITECTURE
जनवरी से दिसंबर 2022
मूल्य : ₹300/-
प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
संकलन ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ईमेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in
/dpd_india
@DPD_India
/publicationsdivision

सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी के लिए सुलभ, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई व्यापक सुधारों की परिकल्पना की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की शक्ति के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) जैसे नए उपायों के बल पर गुणवत्ता में वृद्धि हुई है और शिक्षार्थियों ने बेहतर महसूस किया है।

अनिल सहस्रबुद्धे | अध्यक्ष, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, नई दिल्ली। ईमेल: chairman-netf@gov.in

प्रौद्योगिकी से 17वीं सदी से ही उद्योग 1.0 से लेकर उद्योग 4.0 तक, भाप इंजन के आविष्कार से लेकर अंतरिक्ष शटल तक, टेलीफोन से मोबाइल तक, इंटरनेट और 2जी से 5जी तक, और पीसी से सुपर कंप्यूटर तक हमारे जीवन में क्रांति आई है। तकनीकी परिवर्तन की रफ्तार चौंकाने वाली है और इसे बनाये रखना कठिन होता जा रहा है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन न केवल आवास, पानी, स्वच्छता, ऊर्जा स्रोत, संचार, परिवहन इत्यादि जैसे हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में हैं, बल्कि महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और कृषि में भी हैं। ब्लैकबोर्ड और चॉक, पेंसिल, पेन और कागज से लेकर ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी, पीसी, लैपटॉप, सीडी, डीवीडी और टीवी से लेकर स्मार्ट व्हाइट बोर्ड, इंटरनेट, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और एमओओसी प्लेटफार्मों ने दरवाजे पर शिक्षा को संभव बना दिया है, जिससे शिक्षा की डिलीवरी में बदलाव हुए हैं। शिक्षा आज किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी डिवाइस पर उपलब्ध है। पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए अनेक विकल्पों के बीच कई बार चयन करना कठिन हो जाता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) की शक्ति के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर), वर्चुअल रियलिटी (वीआर), एक्सटेंडेड रियलिटी (एक्सआर), एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) जैसे नए उपायों, और चैटजीपीटी ने गुणवत्ता को बढ़ाया है और शिक्षार्थियों का अनुभव बेहतर हुआ है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे 29 जुलाई, 2020 को लागू किया गया था, सभी के लिए सुलभ, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई व्यापक सुधारों की परिकल्पना की गई है। इसमें स्कूली शिक्षा में जीईआर को शत-प्रतिशत और उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत करना शामिल है। इसे केवल स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की इमारतों के माध्यम से हासिल करना मुश्किल है। यह तभी संभव है जब प्रौद्योगिकी और इसका इस्तेमाल हो, जो खाई को पाटने में सक्षम बनाएगा और पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा, सरकार के दृष्टिकोण से, यह निवेश पर अत्यधिक लाभदायक (आरओआई) होने के साथ-साथ किफायती भी है।

अब तक उल्लिखित प्रौद्योगिकियां पूरी तरह से नई नहीं हैं; वे लगभग दो दशकों से किसी न किसी रूप में अस्तित्व में हैं। हालांकि, इसका उपयोग सीमित था। कोविड-19 महामारी ने किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह दुनिया भर में शिक्षा क्षेत्र को बाधित कर दिया और मार्च 2020 में रातोंरात लगभग पूरी तरह से ठप हो गया। ऐसी स्थिति में डिजिटल होने, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और ऑनलाइन मोड में लोगों की शिक्षा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भारत भी इसका अपवाद नहीं था, हालांकि यह सभी क्षेत्रों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक था, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या अर्थव्यवस्था हो। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रौद्योगिकी, फाइबर कनेक्टिविटी, इंटरनेट और उपग्रहों के माध्यम से सामग्री की डीटीएच डिलीवरी के कारण, हमारी शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रही, हालांकि प्रवेश, परीक्षा और परिणाम में कुछ महीनों की देरी हुई और अब वे पटरी पर हैं। कई अन्य देशों ने पूरा शैक्षणिक वर्ष खो दिया। सभी नागरिकों का हमारा टीकाकरण और राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत मोबाइल पर को-विन एप्लिकेशन के माध्यम से टीकाकरण प्रमाणपत्रों की तुरंत ऑनलाइन डिलीवरी एक और बड़ी उपलब्धि थी। अर्थव्यवस्था में भी यही स्थिति थी, दुनिया में 40 प्रतिशत वित्तीय डिजिटल लेनदेन भारत में होता था।

क्या इसका मतलब यह है कि कोई चुनौतियां नहीं थीं और सब कुछ सामान्य था? हरगिज नहीं। कुछ अध्ययनों में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान शिक्षण के परिणाम खराब थे, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक डिजिटल विभाजन था, और एक छोटे से घर में कैद होने के कारण मनोवैज्ञानिक मुद्दे और स्वास्थ्य से जुड़ी तनावपूर्ण स्थितियां थीं। उस समय कई बच्चों के पास इंटरनेट और डिवाइस तक समान पहुंच नहीं थी। फिर भी, सैटेलाइट डायरेक्ट-टू-होम संचार के माध्यम से हमारी गहरी पहुंच और डाटा दरों की सबसे कम लागत के कारण यह अधिकांश अन्य देशों की तुलना में बेहतर था।

आइए देखें कि सुलभ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ कैसे उठाया जा रहा है। आईआईटी की कक्षाओं या संस्थान स्टूडियो में वीडियो-रिकॉर्ड किए गए इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम 2005 में एनपीटीईएल (नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग) पाठ्यक्रम के रूप में शुरू हुए और सीडी पर और आईआईटी मद्रास की एनपीटीईएल वेबसाइट से डाउनलोड करके उपलब्ध कराए गए, इस प्रकार आईआईटी के सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसरों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले व्याख्यान के माध्यम से सुदूर टियर-2 और टियर-3 कॉलेजों में पहुंच प्रदान की गई। यह सशक्तीकरण का पहला चरण था। इसके बाद, 2008 में, सभी कॉलेजों के लिए उपलब्ध सिमुलेशन-आधारित प्रयोगों के बल पर वर्चुअल लैब बनाई गईं, जहां कुछ उच्च-स्तरीय उपकरण उपलब्ध नहीं थे। वर्चुअल लैब के माध्यम से शिक्षण एक और सशक्त क्षण था। इस सामग्री तक पहुंचने के लिए प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान की गई 1 जीबीपीएस इंटरनेट कनेक्टिविटी एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी।

राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के माध्यम से चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर, राज्य स्तर, विश्वविद्यालय स्तर और यहां तक कि कॉलेज स्तर पर कई उत्साही लोगों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म (एलएमएस) बनाने या संलग्न करने के प्रयास किए गए, जिससे व्यक्तिगत या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण छूटी हुई कक्षाओं वाले लोगों के लिए शिक्षा सुलभ हो सके। मुक्त शिक्षा संसाधनों (ओईआर) का प्रसार और दुनिया भर में उनकी निःशुल्क उपलब्धता और अधिक सशक्त बना रही है।

कारगर शिक्षण और सीखने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और कई राज्य स्तरीय टियर-2 और टियर-3 कॉलेजों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक बड़ी बाधा रही है। भौतिक मोड में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संस्थान से छुट्टी, यात्रा और आवास लागत के संदर्भ में सीमाएं थीं। कुछ महिला शिक्षकों और संकाय सदस्यों को परिवार और छोटे बच्चों के प्रति समर्पण के कारण बाहर न जा पाने की अतिरिक्त समस्याएं थीं। ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से अमृता विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक सरल ए-व्यू प्लेटफॉर्म एक बड़ी सफलता थी। प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की उपलब्धता की बदौलत आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर द्वारा संचालित टी10केटी कार्यक्रम को बड़ी संख्या में संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने में भारी सफलता मिली, जिनमें से कई महिलाएं थीं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अटल अकादमी कार्यक्रम, जिसमें 1.5 लाख फैकल्टी को एआई, एमएल, रोबोटिक्स, ड्रोन, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उच्च-स्तरीय उभरती प्रौद्योगिकियों में साल-दर-साल प्रशिक्षित किया जाना, सफलता की एक और गाथा है। एआईसीटीई ने 8 फैकल्टी इंडक्शन मॉड्यूल भी बनाये, जो इंजीनियरिंग, शिक्षण अध्यापन, पाठ्यक्रम विकास, प्रौद्योगिकी के उपयोग, परीक्षा पेपर सेटिंग, अनुसंधान, नवाचार और संस्थान प्रशासन की भूमिका से शुरू होकर युवा प्रेरक शिक्षकों को सशक्त बनाते हैं।

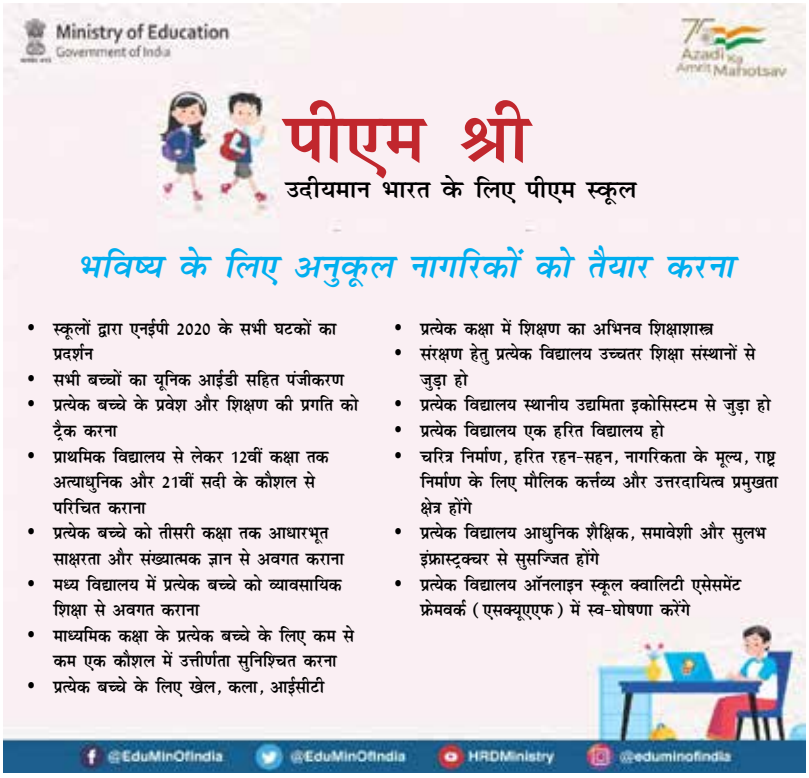

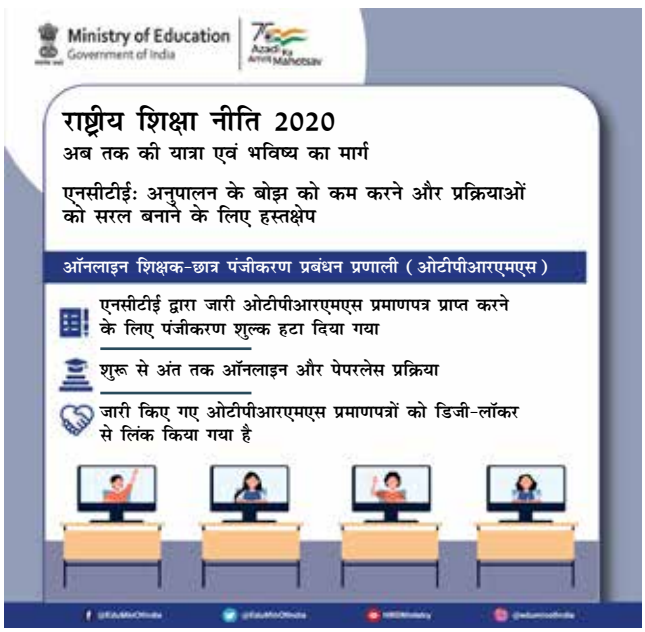

जब ये बदलाव हो रहे थे, 2011 में पहला एमओओसी (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स) अस्तित्व में आया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोरसेरा, एमआईटी से ईडीएक्स और कई अन्य लोकप्रिय हो गए। भारत कहीं पीछे ना रहे, इसलिए इसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से वित्त पोषण के साथ एआईसीटीई के माध्यम से अपना स्वयं का स्वदेशी एमओओसी प्लेटफॉर्म, स्वयम बनाया। आज, आईआईटीएम द्वारा बनाये गए इस उन्नत स्वयम 2.0 एमओओसी में न केवल देश के कोने-कोने से बल्कि कई विकासशील देशों से 3000 से अधिक पाठ्यक्रम और 3 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। कला, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध हैं। इससे छात्र और भी सशक्त हुए हैं।

छात्रों की नियोजननीयता अक्सर उद्योग निकायों द्वारा उठाया जाने वाला मुद्दा रहा है। व्यावहारिक अनुभव, अनुभवात्मक

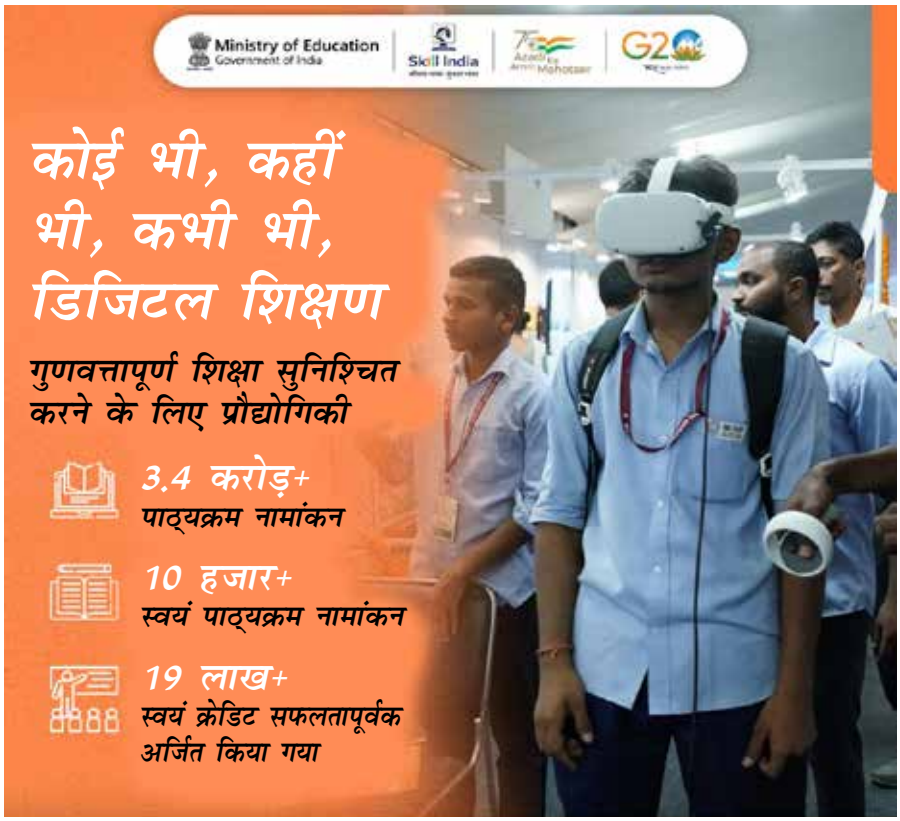

शिक्षा और व्यावहारिक इस्तेमाल-आधारित प्रशिक्षण आवश्यक महसूस किया जाता है। इसलिए, छात्रों को उद्योग से जुड़ाव प्रदान करने के लिए, एक विशेष इंटर्नशिप पोर्टल बनाया गया है जहां उद्योग, छोटे और बड़े, एमएसएमई और स्टार्टअप इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट करते हैं, और इंटर्नशिप चाहने वाले छात्र अपना बायोडाटा, क्षमताएं और रुचियां अपलोड करते हैं। एआई-आधारित मैचमेकिंग के माध्यम से, छात्रों को दो महीने से छह महीने तक की इंटर्नशिप मिलती है, जिससे उनके कौशल, ज्ञान के बल पर, रोजगार क्षमता में वृद्धि होती है। नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजीज (एनईएटी) नामक एक अन्य मंच ने छोटी और बड़ी कंपनियों और स्टार्टअप्स से प्रोग्रामिंग कौशल, उच्च-स्तरीय उभरते प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण मॉड्यूल, भाषा कौशल, संचार कौशल आदि को बढ़ाने के लिए कई एआई-आधारित वैयक्तिकृत शिक्षण उत्पादों को शामिल किया है। इससे छात्रों में रोजगार क्षमता बढ़ाने और उद्यमिता की भावना पैदा करने में भी मदद मिली है।

भाषा और शिक्षा की लागत देश के ग्रामीण, दूरदराज के इलाकों में कई छात्रों के लिए बाधा रही है, जिन्होंने अपनी शिक्षा अपनी-अपनी मातृभाषा में ली है, और उनके माता-पिता की आय कम होने के कारण वे अपने प्रतिभाशाली बेटों और बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए कस्बों और शहरों में भेज कर पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की उपलब्धता और एआई-आधारित ट्रांसलेशन टूल अणुवादिनी के इस्तेमाल से उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम-आधारित पुस्तकों का अनुवाद करके उन भाषाओं में किताबें प्रदान करना दूरदराज के क्षेत्रों में उनकी मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए कई प्रौद्योगिकियां भी चल रही हैं।

एआर, वीआर, एक्सआर और मेटावर्स जैसी प्रौद्योगिकियां उच्च गुणवत्ता वाली आकर्षक सामग्री बनाने में मदद करती हैं जिससे विषय को समझना आसान हो जाता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और आईआईटी खड़गपुर द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना लाखों पुस्तकों और दस्तावेजों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करती है। इसी तरह, इनफ्लिबनेट अनुसंधान पत्रिकाओं, थीसिस और रिपोर्ट तक पहुंच प्रदान करता है।

मौजूदा कुछ नई डिजिटल और तकनीकी पहलों में छात्रों द्वारा अर्जित सभी क्रेडेंशियल्स और क्रेडिट को डिजिलॉकर/एडुलॉकर में संग्रहीत करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) शामिल है; छात्र और संकाय रजिस्ट्री परियोजना जिसके तहत प्रत्येक छात्र और शिक्षक को एक अद्वितीय आजीवन एपीएआर आईडी मिलेगी जो उस व्यक्ति के एबीसी रिकॉर्ड से जुड़ी होगी, जिससे क्रेडेंशियल्स को ऑनलाइन प्रमाणित और सत्यापित किया जाएगा; वन नेशन वन डाटा पोर्टल, जिसके माध्यम से छात्रों और अभिभावकों द्वारा सूचित विकल्प चुनने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों; और विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत की ताकत दिखाने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल की जानकारी उपलब्ध होगी।

प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है। हम राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों, चाहे वे छात्र, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थान या राज्य सरकारें हों, उन्हें सूचित विकल्प प्रदान करने वाले सभी नवीनतम रुझानों से अवगत हैं, और इस प्रकार सभी के लिए सुलभ, न्यायसंगत, किफायती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं, ताकि 21वीं सदी के सशक्त नये भारत का निर्माण संभव हो सके। ❑

अटल इनोवेशन मिशन
एक समग्र नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

नवाचार आदिकाल से ही मानव विकास की आधारशिला रहा है। अग्नि की खोज से लेकर उसे नियंत्रित करने, पहिए के आविष्कार और इसके असंख्य उपयोगों तक नवाचार ने प्रागैतिहासिक काल से प्रगतिशील परिवर्तनों को जन्म दिया है।

प्रमित दाश
कार्यक्रम निदेशक, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग।
ईमेलः pramitdash.aim@govcontractor.in

"भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाना है'' – अज्ञात

औद्योगिक क्रांति के साथ और विशेषकर विगत शताब्दी में नवाचार का गहरा असर स्पष्ट तौर पर देखा गया है। इससे दुनिया भर में प्रौद्योगिकी में असाधारण बदलावों और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। इसने न केवल बढ़ती आबादी की जरूरतों और अपेक्षाओं की पूर्ति की है बल्कि हमारे जीवन को बेहतर, अधिक संयोजित और दिनोंदिन समृद्ध भी बनाया है।

लेकिन वास्तव में नवाचार क्या है?

नवाचार महत्वपूर्ण मसलों के नए समाधान प्रदान करके उनके महत्त्व को बढाने की प्रक्रिया है। यह किसी आविष्कार या स्थापित प्रौद्योगिकी के लिए नए अनुप्रयोगों का सृजन है।

पारंपरिक जीडीपी अनुमानों के अनुसार 1700 ईस्वी तक दुनिया की वास्तविक जीडीपी 0.1 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम की दर से बढ़ी क्योंकि यह केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण उपभोग वृद्धि से जुड़ी थी। विश्व सकल घरेलू उत्पाद में जबरदस्त वृद्धि 1750 के दशक के बाद शुरू हुई। इस बदलाव का श्रेय औद्योगिक क्रांति के दौरान प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों के आगमन को दिया जा सकता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण 18वीं शताब्दी में भाप इंजन प्रौद्योगिकी का विकास है। इसने छोटे और अधिक कुशल इंजनों के निर्माण को सक्षम बनाया जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ और वस्तुओं और लोगों के परिवहन में क्रांति का दौर आ गया।

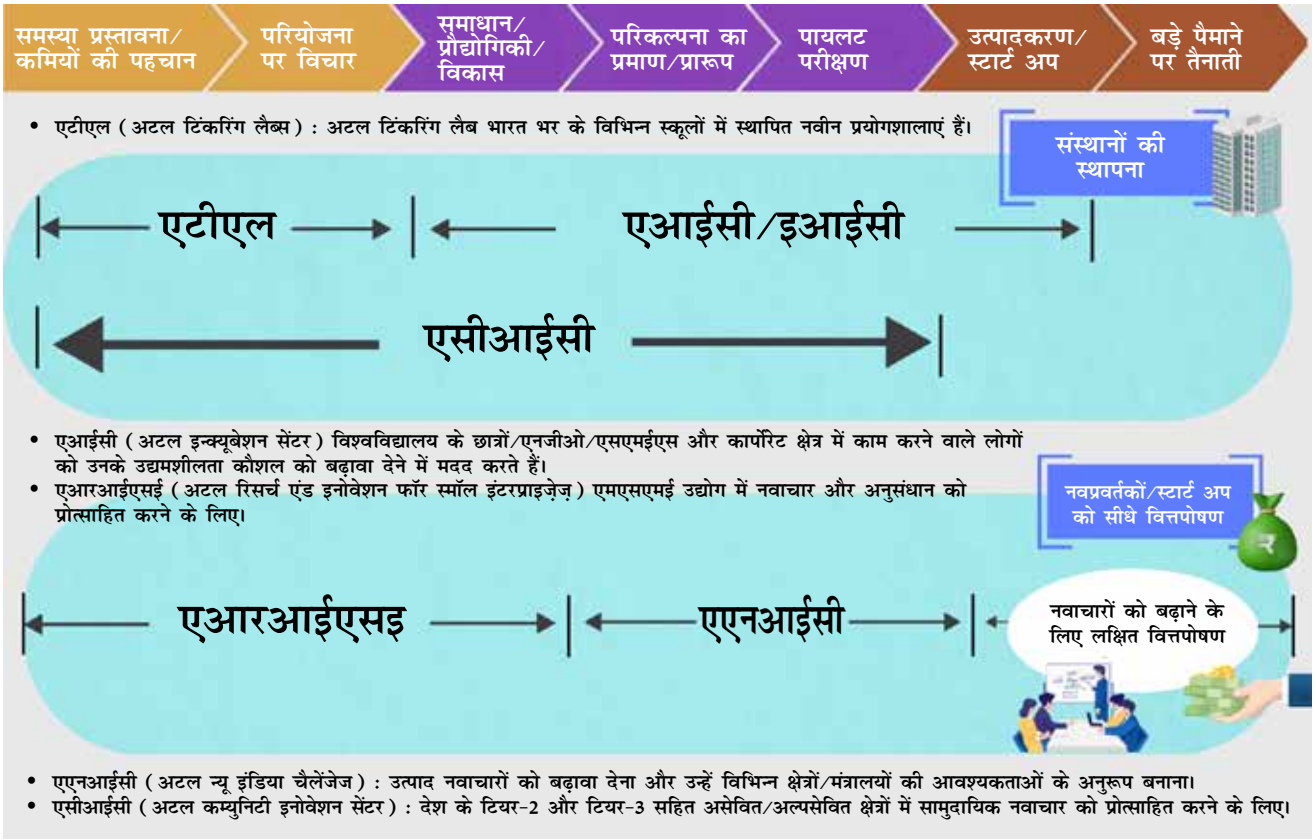

चित्र : नवाचार मूल्य शृंखला में एआईएम कार्यक्रम

केवल एक समाधान से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था कई पायदान ऊपर चली गयी।

इस प्रकार नवाचार किसी देश की अर्थव्यवस्था को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आर्थिक दृष्टिकोण से विकास का सिद्धांत सुझाता है कि कुल आउटपुट को श्रम, पूंजी और कुल कारक उत्पादकता के संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है।

सीधे शब्दों में कहें तो जीडीपी यानि कुल उत्पादकता टीएफपी के बराबर होता जा रहा है जिसके सबसे बड़े उप-वर्ग नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और दक्षता लाभ हैं।

अनुभवजन्य साक्ष्यों से हमें ज्ञात है कि दुनिया के सबसे विकसित देश - अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि - पारंपरिक रूप से प्रौद्योगिकी नवाचार में सबसे अग्रणी रहे हैं। यह किसी राष्ट्र की विकास यात्रा को निर्धारित करने में नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमाणित करता है।

ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर में सरकार ही है जो इसे बढ़ावा देने के लिए पहला कदम उठाती है।

चाहे वह नवाचार के केन्द्र के रूप में अपने इज़राइल रक्षा बल (आईडीएफ) वाला इज़राइल हो या एसबीए और लघु व्यवसाय नवाचार अनुसंधान (एसबीआईआर) कार्यक्रम वाला अमेरिका हो सरकार की भूमिका इसमें सर्वोपरि रही है। यह तब और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब हम भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में नवाचार की संस्कृति के निर्माण के बारे में सोचते हैं।

सहस्राब्दी के मोड़ पर भारत ने जमीनी स्तर पर तकनीकी नवाचारों और पारंपरिक ज्ञान को मजबूत करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (एनआईएफ) की स्थापना की। लगभग एक दशक बाद 2013 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का आरंभ हुआ। इस नीति का लक्ष्य विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार प्रणाली (सृष्टि) स्थापित करके भारत को उच्च प्रौद्योगिकी आधारित पथ पर अग्रसर करने के साथ भारत को विश्व की शीर्ष पांच वैज्ञानिक शक्तियों में स्थान दिलाने की आकांक्षा था। देश भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2013 का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने 2016 में देश के सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) की स्थापना की।

एआईएम का उद्देश्य भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण करना है। लेकिन किसी संस्कृति का निर्माण एक दीर्घकालिक मिशन है जिसके लिए एक नवप्रवर्तक के जीवनचक्र में निरंतर और लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती

है और इसमें नवाचार की संपूर्ण मूल्य शृंखला को शामिल किया जाना चाहिए। एआईएम ने अपने दायित्व को पूरा करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। इसने ऐसे कार्यक्रम, नीतियां और संस्थान विकसित किए हैं जिनमें स्कूली छात्रों से लेकर स्थापित स्टार्ट-अप तक विचार-विमर्श से लेकर विनियोजन तक का पूरा परिदृश्य शामिल होता है। हस्तक्षेपों की यह निरंतरता यह सुनिश्चित करती है कि सहायता के अभाव के कारण कोई नवप्रवर्तक अपने मार्ग से न भटके।

प्रारंभिक चरण में युवाओं के चिंतन में नवाचार के बीज बोए जाते हैं। इस दौरान स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) बच्चों के बीच टिंकरिंग की अवधारणा को बढ़ावा देती है जो चीजों को समझने और बनाने के दौरान समस्या-समाधान, नवीन मानसिकता को प्रेरित करती है।

थोड़े बाद के चरण में जब ये युवा कॉलेज में प्रवेश करते हैं और अपने विचारों को अवधारणाओं और स्टार्ट-अप में विकसित करना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा या अनुसंधान संस्थानों में स्थापित अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) सभी आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सहायता और पोषण देने के लिए तैयार होते हैं ठीक वैसे ही जैसे एक इनक्यूबेटर शिशुओं के साथ करता है। प्रमुख शहरों में नवाचार के सामान्य समूहों से आगे बढ़ने और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों और सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में अटल सामुदायिक नवाचार केन्द्र (एसीआईसी) नवाचार को भौगोलिक और भाषाई रूप से समावेशी बनाते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) कार्यक्रम के माध्यम से एआईएम राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने के लिए काम करने वाले स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई को परिकल्पना से लेकर व्यावसायीकरण तक सीधे वित्त पोषित करता है।

आइए अटल इनोवेशन मिशन के कार्यक्रम स्तंभों को समझा जाए:

एआईएम के कई स्तंभ हैं जिनके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। पिछले वर्षों में एआईएम ने नवप्रवर्तकों को उनके नवाचार के जीवन-चक्र में सहायता देने और भारत की नवाचार यात्रा में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल), अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स (एआईसी), अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स (एसीआईसी), अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी), और मेंटर ऑफ चेंज की शुरुआत की।

मेंटर इंडिया एआईएम द्वारा पूरे भारत में स्थापित 10,000+ अटल टिंकरिंग लैब्स में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए मार्गदर्शकों (परिवर्तन के सलाहकार) को चुनने की स्वैच्छिक पहल है जो युक्तिपूर्ण राष्ट्र-निर्माण में योगदान करती है।

अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल)

'भारत में दस लाख बच्चों को नियोटेरिक इनोवेटर्स के रूप में तैयार करने' की दृष्टि से, एआईएम ने पूरे भारत के स्कूलों में एटीएल की स्थापना की है। एटीएल छठी से 12वीं कक्षा के युवाओं में जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देने और समस्या-समाधान, नवोन्मेषी मानसिकता को प्रोत्साहित करने के लिए एक अत्याधुनिक मंच है। एटीएल में 21वीं सदी के उपकरण और प्रौद्योगिकियां जैसे कि आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूल, रोबोटिक्स, लघुरुपी इलेक्ट्रॉनिक्स, डीआइवाई (डू इट योरसेल्फ) किट आदि होते हैं। यहां युवा प्रायोगिक और स्वयं करें गतिविधियों (डू इट योरसेल्फ) के माध्यम से अपने विचारों को आकार दे सकते हैं।

एटीएल एक ऐसा स्थान प्रदान करते हैं जहां छात्र 'तोड़-फोड़-जोड़' के विचार के साथ सृजन करते हैं - यानी यहां उन्हें नवाचार करते हुए सृजन करने की स्वतंत्रता मिलती है। 21वीं सदी के कौशल के लिए छात्रों की क्षमता निर्माण के लिए एटीएल समय-समय पर कई पाठ्यक्रम और मॉड्यूल जारी करता है। एटीएल की प्रमुख पहल एटीएल मैराथन और टिंकरप्रेन्योर छात्रों को उत्पाद बनाने और उन्हें युवा उद्योगपति के रूप में दुनिया के सामने आने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सर्वश्रेष्ठ छात्रों को 'स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम' के माध्यम से उद्योग से जुड़ने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है जिसके अंतर्गत वे विभिन्न उद्योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अपनी परियोजनाओं को आगे विकसित करते हैं और उन्हें अधिक बाजारोपयोगी बनाते हैं। एटीएल का लक्ष्य भविष्य के नवप्रवर्तकों के लिए आवश्यक कौशल सेट प्रदान करना है।

आज 35 से अधिक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में फैले देश के 700 से अधिक जिलों के 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स हैं। इनमें से 60 प्रतिशत एटीएल सरकारी स्कूलों में हैं और 75 लाख से अधिक छात्रों को कवर करते हैं जिन्होंने 12 लाख से अधिक नवाचार परियोजनाएं बनाई हैं।

अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी)

एआईएम 2017 से अटल इनक्यूबेशन सेंटर नामक इनक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना में सहायता कर रहा है ताकि मापनीय और टिकाऊ उद्यम बनने की दिशा में अग्रसर नूतन स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जा सके। एआईसी देश भर में मौजूद विश्व स्तरीय इनक्यूबेशन केन्द्र हैं जिनमें पूंजीगत संपत्ति और परिचालन सुविधाओं से युक्त उपयुक्त बुनियादी ढांचे के साथ-साथ स्टार्ट-अप

के मार्गदर्शन लिए क्षेत्र विशिष्ट सलाहकारों की उपलब्धता, व्यवसाय के लिए योजना बनाने में सहायता, प्रारंभिक पूंजी, उद्योग भागीदारों, प्रशिक्षणों और नवोन्मेषी स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक अन्य प्रासंगिक घटक शामिल हैं।

एआईएम का एआईसी कार्यक्रम क्रॉस-सेक्टोरल इनक्यूबेटर बनाता है और उनकी सहायता करता है। एआईसी को सरकारी और निजी एचईआई(उच्च शिक्षा संस्थानों) अनुसंधान संस्थान, कॉर्पोरेट निकायों आदि में संचालित किया गया है। एआईसी की स्थापना के पीछे विभिन्न क्षेत्रों में इनक्यूबेटर विकसित करने की परिकल्पना थी- आईआईटी और एनआईटी से इतर संस्थानों में जिनका पारंपरिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर की तुलना में बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हो। कपड़ा, डेयरी, कॉफी आदि के अछूते क्षेत्रों से लेकर समय की आवश्यकता वाले कृषि-तकनीक, शिक्षा-तकनीक, चिकित्सा-तकनीक, स्वच्छ-तकनीक आदि क्षेत्रों से लेकर अत्याधुनिक गतिशीलता, अंतरिक्ष-तकनीक, परमाणु-तकनीक तक को इनमें शामिल किया गया है।

एआईएम का उद्देश्य भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण करना है। लेकिन किसी संस्कृति का निर्माण एक दीर्घकालिक मिशन है जिसके लिए एक नवप्रवर्तक के जीवनचक्र में निरंतर और लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है और इसमें नवाचार की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को शामिल किया जाना चाहिए। एआईएम ने अपने दायित्व को पूरा करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है।

इसके परिणामस्वरूप सफल स्टार्ट-अप्स की स्थापना में वृद्धि हुई है और भविष्य के स्टार्ट-अप्स का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

अब तक, 70 एआईसी स्थापित किए जा चुके हैं, जिन्होंने 3000 से अधिक स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया है और 30,000 से अधिक रोज़गारों का सृजन किया है जिससे भारत आत्मनिर्भरता के स्वप्न साकार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया है।

अटल सामुदायिक नवाचार केन्द्र (एसीआईसी)

एआईएम एक ऐसे नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की परिकल्पना करता है जो भौगोलिक और भाषाई रूप से समावेशी हो। एसीआईसी को उन क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता का एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए तैयार किया गया है जो अभी तक नवाचार की बढ़ती संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं और जिनमें इनका पोषण करने के लिए तंत्र का अभाव है जैसे टियर 2/3 शहर, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र, उत्तर पूर्व, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र।

एसीआईसी का लक्ष्य जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों तक पहुंचना और उन्हें समुदाय के उत्थान और टिकाऊ परिवर्तन के लिए नए समाधानों पर विचार करने और डिजाइन करने के लिए बुनियादी ढांचे, वित्त और जानने-समझने संबंधी सहायता प्रदान करके न्यायसंगत अवसर प्रदान करना है। दुनिया में परिवर्तन लाने वाले किसी भी नवाचार के लिए समुदाय को शामिल करना महत्वपूर्ण है और एसीआईसी जमीनी स्तर पर नवाचार में क्रांति लाने के मिशन पर हैं।

एआईएम ने 10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 14 एसीआईसी स्थापित किए हैं जिन्होंने 50+ स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया है और कम्युनिटी इनोवेटर फ़ेलोशिप के तहत 20+ नवप्रवर्तकों के एक समूह की सहायता की है।

एआईएम ने 50+ स्टार्ट-अप्स को सीधे वित्त पोषित और समर्थन किया है और अन्य 100+ स्टार्ट-अप्स का चयन किया गया है।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी)

अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचारों की तलाश, चयन, सहायता और पोषण करने की एक राष्ट्रीय पहल है जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करती है। एएनआईसी कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य भारत के विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों - शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, ऊर्जा, आवागमन, अंतरिक्ष अनुप्रयोग इत्यादि में नवाचारों को प्रोत्साहित करना है।

स्टार्ट-अप्स को बाजार में नवाचारों को ले जाने से पहले आरंभिक चरण और व्यावसायीकरण चरण में उस परिस्थिति से गुजरना आवश्यक होता है जिसमें उसका कार्य तो आरम्भ हो जाता है पर राजस्व उत्पन्न नहीं होता है (वैली ऑफ़ डेथ)। एएनआईसी का उद्देश्य शुरुआती चरण के स्टार्ट-अप्स को परीक्षण, पायलटिंग और बाजार निर्माण के लिए संसाधनों तक पहुंच से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए एआईएम के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से वित्त पोषण और अन्य संबंधित सहायता के माध्यम से व्यावसायीकरण की इस वैली ऑफ़ डेथ अवस्था का निवारण करना है।

एआईएम ने 50+ स्टार्ट-अप्स को सीधे वित्त पोषित किया है और सहायता की है और अन्य 100+ स्टार्ट-अप्स को चुना गया है।

परिवर्तन के सलाहकार (एमओसी)

मेंटर इंडिया एआईएम द्वारा पूरे भारत में स्थापित 10,000+ अटल टिंकरिंग लैब्स में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए मार्गदर्शकों (परिवर्तन के सलाहकार) को चुनने की स्वैच्छिक पहल है जो युक्तिपूर्ण राष्ट्र-निर्माण में योगदान करती है।

आज देश भर में 6,000 से अधिक मेंटर युवा चिंतन को पोषित करने की एआईएम की आकांक्षा में मददगार सिद्ध हो रहे हैं। उद्योग और शिक्षा जगत के ये सलाहकार एक या अधिक ऐसी प्रयोगशालाओं में नियमित रूप से अपना समय देते हैं और छात्रों को डिज़ाइन और कम्प्यूटेशनल सोच, तर्कसंगत रूप से सोचने और विचारों के बीच तार्किक संबंध को समझने की क्षमता जैसे भविष्य के कौशल का अनुभव करने, सीखने और अभ्यास करने और कक्षाओं में जो उन्होंने सीखा है उसे व्यावहारिक स्थिति में लागू करने में सक्षम बनाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में एआईएम ने बहुत से युवा टिंकरर्स और स्टार्ट-अप्स की सहायता की है जो अपने प्रदेश और क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान खोजने के लिए उन्मुख हुए हैं।

नवीन हस्तक्षेपों की इस निरंतरता के माध्यम से एआईएम मानसिकता में परिवर्तन और एक सांस्कृतिक बदलाव ला रहा है जिससे भारत 'आत्मनिर्भरता' की ओर अग्रसर होगा।

केस स्टडी

क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हर दिन 'नो हॉर्न डे' हो तो माहौल कितना शांतिपूर्ण होगा?

कल्पना कीजिए कि पीक आवर्स में लाल बत्ती और ट्रैफिक जाम के बीच वाहन सड़क पर चल रहे होंगे लेकिन कानफाड़ू हॉर्न नहीं होंगे। हालांकि, सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं लेकिन नागरिकों ने इस दिशा में सीमित प्रयास किए हैं। परन्तु राजस्थान के एक 18 वर्षीय छात्र ने इस समस्या का समाधान निकालने का बीड़ा उठाया।

यह छात्र अन्वेषक जो अभी बीटेक की पढ़ाई कर रहा है ध्वनि प्रदूषण के समाधान खोजने पर काम करने के प्रति इतना संकल्पबद्ध था कि उसने इससे निपटने के लिए एक उपकरण बनाया। उन्होंने व्हीकल हॉर्न कंट्रोल असेंबली (वीएचसीए) पर काम किया जो कुछ क्षेत्रों में हॉर्न बजने को रोकता है और हॉर्न-निषिद्ध क्षेत्रों में इसकी तीव्रता को भी घटाता है। वीएचसीए एक अत्याधुनिक प्रणाली है जो वाहनों के हॉर्न से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को पूरी तरह से नियंत्रित करने में मदद करती है। यह नवाचार सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 11: टिकाऊ शहरों और समुदायों को लक्षित करता है। नवाचार पेटेंट कराया गया है और ऐसे समाधान प्रदान करता है जो लागत-कुशल और मापनीय हैं। ध्वनि प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को काफी हद तक कम करने के लिए ऑटोमोबाइल विनिर्माण

इकाइयों में लागू करने के लिए यह प्रणाली पोर्टेबल और किफायती है। यह कितना आश्चर्यजनक है?

शायद इससे भी दिलचस्प वह यात्रा है जिसने इस समाधान तक पहुंच बनायी। इस नवाचार का बीज अटल टिंकरिंग लैब में बोया गया था। स्कूल में एटीएल सत्र के दौरान उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने अपना प्रोटोटाइप विकसित करने पर काम किया। सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने की अपनी खोज में इस छात्र अन्वेषक ने एटीएल मैराथन 2017 में भाग लिया और शीर्ष स्थान प्राप्त किया जिसका वह पात्र था। उसने एआईसी के माध्यम से स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम (एसआईपी) हासिल किया। एसीआइसी आरआइएसइ, मोहाली द्वारा आयोजित एक आइडियाथॉन में भाग लेने के बाद उसका एसीआइसी आरआइएसइ में इन्कयूबेशन हुआ जहां उसने अपनी व्यावसायिक योजना बनाई।

यह संभवत: एआईएम के सतत हस्तक्षेपों से सहायता का साक्षात् उदाहरण है।

उसकी जिज्ञासा और कल्पनाशीलता एटीएल में उजागर हुई – यह एक ऐसी जगह है जहां युवा टिंकररों की विचार प्रक्रिया को 'स्वयं करें' के व्यवहारिक मॉडल के माध्यम से ढाला और आकार दिया जाता है। उसके विचार को एआईसी-केन्द्रों में एसआईपी के माध्यम से पोषित किया गया था जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय नवाचार और जुझारू उद्यमियों को बढ़ावा देना और सहायता करना है जो मापनीय और टिकाऊ उद्यमों का निर्माण करना चाहते हैं। उसे फिर एसीआईसी-केन्द्रों में इनक्यूबेट किया गया जो सक्षम बुनियादी ढांचा, इन्क्यूबेशन पूर्व सहायता और जमीनी स्तर पर नवाचार के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करता है और भारत के असेवित और वंचितों क्षेत्रों में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करता है। अंतत: देश के महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाले उसके स्टार्ट-अप को अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) के तहत अनुदान भी मिला।

एआईएम का दृष्टिकोण सामाजिक या सामुदायिक चुनौतियों के लिए बेहतर और उज्ज्वल समाधान बनाने के लिए पूरे भारत में नवप्रवर्तकों और उद्यमियों के जुनून को जगाना और प्रेरित करना है। नवाचार के विभिन्न स्तरों पर कुशल सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों की संकल्पना की गई है जिसमें स्वयं हितधारकों के माध्यम से विभिन्न पहलों के बीच जीवंत सहयोग को सक्षम करने की एक बड़ी परिकल्पना शामिल है।

निष्कर्ष

यह वास्तविक नवाचार जीवन यात्रा केवल एक अलग घटना नहीं है बल्कि एक विकासशील प्रक्रिया है जो हर गुजरते वर्ष के साथ तेजी से बढ़ रही है। अधिकाधिक नवप्रवर्तक एआईएम के नवाचार श्रृंखला का मार्ग अपना रहे हैं और इसे बड़ा रूप प्रदान कर रहे हैं,स्थायी उद्यमों का सृजन कर रहे हैं और राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।

साथ ही पिछले कुछ वर्षों में नवाचार को अपनाने में अधिक तेजी आई है और वह युक्तिपूर्ण हो गया है। भारत की विकास गाथा निर्णायक मोड़ पर है और वित्त वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ एक भली-भांति पोषित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का होना आवश्यक है।

भारत अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में तेजी से प्रगति कर रहा है। पिछले दशक में निरंतर प्रयासों से भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में 2022 में 40वें स्थान पर काबिज हो गया है जो 2018 में 57 वां था। भारत विश्व स्तर पर प्रभावशाली नवाचार प्रदान कर रहा है; यहां 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं और इसने दुनिया के सामने आधार, यूपीआई, ओएनडीसी और कई अन्य डिजिटल जन सामग्री का अंबार लगा दिया है।

हालांकि नवाचार महाशक्तियों – संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल, आदि की तुलना में प्रति लाख जनसंख्या पर स्टार्ट-अप्स की संख्या के मामले में देश अभी भी विकसित हो रहा है। इस वर्तमान संख्या के 9 गुना से अधिक होने की संभावना है। डीप-टेक क्षेत्र में बहुत काम किया जाना शेष है।

अतीतकाल में प्रकांड विद्वानों के कारण ही भारत दुनिया में अपना योगदान करने में सक्षम रहा है। लेकिन आज भारत अपने नागरिकों की लीक से हटकर सोचने की क्षमता और एआईएम जैसे मिशनों के संस्थागत समर्थन के साथ – इष्टतम लागत पर विघटनकारी प्रौद्योगिकियों (ऐसा नवाचार जो पुरानी तकनीक का विघटन कर वही कार्य नयी तकनीक के साथ करती हैं) की रचना कर रहा है और नवाचार के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। युवा भारतीयों और स्टार्ट-अप्स को ऐसे अवसर दिए गए हैं जैसे उनको पहले कभी नहीं मिले। पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए इन छोटे कदमों के माध्यम से भारत ने एक ऐसे नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में अपना मार्ग प्रशस्त किया है जो सहयोगात्मक, सक्रिय और समावेशी है। अब हमारा यह कर्तव्य है कि हम नए भारत की आर्थिक क्षमता को हासिल करने और नए भारत के प्रौद्योगिकी दशक का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सामूहिक रूप से 'सबका प्रयास' में शामिल हों। ❑

अन्य योगदानकर्ता लेखक हैं-

तन्वी मिश्रा, यंग प्रोफेशनल, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग।

अनमोल सहगल, कार्यक्रम कार्यकारी, आइडीइएक्स, डीआइओ, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।

भारत 2023

**भारत के प्रांतों, केंद्रशासित प्रदेशों,
भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा
नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की
आधिकारिक जानकारी देने वाला
वार्षिक संदर्भ ग्रंथ**

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260
ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए
कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में पधारें

@publicationsdivision @DPD_India @dpd_India

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

LIVE/ONLINE Classes Available
www.visionias.in

Heartiest Congratulations
to all candidates selected in CSE 2022

हिन्दी माध्यम में 40+ चयन

39 IN TOP 50 SELECTIONS IN CSE 2022
from various programs of VISIONIAS

– हिंदी माध्यम टॉपर –

1 AIR
ISHITA KISHORE

2 AIR
GARIMA LOHIA

3 AIR
UMA HARATHI N

66 AIR
KRITIKA MISHRA

YOU CAN BE NEXT

लाइव/ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाएं

कोई क्लास न छूटे
रिकार्डेड क्लासेस, मिनी टेस्ट, डेली असाइनमेंट और अध्ययन सामग्री के साथ पूर्णतः रिवीजन करें

MAINS 365
संपूर्ण वर्ष के करेंट अफेयर्स को सिर्फ 60 घंटों में कवर करती कक्षाओं से ऑनलाइन जुड़ें

11 जुलाई, 5 PM

लक्ष्य: मुख्य परीक्षा
मेंटरिंग कार्यक्रम 2023

LAKSHYA Mains Mentoring Programme 2023

- बेहतर उत्तर–लेखन कौशल का विकास
- प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन और फीडबैक
- समर्पित सहयोग और प्रेरणा
- अतिरिक्त मार्गदर्शन और सहयोग

प्रारम्भ: **5 जुलाई** (55 दिनों तक एक्सपर्ट्स से लगातार सहयोग)

प्रारम्भ: **18 जुलाई** (45 दिनों तक एक्सपर्ट्स से लगातार सहयोग)

दक्ष: मुख्य परीक्षा
मेंटरिंग कार्यक्रम 2024

- टारगेटेड रिवीजन और समेकन
- उन्नत उत्तर लेखन कौशल का विकास
- सतत प्रदर्शन मूल्यांकन और फीडबैक

4 जुलाई | 18 जुलाई

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन 2024
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा

UPSC के सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम का व्यापक कवरेज

DELHI: 21 जून, 1 PM | 25 जुलाई, 9 AM

LUCKNOW: 22 जून, 9 AM | **BHOPAL:** 8 अगस्त, 9 AM

JAIPUR: 3 जुलाई, 7:30 AM & 4 PM

अभ्यास ही सफलता की चाबी है
VisionIAS प्रारंभिक/मुख्य टेस्ट सीरीज हर 3 में से 2 सफल उम्मीदवारों द्वारा चुना गया
- सामान्य अध्ययन
- निबंध
- दर्शनशास्त्र

ऑफलाइन* 40+शहरों में

अभ्यास 2023
ऑल इंडिया GS मेन्स मॉक टेस्ट

PAPER DATE	ESSAY	GS-1 & GS-2	GS-3 & GS-4
	25 अगस्त	26 अगस्त	27 अगस्त

पंजीकरण करें: www.visionias.in/abhyaas

DELHI
- 1st Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6,1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
- Contact : 8468022022, 9019066066

JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI | PRAYAGRAJ | RANCHI | BHOPAL

YH-2418/2023

भारत की जी-20 अध्यक्षता

वैश्विक व्यवस्था में अग्रणी स्थान बनाने की चाहत रखने वाले देश के रूप में भारत जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्यसेवा और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों से संबंधित विश्व की अहम चुनौतियों को अपने नेतृत्व के माध्यम से सुलझाने के लिये गंभीर है। वह जी-20 की अपनी अध्यक्षता में एक ज्यादा न्यायसंगत विश्व के निर्माण के लिये प्रयासरत है। जी-20 शासन की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा और उनके समाधान के लिये विकसित और विकासशील देशों को एकजुट करने वाला एक अनूठा मंच है। भारत प्रमुख वैश्विक मसलों पर सहमति कायम कर विभाजन को प्रभावी ढंग से मिटा सकता है।

प्रो हर्ष वी पंत | उपाध्यक्ष, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, अध्ययन और विदेश नीति। ईमेल: harshpant@orfonline.org

भारत ने जी-20 की अध्यक्षता वैसे समय में संभाली जब विश्व में उथल-पुथल का माहौल था। लेकिन हमारे देश के लिये यह एक सुअवसर भी था। भारत की आर्थिक विकास गाथा परवान चढ़ रही थी। वह ब्रिटेन को पीछे छोड़ विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है। जी-20 विश्व के 80 प्रतिशत से ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), 75 प्रतिशत व्यापार और 60 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। उसके लिये यह अनेक चुनौतियों के बीच अपनी प्रासंगिकता को रेखांकित करने का समय है। अनिश्चित वैश्विक परिवेश और नयी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की शुरुआत के बीच भारत की विश्वसनीयता अपने सर्वोच्च स्तर पर है। उदीयमान आर्थिक शक्ति होने के साथ ही वह वैश्विक बहुपक्षवाद पर अपनी प्रतिबद्धता के जरिये कानून के शासन तथा विश्व शांति और सुरक्षा के संवर्द्धन के लिये कृतसंकल्प है। वैश्विक जनकल्याण की उसकी क्षमता का विकास हो रहा है। भारत कोविड-19 की वैश्विक महामारी के

उफान पर होने के समय चिकित्सा सामग्री और टीके मुहैया कराने में सबसे आगे रहा। इस तरह उसने ऐसे गंभीर संकट के दौरान विश्व की एकजुटता सुनिश्चित की।

दुनिया लगातार ज्यादा विभाजित होती जा रही है। मौजूदा शक्तियों का ध्यान सिर्फ अपनी तरफ है और संशोधनवादी ताकतें खुद को मजबूत कर रही हैं। ऐसे में भारत ने जी-20 की अपनी अध्यक्षता में विकासशील राष्ट्रों को वैश्विक चर्चाओं के केन्द्र में लाने की कोशिश की है। वैश्विक व्यवस्था संक्रमण काल से गुजर रही है। शक्ति संतुलन परिवर्तनशील है और नियामक बदलाव ज्यादा स्पष्ट हो रहे हैं। दूसरे महायुद्ध के बाद की व्यवस्था सही मायनों में खत्म हो चुकी है। इससे पैदा खालीपन की वजह से चारों तरफ उथल-पुथल है। बड़ी ताकतें आत्मकेंद्रित हैं। वे अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को नजरंदाज कर अंदरूनी मसलों से निपटने में लगी हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये अपनी रणनीति पर फिर से सोचने की जरूरत है। कोविड-19 के प्रकोप ने इस रुझान को तेज कर दिया है। इसने विश्व को बुनियादी विभाजन रेखा के प्रति ज्यादा जागरूक बना दिया। दुनिया पहले तो अपने अंदर सिमटने लगी और फिर संयोजन और वियोजन के नये मॉडल सामने आये। पुराने प्रतिमान अस्वीकार्य हो चुके हैं और नये प्रतिमानों के बारे में दुनिया में अब तक सहमति नहीं बनी। वैश्विक अव्यवस्था एक हकीकत है जिसका अनुमान लगाने में अक्षमता की वजह से नीतिगत प्रतिक्रिया भी अपर्याप्त रही। बहुपक्षीय संस्थाओं में विकासशील देशों और उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के व्यापक प्रतिनिधित्व के अभाव में बहुपक्षवाद का संकट ज्यादा गंभीर हो गया है।

आर्थिक वैश्वीकरण भी दबाव में है। देश आर्थिक सहयोग करने से पहले राजनीतिक वफादारी की परीक्षा चाहते हैं। पहले नारा था- आओ, व्यापार करें और दोस्त बनें। इसकी जगह अब का नारा है- ''आओ, दोस्तों के बीच व्यापार करें।'' फ्रांसिस फुकुयामा की 'इतिहास के समापन' की आशावादिता ने दम तोड़ दिया और अतीत पूरी शिद्दत से लौट आया। राष्ट्रों ने आपसी दूरी बढ़ाने और जोखिम मिटाने का रास्ता अपनाया जिससे विवैश्वीकरण विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरा। एक समय आर्थिक अंतरनिर्भरता को वैश्विक जनकल्याण के रूप में देखा जाता था। लेकिन इसने एक चुनौती के तौर पर उभरते हुए ऐसी कमजोरियां पैदा कीं जिसका दोहन किया जा सकता था। राष्ट्रों ने अपने व्यापारिक साझीदारों के विविधीकरण की ओर तेजी से बढ़ना शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में उभरा।

इस स्थिति में हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारत ने जी-20 की अपनी अध्यक्षता के लिये वसुधैव कुटुंबकम को थीम के रूप में चुना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 के 2023 के लोगो का अनावरण करते हुए कहा कि मौजूदा समय में विश्व टकराव, सदी में एक बार आने वाली वैश्विक महामारी के दुष्प्रभावों और आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने इस स्थिति में वैश्विक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

भारत ने साल भर की अपनी अध्यक्षता के दौरान विभिन्न कदमों के जरिये वैश्विक नेतृत्व का अपना दावा प्रदर्शित करने की गहन कोशिश की है। इस प्रयास का एक पहलू इसकी सहभागी प्रकृति में दिखायी देता है। प्रधानमंत्री ने 9 जनवरी 2023 को इंदौर में सत्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में जो भाषण दिया उसमें सहभागी कूटनीति पर जोर स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि भारत को जी-20 की

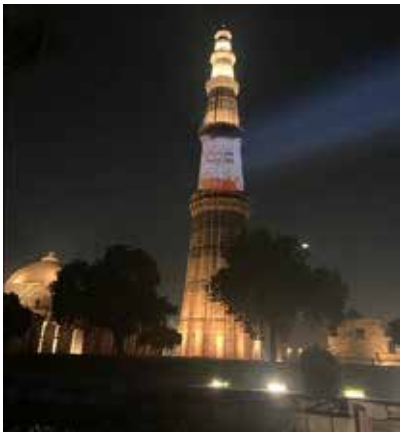

अपनी अध्यक्षता को सिर्फ कूटनीतिक ही नहीं, बल्कि जन भागीदारी की ऐतिहासिक घटना बनाना है। विदेश मंत्रालय ने भी ऐसी ही भावना व्यक्त करते हुए जी-20 को वास्तविकता में जनसमूह बनाने के भारत के लक्ष्य को दोहराया। भारत ने जी-20 में जन भागीदारी की अपनी परिकल्पना के तहत विभिन्न नागरिक गतिविधियों का आयोजन किया है। उसने 50 शहरों में 32 कार्यशाखाओं में 200 से ज्यादा बैठकों की मेजबानी की है। इस सहभागी कूटनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रांतों और क्षेत्रों को प्राथमिकता देना तथा उन संस्कृतियों का प्रदर्शन करना है जिन पर पहले पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

इक्कीसवीं सदी की जटिल चुनौतियों की वजह से वैश्विक सहयोग के पारंपरिक मॉडल तनाव में हैं। वैश्विक व्यवस्था में अग्रणी स्थान बनाने की चाहत रखने वाले देश के रूप में भारत जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्यसेवा और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों से संबंधित विश्व की अहम चुनौतियों को अपने नेतृत्व के माध्यम से सुलझाने के लिये गंभीर है। भारत विकासशील देशों की चिंताओं को ऐतिहासिक रूप से बहुपक्षीय मंचों पर उठाता रहा है। जी-20 की अध्यक्षता ने भारत को वैश्विक मंच पर अपने बढ़ते रसूख को प्रदर्शित करने का एक नया जरिया प्रदान किया है। उसने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, उद्यमिता और नवोन्मेष, जलवायु न्याय तथा किफायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच जैसे उदीयमान

अर्थव्यवस्थाओं के लिये महत्वपूर्ण मसलों को जोरशोर से उठाया है।

लेकिन भारत की जी-20 की अध्यक्षता चुनौतियों से मुक्त नहीं है। समूह की बड़ी ताकतों के बीच बढ़ते तनावों और बहुपक्षीय संस्थाओं की विश्वसनीयता के संकट ने राष्ट्रों को एकजुट करना ज्यादा मुश्किल बना दिया है। भारत को उम्मीद है कि वह विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर प्रमुख हितधारकों को एकजुट करने और बहुपक्षवाद में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की विश्वास बहाली में कामयाब होगा। यह निश्चित तौर पर मुश्किल काम है। लेकिन भारत के कूटनीतिक प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि उसकी जी-20 की अध्यक्षता वैश्विक शासन पर विमर्श को आगे बढ़ा सके। यह कहना सर्वथा उचित होगा कि भारत की जी-20 की अध्यक्षता ने अव्यवस्था और अवरोध की ओर बढ़ रही एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को कुछ हद तक व्यवस्थित किया है।

मौजूदा समय में विश्व भर के राष्ट्र निजी हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आतंकवाद, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी बहुराष्ट्रीय चुनौतियां ज्यादा सहयोग की मांग करती हैं। लेकिन वे स्वार्थ पर आधारित अस्थाई गठजोड़ करने में लगे हैं। मगर भारत ने बहुपक्षीय मंचों की चुनौतियों से निपटने की क्षमता में दुनिया के विश्वास को बहाल करने का प्रयास किया है। जी-20 विकसित और विकासशील देशों को एक जगह लाने वाला एक दिलचस्प मंच है। कोई भी दूसरा मंच इन दोनों समूहों को इस तरह एक साथ नहीं लाता। जी-20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत का लक्ष्य विश्व को एकजुटता की बेहतर समझ की ओर ले जाने का है। भारत का बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र होना विभिन्न हितधारकों को वैश्विक चुनौतियों के बारे में सोचने और उनसे मुकाबले के लिये एकजुट होने पर प्रेरित करने में सहायक हो सकता है। 75 साल का भारत, वैश्विक मंच पर एक महत्वाकांक्षी भूमिका निभाने के लिये अच्छी स्थिति में है। जी-20 की अध्यक्षता ने एक भरोसेमंद वैश्विक वार्ताकार के रूप में उसकी विश्वसनीयता को पुष्ट किया है। ❑

सत्यमेव जयते

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ई-रिसोर्स एग्रीगेटर (ईआरए)

के इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित

सरकार के प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान से जुड़ने और उसके ई-प्रकाशनों के विक्रय का सुनहरा अवसर

विशेषताएं :-

- प्रकाशन विभाग की लोकप्रिय ई-पुस्तकें और ई-पत्रिकाएं उपलब्ध कराने का अवसर।
- प्राप्त राजस्व में 30% की निश्चित हिस्सेदारी।
- किसी निवेश की आवश्यकता नहीं।
- मात्र 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क।

अधिक जानकारी के लिए देखें –
www.publicationsdivision.nic.in

संपर्क करें
फोन : 011 24365609
ईमेल : businesswng@gmail.com
पता : व्यापार स्कंध, कमरा संख्या–758, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

भारत में कृषि वैश्विक शक्ति बनने की ओर

भूख और गरीबी से जूझते हुए, देश ने विकास के लिए अपनी पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) का मसौदा तैयार किया, जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने और भूख को खत्म करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। परिणामस्वरूप, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार का ध्यान कृषि से औद्योगिक विकास की ओर स्थानांतरित करने के लिए बढ़ावा मिला। आज, भारत कृषि के वैश्विक क्षेत्र में कई सराहनीय स्थितियों से गुजर चुका है। उल्लेखनीय है कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन इसकी जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो गया है। आत्मनिर्भरता से उठकर भारतीय कृषि अब कृषि की वैश्विक शक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रही है।

डॉ जगदीप सक्सेना
पूर्व मुख्य संपादक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
ईमेल: jagdeepsaxena@yahoo.com

पिछले 75 वर्षों में, भारतीय कृषि ने परिवर्तन की एक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण सफलता की कहानी लिखी है। आज़ादी के समय खाद्य वस्तुओं की भारी कमी से शुरुआत करते हुए, अब हम कृषि-निर्यात की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ एक गौरवान्वित खाद्य अधिशेष राष्ट्र हैं। पीछे मुड़कर देखें, तो भारत को विनाशकारी बंगाल अकाल (वर्ष 1943-44) की छाया में आज़ादी मिली, जिसमें लगभग 30 लाख लोग कुपोषण या बीमारी के कारण मारे गए। भारत की जनसंख्या तीव्र खाद्यान्न की कमी, लगातार सूखे और अकाल का सामना कर रही थी और व्यापक कुपोषण से पीड़ित थी। हालांकि लगभग 85 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती थी और अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करती थी, लेकिन देश में खाद्यान्न की बेहद कमी थी, जिसका मुख्य कारण खेती के प्रति अंग्रेज़ सरकार की प्रतिकूल नीतियां थीं। वर्ष 1950-51 के दौरान, भारत में केवल 50.82 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जो बढ़ती आबादी को पर्याप्त रूप से खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं से खाद्यान्न मांगने के लिए भारत मजबूर हुआ। वर्ष 1948, 1962 और 1965 में लगातार युद्धों के साथ-साथ बार-बार पड़ने वाले सूखे ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। इस गंभीर परिदृश्य ने देश को एक अप्रत्याशित 'जहाज़ से मुंह तक' के अस्तित्व में धकेल दिया और भारत को 'बेग्गिंग बाउल' या 'भीख का कटोरा' राष्ट्र के रूप में भी बदनाम किया। लाखों भारतीयों को भूख से बचाने के लिए

संयुक्त राज्य अमेरिका ने PL-480 योजना के तहत बड़ी मात्रा में गेहूं दान किया। लेकिन जल्द ही, अमेरिका के साथ तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कारण यह बहुत निचले स्तर पर आ गया। इस अवधि के दौरान, विलियम और पॉल पैडॉक की एक प्रसिद्ध पुस्तक, फैमिन 1975 में भविष्यवाणी की गई थी कि आने वाले वर्षों में लाखों भारतीय भूख से मर जाएंगे।

परिवर्तन की कहानियां

भूख और गरीबी से जूझते हुए देश ने विकास के लिए अपनी पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) का मसौदा तैयार किया, जिसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पादन बढ़ाने और भूख मिटाने को दी गयी। कुल योजना निधि का लगभग एक-तिहाई हिस्सा कृषि के लिए आवंटित किया गया था, जिससे देश में सिंचाई सुविधाओं और उर्वरक उत्पादन में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1956-61 तक) में अपना ध्यान कृषि से हटाकर औद्योगिक विकास की ओर केंद्रित करना पड़ा। कृषि के लिए आवंटन में भी 20 प्रतिशत की कटौती की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1961-66 तक) के दौरान, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राथमिकताओं में से एक थी, लेकिन यह चीनी आक्रामकता (वर्ष 1962), भारत-पाक युद्ध (वर्ष 1965), और वर्ष 1965-66 के दौरान गंभीर और लंबे समय तक सूखा पड़ने से बुरी तरह विफल रही। इससे देश में भारी खाद्य संकट पैदा हो गया, जिसके चलते लोगों से सप्ताह में एक बार उपवास रखने की अपील की गई। लोगों को कंद और मोटे अनाज को शामिल करके अपने भोजन की टोकरी को व्यापक बनाने की भी सलाह दी गई।

इस बीच, मेक्सिको में, एक वैज्ञानिक, डॉ नॉर्मन बोरलॉग ने, गेहूं की अनोखी किस्में विकसित करके सफलता हासिल की, जो अर्ध-बौनी, अधिक उपज देने वाली, रोग-प्रतिरोधी, तेजी से बढ़ने वाली और उर्वरकों के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियाशील थीं। भारत सरकार ने वर्ष 1966 में 18,000 मीट्रिक टन नई गेहूं की किस्मों के आयात की अनुमति दी। ये बीज दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में किसानों को 5 किलोग्राम के पैक में वितरित किए गए; और साथ ही, डॉ एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में किसानों के खेतों में 1000 से अधिक राष्ट्रीय प्रदर्शन आयोजित किए गए। किसान पहले के एक टन प्रति हेक्टेयर की तुलना में प्रति हेक्टेयर 4-5 टन की सफलतापूर्वक पैदावार कर सके। किसानों ने नई किस्मों को दिल से अपनाया। वर्ष 1968 में, देश में 17 मिलियन टन गेहूं की बंपर फसल हुई, जो वर्ष 1966 के 11 मिलियन टन से अधिक थी। यह दुनिया में अब तक दर्ज गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ी छलांग थी। इसे 'हरित क्रांति' कहा गया। चावल के मामले में भी इसका पालन किया गया और इसके बाद गन्ना, कपास और फलों और सब्जियों जैसी अन्य फसलों के उत्पादन में उछाल आया। हरित क्रांति ने आत्मनिर्भरता की नींव रखी और अब हम अधिशेष खाद्यान्न वाले देश और शुद्ध कृषि निर्यातक के रूप में आगे बढ़ गए हैं। इस अद्वितीय विशिष्टता को प्राप्त करने के लिए, वैज्ञानिक कौशल, राजनीतिक इच्छाशक्ति और किसानों की मेहनत सभी ने एक ही मंच पर सहक्रियात्मक रूप से काम किया।

भारत ने खेतों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा संचालित खेती के एक नए युग की शुरुआत की। इसके साथ ही, सरकार ने विभिन्न विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को नीति समर्थन, धन आवंटन और सब्सिडी प्रदान की। परिणामस्वरूप, आज कृषि के वैश्विक क्षेत्र में भारत का स्थान बहुत ही ऊंचा और सराहनीय है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और चावल के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। गेहूं के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में, वर्ष 2020 में वैश्विक गेहूं उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 14.14 प्रतिशत थी। भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ने के साथ, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। दूसरे अग्रिम अनुमान (वर्ष 2022-2023) के अनुसार, देश में खाद्यान्न का उत्पादन 323.5 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 की तुलना में 7.9 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 342.33 मिलियन मीट्रिक टन बागवानी उत्पादन का अनुमान है, जो वर्ष 2020-21 के उत्पादन से 7.73 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान गन्ने का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 468.8 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो औसत गन्ना उत्पादन से 155.3 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है। घाटे की फसल होने के कारण, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तिलहन और ऑयल पाम पर राष्ट्रीय

मिशन शुरू करके तिलहन पर विशेष जोर दिया गया। नवीनतम फसल उत्पादन तकनीकों को शुरू करने और नए क्षेत्रों में अपने खेतों का विस्तार करके तिलहन उत्पादन में सफलता हासिल की गई। परिणामस्वरूप, तिलहन उत्पादन वर्ष 1985-86 में 108.30 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 400 लाख मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 तक उत्पादन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही। रबी 2020-21 के दौरान शुरू किए गए विशेष सरसों कार्यक्रम का सबसे शानदार परिणाम आया। सरसों के उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 91.24 से बढ़कर 128.18 लाख टन हो गई, और उत्पादकता में 11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो 1331 से 1447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। रेपसीड और सरसों का क्षेत्रफल 29 प्रतिशत बढ़ा, जो वर्ष 2019-20 में 68.56 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2020-23 में 88.58 लाख हेक्टेयर हो गया। तिलहन उत्पादन में भारी उछाल को भारत में कृषि के इतिहास में अक्सर 'पीली क्रांति' के रूप में जाना जाता है।

उल्लेखनीय है कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन इसकी जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो गया है। वर्ष 1951 से 2022 तक, खाद्यान्न उत्पादन में प्रति वर्ष 2.61 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर 1.95 प्रतिशत रही। जबकि अनाज का उत्पादन लगभग सात गुना बढ़ गया है, इसी अवधि के दौरान दालों का उत्पादन 3.25 गुना बढ़ा है। खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता वर्ष 1951 में 395 ग्राम से बढ़कर वर्ष 2022 में 514.5 ग्राम हो गई है। बागवानी फसलों (60 प्रतिशत सब्जियां, 31 प्रतिशत ताजे फल) का उत्पादन हाल ही में खाद्यान्न के उत्पादन से आगे निकल गया है, और देश की पोषण सुरक्षा को एक मजबूत योगदान दे रहा है। खाद्य अधिशेष राष्ट्र होने के नाते, सरकार किसानों और 'कृषि उद्यमियों' के हित में कृषि-निर्यात को बढ़ावा दे रही है। परिणामस्वरूप, कृषि और संबद्ध निर्यात वर्ष 2020-21 में 41.86 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 50.24 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है, यानी लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि। 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष' (2023) मनाते हुए, भारत मोटा अनाज के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केन्द्र बनने के लिए तैयार है, जिसे हाल ही में 'श्री अन्न' नाम दिया गया है। इसकी विभिन्न प्रचार रणनीतियों ने वर्ष 2022-23 में इसका उत्पादन 159 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया है, जबकि सरकार ने वर्ष 2023-24 में 170 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कोविड-19 महामारी के दौरान, भारतीय कृषि ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे देश महामारी प्रभावित गरीब देशों को भोजन की आपूर्ति करने में सक्षम हुआ।

विभिन्न क्रांतियों की बौछार

हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बीच कई समानताएं हैं, दोनों ने क्रमशः खाद्यान्न और दूध में आत्मनिर्भरता लाने में मौलिक भूमिका निभाई है। खाद्यान्नों की तरह, आज़ादी के समय भारत दूध की उपलब्धता से भी जूझ रहा था, जिसका उत्पादन उस समय मात्र 17 मिलियन मीट्रिक टन था। जैसे-जैसे हमारी आबादी बढ़ी, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में गिरावट आई, जिससे देश दूध संकट में और फंस गया। सरकार ने मेट्रो शहरों में डेयरी योजनाएं स्थापित की थीं, लेकिन उनकी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा दूध पाउडर के वाणिज्यिक आयात से पूरा किया गया था। हालांकि, सरदार वल्लभभाई पटेल की सलाह पर स्थापित एक सफल दुग्ध सहकारी समिति आणंद, गुजरात में काम कर रही थी। वर्ष 1964 में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख डॉ वर्गीस कुरियन थे। एनडीडीबी ने भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्ष 1970 के दशक के दौरान एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, ऑपरेशन फ्लड (ओएफ) शुरू किया। ओएफ कार्यक्रम ने दूध के संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ ग्राम-स्तरीय दुग्ध सहकारी समितियों का एक नेटवर्क बनाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इसने आधुनिक तरल दूध प्रसंस्करण संयंत्रों की शुरुआत की और दूध को अधिशेष से कमी वाले क्षेत्रों में ले जाने के लिए एक राष्ट्रीय दूध ग्रिड बनाया। आंदोलन ने जल्द ही गति पकड़ ली और बहुत तेजी से दूध उत्पादन संतोषजनक स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 1976 तक, दूध का नियमित वाणिज्यिक आयात बंद हो गया था। तब से, भारत ने दूध उत्पादन के मामले में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

आत्मनिर्भरता के अलावा, भारत वर्ष 2021-22 में लगभग 222 मिलियन टन के कुल उत्पादन के साथ एक दशक से अधिक समय से दूध उत्पादन में वैश्विक नेता है। यह दुनिया भर में उत्पादित कुल दूध (931 मिलियन टन) का लगभग 24 प्रतिशत बनाता है, जबकि वर्ष 1973 में यह विश्व दूध उत्पादन का केवल छह प्रतिशत था। वर्तमान में, भारत का दूध उत्पादन छह प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक विकास दर करीब दो फीसदी है। दुनिया भर में दूध की प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता 308 ग्राम है, जबकि भारत के लिए वर्ष 2022 में यह 444 ग्राम था। इस अद्भुत सफलता, जिसे अक्सर 'श्वेत क्रांति' के रूप में जाना जाता है, ने डेयरी क्षेत्र को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक आर्थिक रूप से प्रासंगिक उद्यम में बदल दिया है। लगभग 80 मिलियन परिवारों को डेयरी क्षेत्र से सीधे रोजगार मिल रहा है, जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान और भूमिहीन परिवार हैं। भारत में दूध उत्पादन वर्ष 2047 में 628 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि दूध और डेयरी उत्पादों की मांग भी 517 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे निर्यात के लिए 111 मिलियन टन दूध अधिशेष रह जाएगा।

इंद्रधनुष के एक और रंग की ओर बढ़ते हुए, 'नीली क्रांति' स्वतंत्रता के बाद प्राप्त मत्स्य उत्पादन में वृद्धि का प्रतीक है। लगातार प्रयासों और प्रचार नीतियों के कारण, भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक उत्पादन में 7.58 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 1950-51 में, कुल मछली उत्पादन 0.752 मिलियन टन था, जो अब 4.42 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर के साथ 16.3 मिलियन टन (2021-22) तक पहुंच गया है। वर्तमान में, भारत दुनिया का

एक प्रमुख समुद्री आहार निर्यातक देश भी है। मत्स्य पालन क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग 16 मिलियन मछुआरों और मछली किसानों को आजीविका प्रदान करता है। भारत सरकार ने पांच वर्षों की अवधि (वर्ष 2016-16 से वर्ष 2019-20) के लिए मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन - 'नीली क्रांति' - नमक एक उल्लेखनीय योजना लागू की, जो मुख्य रूप से देश के अंतर्देशीय और समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। दुनिया में अंडे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर देश ने पोल्ट्री क्षेत्र में एक और क्रांति देखी है। इसे अक्सर 'रजत क्रांति' के रूप में जाना जाता है। देश वर्तमान में 1,29,600 मिलियन अंडे (वर्ष 2021-22) का उत्पादन कर रहा है, जबकि वर्ष 1950-51 के दौरान यह 1,832 मिलियन था।

आगे बढ़ने का रास्ता

कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, बिगड़ते प्राकृतिक संसाधनों, कम उर्वरता और कम उत्पादकता और गुणवत्तापूर्ण उपज की बढ़ती मांग के रूप में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी चुनौतियों से निपटने और भारतीय कृषि को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय मंच पर सतत कृषि मिशन, कृषि-तकनीकी अवसंरचना निधि, परम्परागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी पहल की हैं। इस तरह की पहल उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के समर्थन और बाजार संबंधों के साथ खेतों और खेतों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा दे रही है। इस तरह की पहल उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के समर्थन और बाजार संबंधों के साथ खेतों और खेतों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा दे रही है। जबकि प्राकृतिक खेती नया मंत्र है, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, सटीक कृषि और आईटी अनुप्रयोग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां भी आधुनिक कृषि में अपना रास्ता तलाश रही हैं। हाल की घटना के रूप में, कृषि-स्टार्टअप डिजिटल उपकरणों और नवाचारों को नियोजित करके, ज्यादातर वास्तविक समय के आधार पर किसानों को कृषि समाधान प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न डिजिटल पहल भी किसानों को दक्षता बढ़ाने और खेती की लागत कम करने में सहायता कर रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए, सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कई पहल की हैं। प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता से लेकर फसल बीमा और संस्थागत ऋण तक, किसान आय बढ़ाने वाली योजनाओं के मूल में हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईएनएएम) पहल के तहत, देश भर के बाजार अब किसानों को उनकी उपज के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बना रहे हैं। आत्मनिर्भरता से उठकर भारतीय कृषि अब कृषि की वैश्विक शक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रही है। ❑

मीठी क्रांति

शहद उत्पादन में धूम

मीठी क्रांति या स्वीट रिवोल्यूशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है। मधुमक्खी पालन एक कम निवेश और अत्यधिक कुशल उद्यम मॉडल है, जिसमें प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरा है। मीठी क्रांति को बूस्टर शॉट प्रदान करने और मिशन मोड में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया।

डॉ शैलेश कुमार मिश्र | निदेशक (विस्तार), विस्तार निदेशालय, कृषि भवन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ईमेल: shaileshk.mishra29@gov.in

डॉ धीरज कुमार तिवारी | वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र (आईसीएआर), उन्नाव। ईमेल: dk9hau@gmail.com

भारत ने कृषि आधारित सहायक व्यवसाय के रूप में मधुमक्खी पालन की अनुकरणीय तीव्र गति से वृद्धि देखी है। भारत में मधुमक्खी पालन पहाड़ों, तलहटी, जंगलों, कृषि भूमि, मैंग्रोव वनों आदि में किया जाता है। मधुमक्खी पालन में शामिल तकनीक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। मुख्य फसल एपिस डोरस्टा, एपिस सेराना और एपिस मेलिफेरा से होती है। एपिस मेलिफ़ेरा को भारत के उत्तरी और पूर्वी मैदानी इलाकों में सफलतापूर्वक पेश किया गया था। देश में विशिष्ट स्थानों के लिए प्रबंधन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम विकसित हुए हैं। वनस्पति और जलवायु की बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में जोर दिया गया है। प्रत्येक कृषि-जलवायु क्षेत्र के लिए मौसमी प्रबंधन के अलावा, कॉलोनी उत्पादकता और शहद, मोम, पराग, रॉयल जेली, आदि के उत्पादन में सुधार के लिए उपयुक्त प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है। आज, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण, टिकाऊ और अभिन्न कृषि गतिविधि है क्योंकि यह पोषण, आर्थिक और पारिस्थितिक सुरक्षा और संतुलन प्रदान करता है। कृषि-जलवायु परिस्थितियों, विविध वनस्पतियों, फसल के बदलते कृषि/बागवानी पैटर्न, मधुमक्खियों के प्रकार, प्रबंधन प्रथाओं आदि का ज्ञान देश में मधुमक्खी पालन उद्योग को

बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एपिकल्चर या मधुमक्खी पालन शहद और अन्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रखने और प्रबंधित करने की प्रथा है। शहद प्राकृतिक रूप से मिठास प्रदान करने वाला स्वीटनर है जिसके कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ हैं। उत्पाद का उपयोग अन्य उत्पादों, जैसे मोम, रॉयल जेली, प्रोपोलिस और पराग के निर्माण के लिए भी किया जाता है। एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन के घटकों में मधुमक्खी कालोनियां, मधुमक्खी पालक, मधुमक्खी पालन उपकरण और मधुमक्खी कालोनियों से उत्पादित उत्पाद शामिल हैं। मधुमक्खियां फसलों और फलों को उगाने के लिए आवश्यक परागण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि के अन्य रूपों की तुलना में एपिकल्चर या मधुमक्खी पालन के लिए कम भूमि और पानी की आवश्यकता होती है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है। मधुमक्खियों को कृत्रिम छत्ते में रखा जाता है, जहां वे मधुमक्खियों के लिए छत्ते में पर्याप्त शहद रखने के बाद, अतिरिक्त शहद की जांच और निष्कर्षण के लिए मधुमक्खी पालक की आसान पहुंच के भीतर आराम से रहती हैं। शहद मधुमक्खियों का एक उत्पाद है, जो फूलों से चीनी युक्त रस इकट्ठा करती हैं। शहद को छत्ते से निकालने के बाद जितनी जल्दी हो सके संसाधित किया जाना चाहिए। शहद प्रसंस्करण एक कठिन कार्य है, जिसमें सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए समय और धीरज रखने की आवश्यकता होती है। प्रसंस्करण के सभी चरणों में चींटियों और उड़ने वाले कीड़ों द्वारा संदूषण से बचने के लिए सावधानीपूर्वक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। कई लघु उद्योग मधुमक्खियों और मधुमक्खी उत्पादों पर निर्भर हैं।

मधुमक्खी पालन का इतिहास

आदिम लोग खोखले पेड़ों की गुहाओं, चट्टानों और पारंपरिक मिट्टी के घरों में पाई जाने वाली मधुमक्खी कालोनियों को लूटते थे और कुछ जनजातियां अभी भी इसका पालन कर रही हैं। 16वीं शताब्दी तक मधुमक्खी पालन में कोई विकास नहीं हुआ था। जब मनुष्य ने प्रकृति में पाई जाने वाली कॉलोनियों को संरक्षण देना शुरू किया, तभी उचित मधुमक्खी पालन शुरू हुआ। ऐसा बताया गया है कि मधुमक्खियों को लकड़ी के छत्ते में रखने का विचार गिरे हुए खोखले पेड़ों में मधुमक्खियों द्वारा घोंसला बनाते देख आया है। आधुनिक मधुमक्खी पालन का विकास 1500 और 1851 के बीच हुआ, जब विभिन्न प्रकार के छत्ते में मधुमक्खियों को पालतू बनाने के कई प्रयास किए गए, लेकिन सफल नहीं हुए क्योंकि मधुमक्खियां अपने छत्तों को एक साथ और साथ ही छत्ते की दीवारों पर भी जोड़ लेती हैं और शहद के लिए आवश्यक छत्तों को काटना पड़ता था। 1851 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एलएल लैंगस्ट्रॉथ द्वारा मधुमक्खी अंतरिक्ष के सिद्धांत की खोज के परिणामस्वरूप पहला वास्तविक चलनशील फ्रेम हाइव प्राप्त हुआ। इस खोज के बाद कॉम्ब फाउंडेशन मिल, हनी एक्स्ट्राक्टर, स्मोकर इत्यादि जैसे नए आविष्कार हुए, जिससे आधुनिक मधुमक्खी पालन के विकास में मदद मिली, जो आज देखा जा रहा है।

भारत में मधुमक्खी पालन

भारत में, मधुमक्खियों को चलनशील फ्रेम छत्ते में रखने का पहला प्रयास 1882 में बंगाल में और फिर 1883-84 में पंजाब में किया गया था। दक्षिण भारत में, 1911-1917 के दौरान कई मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित किया गया था, और बी-स्पेस के सिद्धांत के आधार पर स्वदेशी मधुमक्खी एपिसेराना (एशियाई मधु मक्खी) के लिए एक छत्ता तैयार किया गया था। मधुमक्खी पालन 1917 में त्रावणकोर राज्य (अब कोचीन) में और 1925 में मैसूर में भी शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश में, स्वदेशी शहद मधुमक्खी ए. सेराना के साथ आधुनिक मधुमक्खी पालन 1934 में कुल्लू में और 1936 में कांगड़ा में शुरू हुआ। विदेशी मधुमक्खी ए. मेलिफ़ेरा को भारत में पहली बार 1962 में नगरोटा बगवान (तब पंजाब राज्य और अब हिमाचल प्रदेश में) में सफलतापूर्वक पेश किया गया था क्योंकि इस मधुमक्खी में अधिक शहद पैदा करने की क्षमता है। वर्तमान में, आधुनिक मधुमक्खी पालन में छत्ता मधुमक्खी की दोनों प्रजातियों का उपयोग किया जा रहा है, और जंगली मधुमक्खियों, ए. डोरसाटा और ए. फ्लोरिया से भी बहुत सारा शहद एकत्र किया जा रहा है। भारत मधुमक्खियों की सभी चार प्रजातियों से सालाना लगभग 70000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन करता है।

शहद पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसमें जीवाणुरोधी गुण हैं, और संतुलित आहार के हिस्से के रूप में मधुमेह प्रबंधन में भूमिका निभा सकता है। उत्पाद के कई

संभावित स्वास्थ्य लाभ भी हैं और यह कई घरेलू उपचारों और वैकल्पिक चिकित्सा उपचारों में भूमिका निभाता है। स्वादिष्ट होने के अलावा, अन्य तरीकों से भी कच्चा शहद सभी के लिए अच्छा है। मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण टिकाऊ और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल गतिविधि है; इसमें वानिकी, सामाजिक वानिकी और कृषि सहायक गतिविधियों का एकीकरण शामिल है क्योंकि यह रोजगार और आय प्रदान करते हुए पोषण, आर्थिक और पारिस्थितिक संतुलन प्रदान करता है। शहद उत्पादन एक स्थायी आय स्रोत प्रदान करता है, जिसमें केवल कम लागत वाले निवेश और प्राकृतिक संसाधन आधार का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। शहद सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मिठास में से एक है, जिसके अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ हैं। इसके अलावा, इसका उपयोग दुनिया भर में कई संस्कृतियों द्वारा कई पारंपरिक दवाओं, खासकर आयुर्वेद के आधार के रूप में किया जाता है।

मधुमक्खी पालन के विकास को सुविधाजनक बनाने वाले प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, भारत के गंगा के मैदान और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है।

मीठी क्रांति

मीठी क्रांति या स्वीट रिवोल्यूशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है। मधुमक्खी पालन एक कम निवेश और अत्यधिक कुशल उद्यम मॉडल है, जिसमें प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में अच्छी गुणवत्ता वाले शहद की मांग बढ़ी है क्योंकि इसे प्राकृतिक रूप से पौष्टिक उत्पाद माना जाता है। अन्य एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन संबंधी उत्पाद जैसे रॉयल जेली, मोम, पराग आदि का भी दवा निर्माण, भोजन, पेय पदार्थ, सौंदर्य और अन्य

विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी पालन को बढ़ाने से किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार पैदा होगा, खाद्य सुरक्षा और मधुमक्खी संरक्षण सुनिश्चित होगा और फसल उत्पादकता और परागण में वृद्धि होगी। मधुर क्रांति को बूस्टर शॉट प्रदान करने के लिए, सरकार ने एक लक्ष्य की तरह वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया।

सरकारी पहल

प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2017 को आमेरली (गुजरात) में एक किसान सभा का आह्वान किया, इसका उद्देश्य श्वेत और हरित क्रांति की तर्ज पर देश में 'मीठी क्रांति' लाने के लिए बड़े पैमाने पर शहद की खेती शुरू करना है। मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए और 'मीठी क्रांति' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन के समग्र विकास की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास और गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन के लिए एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र योजना (भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित) के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) का मुख्य उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और मधुमक्खी पालकों/किसानों की आय बढ़ाने के लिए शहद उत्पादन में वृद्धि करके मधुमक्खी पालन का समग्र विकास करना है।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) में निम्नलिखित उप-योजनाएं/तीन लघु मिशन हैं-

1. **मिनी मिशन-I:** इस मिशन के तहत, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को अपनाकर परागण के माध्यम से विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार पर जोर दिया जाएगा;
2. **मिनी मिशन-II:** यह मिशन इन गतिविधियों के लिए अपेक्षित ढांचागत सुविधाओं को विकसित करने पर जोर देने के साथ संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन इत्यादि सहित मधुमक्खी पालन/मधुमक्खी उत्पादों के कटाई के बाद प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा; और
3. **मिनी मिशन-III:** यह मिशन विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों/कृषि-जलवायु और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा।

देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए एनबीएचएम मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने से संबंधित अन्य सरकारी कार्यक्रम/योजना, जैसे एमआईडीएच

आरकेवीवाई, डब्ल्यूआईसी का शहद मिशन, एमएसएमई, एनएलआरएम/एसएलआरएम, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आयुष, आईसीएआर, आदि के साथ समन्वय पर काम करेगा। यह योजना के प्रभावी और सुचारू कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन/सलाह और प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा। एनबीएचएम के माध्यम से केंद्रित प्रयासों से 2021-2022 और उन्नत अनुमान के अनुसार शहद उत्पादन में लगभग 1,33,200 माउंट (मीट्रिक टन) की वृद्धि हुई है। भारत ने 2020-2021 के दौरान दुनिया को 74,413 मीट्रिक टन प्राकृतिक शहद का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 1,221 करोड़ रुपये है। परिणामस्वरूप, भारत दुनिया के शीर्ष पांच शहद उत्पादकों में से एक है। शहद के स्रोत को सुनिश्चित करने के लिए 8 अप्रैल 2021 को मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। यह एनबीएचएम के सर्वोत्तम कार्यान्वयन का परिणाम है। 10,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 16 लाख शहद मधुमक्खी कालोनियों वाली शहद समितियां/फार्म/कंपनियां राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्डों के साथ पंजीकृत हैं और मधु क्रांति पोर्टल से जुड़ी हुई हैं।

अब तक, 16 एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केन्द्र (आईबीडीसी) और 3 क्षेत्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं (आईएआरआई, नई दिल्ली, आईआईएचआर बंगलौर आईआईवीआर, वाराणसी में) और विभिन्न कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में 28 मिनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। आईसीएआर, नई दिल्ली, मधुमक्खियों और परागणकों पर अखिल भारतीय-समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (देश के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में फैले 26 केन्द्र) के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थान और स्थिति-विशिष्ट अनुसंधान को भी बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए गुणवत्ता मानकों को बनाये रखते हुए और अन्य मधुमक्खी उत्पादों, जैसे मधुमक्खी पराग, मधुमक्खी बैग, रॉयल जेली, प्रोपोलिस और मधुमक्खी जहर के उत्पादन को बढ़ावा देकर शहद के उत्पादन और परीक्षण को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक को अपनाया जा रहा है। इससे मधुमक्खी पालकों को अपनी आय बढ़ाने और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में शहद और मधुमक्खी उत्पादों की मांग बढ़ाने में सुविधा हुई है।

प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग:

मधुमक्खी पालन में प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप से इस क्षेत्र को बढ़ाने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। संगठित मधुमक्खी-पालन क्षेत्र का विकास, स्थानीय से लेकर उच्च-तकनीकी मधुमक्खी पालन गृहों तक, इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। IoT, AI, मोबाइल सेंसर और स्मार्टफोन ऐप मधुमक्खी पालकों को स्वस्थ मधुमक्खी परिवार बनाने और गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य उत्पाद निकालने में मदद कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन प्रथाओं के लिए परिचालन सहायता प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक मधुमक्खी पालकों के लिए एल्गोरिदम-आधारित पूर्वानुमानित मॉडल डिज़ाइन किए जा सकते हैं। लागत प्रभावी स्वदेशी तकनीक का विकास जो किसानों को खेतों पर स्वस्थ मधुमक्खियों को पालने और सेंसर या क्लाउड जानकारी के माध्यम से उनके छत्ते की उपयुक्तता का आकलन करने में सक्षम बनाता है, उसे भी इस क्षेत्र में पेश किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी मधुमक्खी संरक्षण को संरक्षित और समर्थन करेगी, बीमारियों को रोकेगी या मधुमक्खी कालोनियों के नुकसान को रोकेगी, और मधुमक्खी पालन उत्पादों की भरपूर गुणवत्ता और मात्रा प्रदान करेगी। व्यावसायिक मधुमक्खी पालन के लिए हाई-टेक मधुमक्खी पालन उच्च मात्रा में विपणन योग्य उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देंगी। अच्छी कृषि पद्धतियों से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला शहद और अन्य उत्पाद प्राप्त होंगे। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी व्यवहार आदि के क्षेत्र में अनुसंधान से स्वस्थ मधुमक्खी कालोनियों और मधुमक्खी पालन उत्पादों के व्यावसायिक पालन की गुंजाइश बढ़ेगी।

एक संगठित और तकनीक-संचालित मधुमक्खी-पालन क्षेत्र कौशल-निर्माण परियोजनाओं के साथ रोजगार के अवसर पैदा करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। यह सतत विकास लक्ष्य 1 (गरीबी रहित), 2 (भूख रहित), 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण), और 15 (जैव विविधता और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र) प्राप्त करने में भी मदद करेगा।

पिछले कुछ वर्षों में, पारंपरिक मधुमक्खी पालन व्यवसाय प्रौद्योगिकी के मामले में विकसित हुआ है। इसका एक उदाहरण शहद निकालने के लिए 'सुपर' चैंबर का उपयोग है। यदि हम सुपर चैम्बर का उपयोग करते हैं तो हम एक छत्ते से लगभग 70-80 किलोग्राम शहद ले सकते हैं। सुपर चैम्बर के बिना सामान्य छत्ते केवल 10-15 किलोग्राम ही देते हैं। रानी मधुमक्खी पालन की एक नई तकनीक भी है। ❑

भारतीय सिनेमा का सफ़र

भारतीय सिनेमा में मुख्यधारा की फ़िल्मों पर शुरूआत से ही भरत मुनि के 'नाट्यशास्त्र' की भारतीय नाट्य परंपरा का अत्यधिक प्रभाव रहा है। 40 के दशक की शुरूआत में अपने प्रसार के बल पर ही हिंदी सिनेमा ने 'भारतीय' सिनेमा के सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में स्थापित होने लगा। सत्यजीत रे की बांग्ला फ़िल्म पाथेर पंचाली भारतीय सिनेमा की आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक फ़िल्म है। 1950 के दशक में यकायक कई भारतीय फ़िल्मों का प्रवेश विदेशी फ़िल्मोत्सव में होने लगा। इनमें भारतीय फ़िल्मों को काफी सराहा गया और यह सिलसिला 1957 में चरम पर पहुंच गया। 1951 में गठित एस के पाटिल फ़िल्मों जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर फ़िल्म निर्माण में कलात्मक प्रतिभा विकसित करने के लिए 1960 में फ़िल्म वित्त निगम (बाद में फ़िल्म विकास निगम) का गठन किया गया। तब से साढ़े सात दशक बाद भारतीय सिनेमा जहां वह नई प्रोद्यौगिकी को अपनाकर फिर से खड़ा है और ओटीटी प्लेटफॉर्म की खोज करता है।

अमिताव नाग
स्वतंत्र फ़िल्म आलोचक, सिलहट पत्रिका के एक संस्थापक सदस्य एवं उसके वर्तमान संपादक।
ईमेल: amitava.nag@gmail.com

22 मार्च 1895 को मानव इतिहास में पहली बार फ़िल्म प्रदर्शित की गयी। पेरिस में ल्यूकमिरे बन्धुओं ऑगस्तेफ और लुइस ने एक फ़िल्म 'ला सोर्टी दि आई यूसीन ल्यूमिरे अ ल्योशन' को गिने-चुने दर्शकों के सामने निजी रूप से प्रदर्शित किया। दोनों भाइयों ने उसी वर्ष 28 दिसंबर को 10 लघु फ़िल्मों का व्यावसायिक प्रदर्शन किया। यह फ़िल्में दुनियाभर में घूमीं और छह महीने के भीतर 'सिनेमा' भारत पहुंच गया। फ़िल्मों को सबसे पहले तत्कालीन बम्बई में और फिर कलकत्ता और मद्रास में दिखाया गया। बड़े शहरों में भारतीय फ़िल्म उद्योग पल्लवित हुआ। 1913 में पहली फीचर फ़िल्म 'राजा हरिश्चंद्र' आई। अपेक्षानुरूप यह एक मूक फ़िल्म थी जिसे दादा साहब फाल्के ने बनाया था। उसके बाद से भारतीय सिनेमा ने तेज़ी से उड़ान भरी और 1931 में अर्देशिर ईरानी की फ़िल्म 'आलम आरा' से बोलती फ़िल्मों का शुभारंभ हुआ।

भारतीय सिनेमा में मुख्यधारा की फ़िल्मों पर शुरूआत से ही भरत मुनि के 'नाट्यशास्त्र' की भारतीय नाट्य परंपरा का अत्यधिक प्रभाव रहा है। संगीत और नृत्य की यह विधा पश्चिमी नाट्य रूपों से बिल्कुल भिन्न है। परिणामस्वरूप मुख्यधारा की भारतीय फ़िल्मों में शुरूआत से ही गूढ़ संगीत और नृत्यों की भरमार रही, जो कभी कभी बेहिसाब हो गयी। जैसे 69 गीतों से भरी 1932 की जेजे मदान की फ़िल्म 'इंद्रसभा' लगभग चार घंटे की रही। स्टूडियो व्यवस्था विकसित होने से भारतीय सिनेमा के पर्दे पर 'स्टार' का जन्म हुआ।

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब यूरोप के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी तब भारतीय बाज़ार में नकदी की बाढ़ आयी हुई थी। रातों-रात निर्माता की जमात खड़ी हो गयी, धड़ाधड़ फ़िल्में बनने लगीं और व्यावसायिक सफलता पाने के लिए मुख्यधारा की फ़िल्मों में जादूई फॉर्मूले आज़माये जाने लगे जिनमें गीत-संगीत नृत्यों की भरमार थी। जल्द ही लड़ाई के दृश्यों का तड़का भी लगने लगा। इस तरह 'मसाला' भारतीय व्यावसायिक सिनेमा जन्म लेने लगा।

40 के दशक की शुरूआत में अपने प्रसार के बल पर ही हिंदी सिनेमा ने 'भारतीय' सिनेमा के सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में स्थापित होने लगा। पन्ना शाह की पुस्तक 'द इंडियन फ़िल्म' (1950) के अनुसार 1945 में कुल 99 फ़िल्मों में से 73 (74 प्रतिशत) हिंदी, 12 तमिल, 9 बांग्ला, 4 तेलुगु और एक कन्नड़ फ़िल्में थी। पिछले तीन वर्षों में भी, 1942 में बनी कुल 165 में से हिंदी फ़िल्मों की संख्या 99 (60 प्रतिशत), 1943 में 149 में से 98 (66 प्रतिशत) और 1944 में 124 में से 88 (71 प्रतिशत) हिंदी फ़िल्में थी। 1947 में भारत स्वाधीन हुआ तो पंजाब और बंगाल का विभाजन हो गया। हालांकि पंजाब में कोई फलता-फूलता फ़िल्म उद्योग नहीं था लेकिन बंगाल में था। विभाजन का मतलब था कि बांग्ला फ़िल्म बाज़ार अपने मूल आकार के आधे से भी कम रह गया था। बिमल रॉय, सलिल चौधरी और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे तकनीशियन और निर्देशक, अधिक अवसरों और अपनी फ़िल्मों के व्यापक प्रसार की तलाश में बम्बई पहुंच गए।

स्वतंत्रता से पहले भारतीय फ़िल्म उद्योग का विकास अव्यवस्थित और बेतरतीब था। उन्नत तकनीक को समझने और सीखने के लिए, केवल कुछ विशिष्ट लोगों के पास ही विदेश में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा थी। उस समय लोकप्रिय अंग्रेज़ी दैनिक, 'द स्टेट्समैन' में, सत्यजीत रे ने 1948 में लिखा था, "आज भारतीय सिनेमा को अधिक चमक-दमक नहीं, बल्कि अधिक कल्पनाशीलता, अधिक ईमानदारी और

माध्यम की सीमाओं की अधिक समझबूझ की आवश्यकता है... हमारे सिनेमा को सबसे ज्यादा ज़रूरत ऐसी शैली और मुहावरे की, सिनेमा के ऐसे निराले अंदाज़ की है, जिस पर विशिष्ट भारतीयता की छाप हो।'' रे ने चिदानंद दासगुप्ता, आर पी गुप्ता, हरिसाधन दासगुप्ता जैसे अपने मित्रों के साथ मिलकर एक साल पहले कलकत्ता फ़िल्म सोसाइटी की स्थापना की थी। यह फीचर फ़िल्मों के लिए भारत की पहली फ़िल्म सोसायटी थी, हालांकि वृत्तचित्र फ़िल्म निर्माताओं ने भी 1942 में बम्बई में फ़िल्म सोसायटी की स्थापना की थी। अगले तीन दशकों में, कला रूप में सिनेमा पर चर्चा करने और दर्शकों को इसकी

क्षमता एवं रचनात्मक संभावनाओं से अवगत कराने के उद्देश्य से देशभर में फ़िल्म सोसायटियां स्थापित की गईं। दुर्भाग्यवश इनमें से अधिकांश सोसायटियों की चर्चाएं, भारतीय फ़िल्मों को नजरअंदाज कर विदेशी भाषा की फ़िल्मों तक सीमित हो जाने से उन्होंने अपनी प्रासंगिकता खो दी।

चेतन आनंद की 'नीचा नगर' और ख्वाजा अहमद अब्बास की 'धरती के लाल', दोनों ही 1946 में बनीं थीं। उनमें 'चमक दमक' के बजाय सत्यजीत रे की धारणा के अनुसार 'विशिष्ट और भारतीयता की छाप' छोड़ने की कोशिश दिखायी दी। संयोग से, 'नीचा नगर' कान फ़िल्मोत्सव में सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फ़िल्म बन गई। इसने 1946 में प्रथम कान फ़िल्म पुरस्कारों में कई अन्य फ़िल्मों के साथ सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार प्राप्त किया। 1948 में, उदय शंकर की शालीन लेकिन कुछ हद तक अव्यवस्थित फ़िल्म 'कल्पना' ने दर्शकों के मनोरंजन के लिए अंतहीन नाच-गाने के बजाय भारतीय सिनेमा में नृत्य-संगीत को एक विधा के रूप में स्थापित करने की संभावनाएं खोलीं। हालांकि, भारत के लिए सफलता का सबसे बड़ा क्षण 1955 में स्वयं सत्यजीत रे फ़िल्म निर्माता के रूप में लेकर आये।

सत्यजीत रे की बांग्ला फ़िल्म 'पाथेर पांचाली' आज तक भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी उपलब्धि है जो पहले भी और आज भी भारतीय फ़िल्मों को प्रोत्साहित करती है।

1950 के दशक में यकायक भारतीय फ़िल्मों को विदेशी फ़िल्मोत्सवों में प्रवेश मिलने लगा और काफी सराहा जाने लगा। 1957 में यह सिलसिला चरम पर पहुंच गया। सत्यजीत रे की दूसरी फ़िल्म, 'अपराजितो' (पाथेर पांचाली की अगली कड़ी) ने वेनिस फ़िल्मोत्सव में गोल्डन लायन और क्रिटिक्स पुरस्कार सहित कुल 11 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते। दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह पहली फ़िल्म थी। अमित मित्र और शम्भू

मित्र की बांग्ला फ़िल्म 'एक दिन रात्रे' ने उसी वर्ष कार्लोवी वैरी अंतरराष्ट्रीय फ़िल्मोत्सव में क्रिस्टल ग्लोब ग्रां प्री पुरस्कार जीता। 1957 में ही एक और बांग्ला फ़िल्म, तपन सिन्हा की 'काबुलीवाला' को संगीत के लिए ज्यूरी के सिल्वर बियर विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वी शांताराम की हिंदी फ़िल्म 'दो आंखें बारह हाथ' ने अगले वर्ष बर्लिन में ज्यूरी का सिल्वर बियर – विशिष्ट पुरस्कार जीता। निस्संदेह, 1950 के दशक के बांग्ला सिनेमा की संवेदनशीलता और कलात्मक चेतना के प्रति गहरी प्रतिबद्धता ने भारतीय सिनेमा में रचनात्मक उत्कृष्टता की तलाश को नये आयाम दिये।

इसके समानांतर, भारत सरकार ने भी कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रयास किये। 1951 में गठित एसके पाटिल फ़िल्म जांच समिति की सिफारिश के आधार पर, फ़िल्म निर्माण में कलात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए 1960 में फ़िल्म वित्त निगम (बाद में राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम) की स्थापना की गई थी। उसी वर्ष, पुणे में पुराने प्रभात स्टूडियो के परिसर में भारतीय फ़िल्म संस्थान की स्थापना की गई। चार साल बाद, भारतीय सिनेमा की विरासत को खोजकर संरक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार की स्थापना की गई।

इन सरकारी संस्थाओं का महत्व बहुत बड़ा है। फ़िल्म वित्त निगम द्वारा निर्मित दो फ़िल्मों मृणाल सेन की 'भुवन

शोम' और मणि कौल की 'उसकी रोटी' ने 1969 में भारतीय सिनेमा में नई लहर की शुरुआत की। संयोग से, कौल फ़िल्म संस्थाान से स्नातक थे। इस संस्थान ने जल्द ही भारत को मणि कौल, कुमार शाहनी, अडूर गोपालकृष्णन, गिरीश कासरवल्ली जैसे कई साहसी और भावबोधक फ़िल्म निर्माता दिए जिन्होंने भारतीय सिनेमा की सीमाओं को विस्तार दिया। जब फ़िल्म सोसायटियां, दर्शकों का एक विशेष वर्ग तैयार कर रही थीं, उसी दौर में फ़िल्म संस्थान, तकनीकी प्रशिक्षण का ऐसा मंच बन गया था जिसका अब तक अभाव था। फ़िल्म वित्त निगम ने न केवल फ़िल्म संस्थान के स्नातकों बल्कि सिनेमा में कुछ अलग सौंदर्यमय अभिव्यक्ति के लिए प्रतिबद्ध अन्य फ़िल्म निर्माताओं के अनूठे प्रयासों के लिए भी धन उपलब्ध कराया।

इन तीनों संस्थाओं ने किसी सोची-समझी सहमति के बिना ही, 1969 के बाद से बांग्ला और हिंदी सिनेमा की छिटपुट तरंगों को राष्ट्रीय सिनेमा की उद्दाम लहर का रूप दे दिया। अब तक व्यावसायिक फ़िल्मों के जाल में उलझी अनेक अन्य भाषाओं में भी सार्थक फ़िल्में बनने लगीं। मराठी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, असमिया और ओडिशा में नए किस्म के सिनेमा की धाक जमने लगी। उदाहरण के लिए, अरिबाम स्याम शर्मा की 'इमागी निंगथेम' (1981) ने पूर्वोत्तर भारत के सिनेमा को पहली बार विश्व मंच पर स्थापित किया।

70 के दशक के मध्य में, लोकप्रिय मुख्यधारा सिनेमा में 'एंग्री यंग मैन' का उदय हुआ, जो अपने और अपने जैसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए जूझ रहा था। 'अंडरवर्ल्ड' और 'गैंगस्टर्स' शब्दों ने भारतीय सिनेमा की शब्दावली में जगह बना ली। समय के साथ, 'मिस्टर इंडिया' (1987) के 'मोगैम्बो, खुश हुआ' से लेकर 'सत्या' (1998) में भीखू म्हात्रे के 'मुंबई का किंग कौन?' जैसे संवादों के साथ भारतीय मुख्यधारा सिनेमा ने कल्पना जगत से पराजगत तक का सफर तय कर लिया।

50 के दशक का सिनेमा बहुत हद तक गांवों से शहरों की ओर पलायन का प्रतीक था, उसी के साथ-साथ दशकों के इस सफर में भारतीय सिनेमा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ने लगा। सत्यजीत रे की 'महानगर' (1963) में अनिश्चितताओं से भरे जीवन से जूझती कामकाजी महिला से लेकर, बिमल रॉय की निम्न जाति की बेचारी 'सुजाता' (1959), 'उम्बर्था' (1982) में अधिक आत्मविश्वासी सावित्री या बाद में, 'क्वीन' (2014) में रानी के किरदार इसके उदाहरण हैं।

'द एलिफेंट व्हिस्पर्स' (2022) पहला भारतीय वृत्तचित्र है जिसने 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फ़िल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। दशकों से दुनिया भर में सबसे अधिक फ़िल्में बना रहे देश में, भौगोलिक क्षेत्र और भाषाओं के हिसाब से किसी रूझान को पहचान पाना कठिन काम है।

भारत में वृत्त चित्रों, लघु फ़िल्मों और एनीमेशन निर्माण में भी प्रगति का एक लंबा इतिहास रहा है।

पिछले पचहत्तर वर्षों में फ़िल्मों में राष्ट्रवाद का चित्रण भी बहुत होने लगा। आज़ादी से पहले और बाद में देशभक्ति की फ़िल्मों के अलावा, कुछ अन्य फ़िल्में, जैसे, 'मदर इंडिया' (1957) उभरते राष्ट्र में विकास के प्रयासों को चित्रित करना चाहती थीं। नई सहस्राब्दी में खेलों के माध्यम से देशभक्ति की भावना फिर जागृत हुई। 'लगान' (2001), 'चक दे! इंडिया' (2007) और प्रख्यात खिलाड़ियों के जीवन पर बनी फ़िल्मों ने समूचे देश के दर्शकों को आकृष्ट किया। ❑

नोट : चित्र लेखक की हालिया पुस्तक '75 साल 75 फ़िल्म्स' से ली गई है।

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी-विंग, केन्द्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एस्प्लेनेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455

हमारी पत्रिकाएं

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेज़ी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोष' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल		बाल भारती	
वर्ष	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ
1	₹ 230	₹ 434	₹ 160	₹ 364

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**" के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन" या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है-
संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- **फोन : 011-24367453** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद सदस्यता शुरू होने में कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं। कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1 वर्ष के प्लान के तहत ..... पत्रिका ..... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) .....

पता : .....

..... ज़िला ..... पिन .....

ईमेल ..... मोबाइल नं. .....

डीडी/पीओ/एमओ सं. ..... दिनांक ..... सदस्यता सं. .....

काला पानी

लेखक : हिमांशु जोशी

पृष्ठः 70, मूल्य : 105 रुपये

काला पानी की सज़ा को भयावह दु:स्वप्न के रूप में देखा जाता है। वहां कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं का विवरण रोंगटे खड़े कर देता है। अंग्रेज़ों ने भारत की मुख्य भूमि से सैंकड़ों मील दूर अंडमान द्वीप में सेलुलर जेल बनाई। अनेक स्वतन्त्रता सेनानियों को वहां घोर अमानवीय यातनाएं दी गईं। इस पुस्तक में इन यातनाओं का मार्मिक वर्णन किया गया है। पुस्तक के लेखक जाने-माने कथाकार हैं।

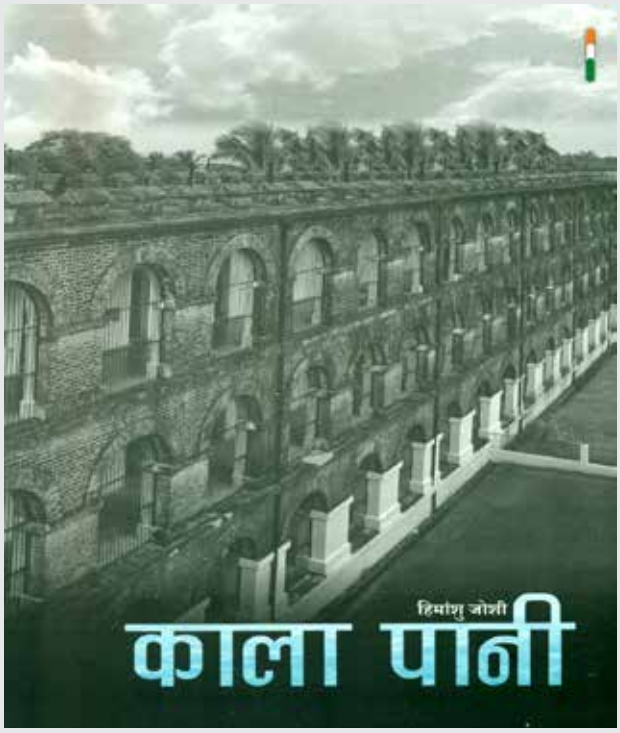

'काला पानी' का सांस्कृतिक भाव 'काल' से बना है जिसका अर्थ 'समय' या 'मृत्यु' होता है। 'काला पानी' शब्द का अर्थ मृत्यु के उस स्थान से है जहां से कोई भी वापस नहीं आता है। इस जेल में 15X8 फ़ीट की कुल 698 कोठरियां थीं। सभी कोठरियों में तीन मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाये गए थे ताकि क़ैदी एक-दूसरे से बात न कर सकें। ऐसे में क़ैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और ये अकेलापन उनके लिए मौत से भी भयानक होता था।

वर्षों तक सभी क़ैदी बाहर ही रहते थे घास-फूस की झोपड़ियों में, किन्तु बाद में एक पक्की जेल बनाई गई जो 1905 में पूरी हुई। इस जेल का नाम रखा गया- सेलुलर जेल। हर क़ैदी को प्रतिदिन नौ घंटे कठोर काम करना अनिवार्य था। हर क़ैदी को वर्ष में एक ही पत्र मिलता था और केवल एक ही पत्र इस अवधि में उसे भेजने की अनुमति थी। यदि अधिकारी चाहते तो इस सुविधा से भी उन्हें वंचित कर सकते थे। भोजन के नाम पर जो भी मिलता, उन्हें सब खाना पड़ता। कई बार भोजन करते समय सब्ज़ी में केंचुल के टुकड़े मिलते तो कभी-कभी सांप की बोटियां भी।

हमारे देश में समय-समय पर ऐसे वीर सपूत अवतरित हुए, जिनकी गौरव गाथाएं हमारे इतिहास का शृंगार बन गई हैं। आज़ादी की लड़ाई के परवाने कुछ ऐसे भी हैं, जिनके नाम शायद हमारे मानस पटल पर नहीं हैं। निष्काम भाव से त्याग करने वाले ऐसे कितने ही सेनानी हैं, जिन्होंने यातनाओं पर यातनाएं सहते हुए देश को परतन्त्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए नि:स्वार्थ भाव से अपने प्राणों तक की आहुति दे डाली। ऐसे नींव के सशक्त पत्थरों पर ही राष्ट्र का भव्य भवन खड़ा है। सचमुच ऐसे वीरों का त्याग और बलिदान ही सच्चा त्याग है, जिनकी अमर कहानी 'काला पानी' की दीवारें आज भी कह रही हैं। उन वीरों को, अपने परिवार से बिछुड़कर, अंग्रेज़ी शासन में कैसी-कैसी घोर यातनाएं सहन करनी पड़ीं, उन्हें पढ़-पढ़कर रोम-रोम सिहर उठता है। जो गाथाएं एवं जो महान चरित्र हमारे प्रेरणा-स्रोत हैं, उन्हें आज सारा देश नमन करता है। सुपरिचित लेखक हिमांशु जोशी ने 'काला पानी' शीर्षक से अपनी इस पुस्तक में भारत माता के ऐसे वीर सपूतों- जिसमें वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, शचीन्द्रनाथ सान्याल, भाई परमानन्द, उपेन्द्रनाथ बनर्जी, ज्योतिषचन्द्र घोष, उल्हासकर दत्त, बाबा भानसिंह, वारीन्द्र कुमार घोष, पृथ्वी सिंह आज़ाद, नानी गोपाल, गोविन्द चरण जैसे गुमनाम क्रान्तिकारियों की अदम्य, साहसिक और देशभक्तिपूर्ण गाथाओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है।

सेलुलर जेल में आने वालों में अंतिम व्यक्ति थे - नेताजी सुभाष चन्द्र बोस। वह बंदियों के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वाधीन नागरिक, एक मुक्त योद्धा और एक विजेता सेनापति के रूप में इस द्वीप में आए। उन्होंने काला पानी के द्वीपों में तिरंगा फहराकर सेलुलर जेल के द्वार हमेशा के लिए खोल दिए।

वास्तव में ये स्वातंत्र्य वीर काले द्वीप में धधकते अंगारे थे, जिसकी ऐसी गौरव गाथाएं हमारे इतिहास के पृष्ठों में सदा दैदीप्यमान रहेंगी। ❑

रजि.सं. डी.एल.(एस)-05/3231/2021-23
Reg. No. DL(S)-05/3231/2021-23 at RMS, Delhi
28 जुलाई, 2023 को प्रकाशित
• 2-3 अगस्त, 2023 को डाक द्वारा जारी

R.N.I. (आर.एन.आई.) - 951/57
Licenced under U(DN)-55/2021-23
Magazine Post Registration No. : DL(DS)-43/MP/2022-23-24

संस्कृति IAS

जहाँ एक नहीं, हर शिक्षक है श्रेष्ठ

देश में हिंदी माध्यम से
सामान्य अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ टीम

श्री अखिल मूर्ति
इतिहास, कला एवं संस्कृति

श्री अमित कुमार सिंह
(IGNITED MINDS)
एथिक्स

श्री ए.के. अरुण
भारतीय अर्थव्यवस्था

श्री सीबीपी श्रीवास्तव
(DISCOVERY IAS)
राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय, गवर्नेन्स, आंतरिक सुरक्षा

श्री कुमार गौरव
भूगोल, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन

श्री राजेश मिश्रा
भारतीय राजव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध

श्री रीतेश आर जायसवाल
सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स + मेन्स)

हाइब्रिड कोर्स
ऑफलाइन + ऑनलाइन

हाइब्रिड कोर्स की विशेषताएँ

- ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास करने की सुविधा
- बैच शुरू होने से 3 वर्षों तक ऑनलाइन मोड में असीमित बार क्लास देखने की सुविधा
- नियमित क्लास टेस्ट : प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा
- संस्कृति IAS की मासिक करेंट अफेयर्स मैगज़ीन एवं योजना पत्रिका उपलब्ध कराई जाएगी
- प्रत्येक विषय/खंड के अपडेटेड प्रिंटेड क्लासनोट्स + NCERT की पुस्तकें

वैकल्पिक विषय

इतिहास — द्वारा श्री अखिल मूर्ति

दर्शनशास्त्र — द्वारा श्री अमित कुमार सिंह (IGNITED MINDS)

भूगोल — द्वारा श्री कुमार गौरव

राजनीति विज्ञान — द्वारा श्री राजेश मिश्रा

सीसैट

ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कोर्स

लगभग 120+ घंटों की कक्षाएँ

प्रत्येक विषय / खंड के प्रिंटेड क्लासनोट्स

नियमित क्लास रिवीज़न

UPSC/UPPCS

टेस्ट सीरीज़
ऑफलाइन एवं ऑनलाइन

Pre + Mains

टेस्ट सेंटर : दिल्ली एवं प्रयागराज

उपलब्ध लाइव कोर्स

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स+मेन्स)

सीसैट

वैकल्पिक विषय — भूगोल द्वारा– श्री कुमार गौरव

इतिहास द्वारा– श्री अखिल मूर्ति

NCERT ONLINE COURSE

लगभग 450+ घंटों की कक्षाएँ

कोर्स की वैधता: कोर्स शुरू होने से 1 वर्ष तक — असीमित बार क्लास देखने की सुविधा

TARGET Prelims 2024

सामान्य अध्ययन + सीसैट

ऑनलाइन कोर्स

लगभग 500+ घंटों की कक्षाएँ

प्रत्येक विषय / खंड के प्रिंटेड क्लासनोट्स एवं नियमित क्लास टेस्ट

कोर्स की वैधता: कोर्स शुरू होने से 1 वर्ष तक — असीमित बार क्लास देखने की सुविधा

हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
प्रयागराज केंद्र: 7/3/AA/1, ताशकंद मार्ग, पत्रिका चौराहा, प्रयागराज, उ.प्र.

9555-124-124
sanskritiias.com

YH-2397/2023

प्रकाशक व मुद्रक : अनुपमा भटनागर, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए जे.के. ऑफसेट ग्राफ़िक्स प्रा.लि., बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक : डॉ ममता रानी